

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 1994

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण



विषय सूची

बुधवार, 9 मार्च, 1994

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8) 1
नियम 45 के अधीन सदन की भेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8) 26
राज्यपाल महोदय का सन्देश	(8) 24
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(8) 24
ध्यानाकर्षण सूचनाएं	(8) 28
विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरादम्भ)	(8) 29
स्वगत प्रस्ताव	(8) 32
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	
सब्जियों तथा फलदार पौधों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किये जा रहे - सीवरेज के पानी सम्बन्धी—	(8) 33

मूल्य : 155 00

(ii)

वक्तव्य—

जन-स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना सम्बन्धी	(8)33
वर्ष 1994-95 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)36
बैठक का समय बढ़ाना	(8)78
वर्ष 1994-95 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)78
बैठक का समय बढ़ाना	(8)82
वर्ष 1994-95 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)82
बैठक का समय बढ़ाना	(8)83
वर्ष 1994-95 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)84
अनैवश्वर-ए	(8)85

ERRATA

To

Haryana Vidhan Sabha Debates, Vol. 1, No. 8, dated the
9th March, 1994.

<u>Read</u>	<u>For</u>	<u>Page</u>	<u>Line</u>
किलोमीटरजं	किसोमीटरजं	3	16
तारांकित	तारांकिस	7	Top heading
मैप	मप	7	4
में	मैं	8	3
के बाद	बाद	8	33
सीरयसली	भीरयसली	16	23
सभापतियों	सभापतिरों	38	6
74.8	748	42	17
मैम्बरजं	मम्बरजं	52	21
1991	1981	61	2
State	Slate	85	4
(ख)	(ख) f	85	12
गए	गन	110	3
स्वीपर	स्वीपर	110	10

Vertical line of text on the left margin, possibly a page number or header.

Main body of text, appearing to be a list or table with multiple columns and rows. The text is extremely faint and illegible.

Vertical line of text on the right margin, possibly a page number or header.

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 9 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन,
सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष
(चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष :— मंत्र सहाय, अब सवाल होंगे।

Widening of Road from Hisar to Narnaul

*658. Shri Ram Bhajan Aggarwal : Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the road from Hisar to Narnaul via Bhiwani, Charkhi Dadri; and

(b) if so, the time by which it is likely to be widened ?

लोक निर्माण मन्त्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) :

(क) अध्यक्ष महोदय, सड़क पहले से ही 18 फुट चौड़ी है और कुछ सैवधान में 22 फुट चौड़ी भी है। हांसी-भिवानी-दादरी-महेन्द्रगढ़ से नारनौल तक सड़क को 24 फुट चौड़ा करना सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस स्टेज पर इसे पूरा करने का समय नहीं बताया जा सकता।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक गुजरता है और जो ट्रैफिक बम्बई और राजस्थान बगैरह को जाता है, वह इसी सड़क से गुजरता है। इस बात को देखते हुए क्या इस सड़क को दीर्घ प्रयत्नी देकर चौड़ा किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार इस सड़क को जल्दी चौड़ा नहीं कर पा रही है तो क्या मंत्रालय गवर्नमेंट से प्रयास करके इसकी नैशनल हाईवे बनाने की कोशिश करेगी?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क को वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और इसको 24 फुट चौड़ा करना विचाराधीन है। अगले महीने वर्ल्ड बैंक के साथ डिपार्टमेंट की मीटिंग फिक्स की गई है। अगले साल इस सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जहां आबादी वाले एरिया आते हैं, वहां इसकी वाइडनिंग करके फोर लेनो करने का प्रयत्न है। हमें प्रार्थना है कि आने वाले साल में कार्य शुरू कर दिया जाएगा और इसकी चौड़ा कर दिया जाएगा।

श्री राम रत्न : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पलवल से अलीगढ़ की जो रोड जा रही है, वह बारह फुट चौड़ी है और उस पर ट्रैफिक बहुत चलता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसकी चौड़ा करने की कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है और अगर है तो कब तक ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही सदन को बताया है कि जितने हमारे स्टेट हाईवेज हैं, उनको 12 फुट से अठारह फुट किया जाएगा और अठारह फुट से बाईस फुट किया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और ज्यों-ज्यों फण्डज अवैलेबल होते जाएंगे, उसके हिसाब से यह कार्य किया जाएगा।

चौधरी बरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, नारनौल भिजानी की जो सड़क है, वह नेशनल हाईवे नम्बर—1 है और सारा ट्रैफिक जो लुधियाना अमृतसर को जाता है, वह डाईवर्ट हो कर इस सड़क से चलने लग गया है। स्पीकर साहब, वाइडनिंग तो अलग चीज है लेकिन चूंकि इस सड़क पर कई गुणा ट्रैफिक बढ़ गया है, इसलिए क्या मंत्री जी बताएंगे कि ट्रैफिक बढ़ने के कारण इस सड़क की स्ट्रैथनिंग तथा वाइडनिंग करने के लिए कोई प्रोपोजल सरकार के विचाराधीन है ? अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि सदन में जो पहली हमारी बैठक थी, उसमें गवर्नमेंट पालिसी के बारे में मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जो सड़क बारह फुट चौड़ी है, उसको अठारह फुट किया जाएगा और जो सड़क अठारह फुट है, उसकी बाईस फुट चौड़ा किया जाएगा। स्टेट हाईवेज की सड़कों पर, जो सड़क एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, और एक सब-डिविजन से दूसरे सब-डिविजन को जाती है, उन सड़कों को प्रायोरिटी देकर काम शुरू किया जाएगा और एक फाइव ईयर प्लान में यह काम कम्प्लीट करने की बात कही गई थी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रोजेक्ट पर क्या कहीं काम शुरू किया गया है; और अगर किया है तो कितने परसेंट काम उन सड़कों पर कम्प्लीट हुआ है ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, बरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है और इस कार्यक्रम के लिए हमने पांच स्टेट हाईवेज लिए हैं और वर्ल्ड बैंक की सहायता से उनकी स्ट्रैथनिंग और वाइडनिंग की जाएगी। वे पांच स्टेट हाईवेज हैं—(1) अम्बाला, कैथल, करनाल और मेहवा; (2) कोटपुतली, नारनौल,

भिवानी और हासी; (3) अम्बाला, कैथल, नरवाना, हिसार और रामगढ़; (4) पानीपत, जीन्द, बरवाला, आदमपुर, भादरा व हासी; और (5) पंचकूला, साहा, अम्बाला, जगाधरी और सहारनपुर नगौरह-वगौरह।

इसके साथ-साथ दूसरा जो सवाल मेरे माननीय सदस्य ने किया कि जो हमारी सड़कें केवल 12 फुट चौड़ी हैं और मेन सड़कें हैं, उनको और चौड़ा करने का हमारा क्या कार्यक्रम है। मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सालों-साल हम सड़कों का काम फण्डज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से करते हैं। जो सड़कें हमने चौड़ी की हैं, वे 1991-92 में 204 किलोमीटर और 1993-94 में 222 किलोमीटर लम्बी हैं। आगे भी फण्डज के हिसाब से, हम सड़कों को चौड़ा करने की प्रायोरिटी देंगे।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में मेन रोडज को चौड़ा किया जाना है। तीन साल तो बीत चुके हैं, चौथा साल शुरू है। क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि कितने परसेन्ट काम अब तक हो चुका है? बाकी का जो काम रहता है, वह डेढ़ साल के अन्दर सरकार कैसे पूरा कर लेगी?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, मैंने किलोमीटर भी बताया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो स्टेट हाईवेज 12 फुट हैं, वे हैं केवल 570 किलोमीटर और जो डिस्ट्रिक्ट रोडज हैं, वे 850 किलोमीटर हैं जो 12 फुट हैं। हमारे कार्यक्रम के अनुसार जैसाकि मैंने पहले बताया है कि फण्डज की अवेलेबिलिटी के मुताबिक प्रायोरिटीज फिक्स की जाएंगी और जो मेन सड़कें हैं, वे बल्ले बैंक से, जिसके लिए बातचीत चल रही है और वह तय भी है कि आने वाले समय में हमें बल्ले बैंक से पूरी मदद मिलेगी। सहायता मिलने पर सड़कों की स्ट्रेथनिंग व वाइडनिंग करने का काम जल्दी ही शुरू कर लेंगे।

प्रो० उत्तर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, दादरी से महेन्द्रगढ़ को जो सड़क जाती है, उसकी वाइडनिंग तो दूर रही, उसकी हालत इतनी खराब है कि वहाँ पर कोई गाड़ी आ-जा नहीं सकती। ढाई-तीन सालों से जब से यह सरकार आई है, दादरी से बघवाना को जाने वाली सड़क पर इस सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। राज बंसी सिंह जी बैठे हैं, वे आमतौर पर इसी रोड से आते जाते हैं, उन्हें भी इस बात की जानकारी होगी कि यह सड़क कितनी खराब है। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूँगा और यह जानना भी चाहूँगा कि दादरी से महेन्द्रगढ़ जाने वाली जो बड़ी टूटी हुई सड़क है, उसकी वाइडनिंग तो ये करेंगे ही, क्या उस सड़क को चौड़ा करने से पहले उसकी मुरम्मत भी करने का प्रयास करेंगे?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी: अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं हर महीने इसी सड़क से नारनाल विवेक सिज कमेटी की सीटिंग अटैन्ड करने जाता हूँ। केवल मात्र बीच में चार-पाँच किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा बेविंग है जो खराब

[चौधरी आनन्द सिंह डांगी]

है, बाकी सड़क की कहीं भी कोई बुरी हालत नहीं है जहाँ हमारा ट्रैफिक अच्छी तरह से न चल रहा हो। पाँच छः किलोमीटर पर मेटल जाल दिया है और हम जल्दी ही इसे ठीक कर देंगे।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो सड़कें 12-12 फुट चौड़ी हैं, उनको 24 फुट तक चौड़ी करेंगे। छह वर्ष से यह बात चल रही है। जैसे अभी उन्होंने उपमोक्षिता को देखते हुए दिल्ली और अम्बाला की जी० टी० रोड को फोर लेनिंग करने के अतिरिक्त यमुनानगर और दिल्ली के बीच अन्ध से रास्ता बनाने की बात भी कही है। जैसा अभी मेरे भाई चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने अपने सवाल में कहा कि कोटपुतली से लेकर लुधियाना पंजाब तक सेल्ज टैक्स के काफी बैरियर हैं और तीन हजार के लगभग हेवी व्हीकलज कोटपुतली से फास करते हैं। कोई हिसार तक जाता है, कोई रोहतक तक जाता है। हेवी व्हीकलज का रेश इस सड़क पर देखते हुए, क्या मन्त्री महोदय प्राथमिकता के आधार पर कोई आल्टरनेटिव ढूँढेंगे या फिर उसको फोर लेन करने का सरकार जल्दी ही कोई प्रस्ताव करेगी ताकि हेवी ट्रैफिक को कम किया जा सके ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि पाँच रोडज में से ही हैं, वे हैं कोटपुतली, नारना, भिवानी और हांसी इत्यादि जो कि पंजाब के एरिया के साथ मिलती हैं और इसके लिए इसी महीने में बल्ड बैंक से बातचीत हो रही है। मैं इतना ही बहना चाहता हूँ कि जो-जो दिक्कतें मेरे माननीय सदस्य ने बताई हैं, वह सब हम दूर करेंगे। फण्डज की अवैलेबिलिटी को देखते हुए जाने वाले समय में सभी कार्यों के लिए प्रायोरिटी फिक्स करेंगे।

श्री हरि सिंह नलथा : अध्यक्ष जी, अभी मन्त्री जी ने बताया कि उनके पास फण्डज की कमी है। यह बात किसी हद तक सही है और यह भी सही है कि हरियाणा के ऊपर सारी दुनिया के इंटरस्ट्रियलिस्ट्स की नजर लगी हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री जी को दाद भी देता हूँ। उन्होंने हरियाणा प्रान्त को इंटरस्ट्रियलाइज करने का क्लेश प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो इंस्ट्रीज लगाने के लिए खास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सड़कों की जरूरत होती है। जब तक सड़कें चौड़ी नहीं करेंगे, तब तक यह बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि पैसे का जहाँ तक टाल्लुक है, क्या उसके लिए वे राजस्थान की फालो करेंगे ? राजस्थान में मार्किटिंग बोर्ड ने कई अरब और खरब रुपए वर्ल्ड बैंक से इस काम के लिए ले लिए हैं। यह पैसा वर्ल्ड बैंक को 30 सालों में वापिस करना होता है। उन्होंने सारे राजस्थान में सड़कें बनाने का क्लेश प्रोग्राम शुरू कर दिया है। क्या इस किस्म का प्रोग्राम सरकार के विचाराधीन है ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्टेट हाई-वे बनाने का क्या फाइटेरिया है और राज्य में कुल कितने स्टेट हाई-वेज हैं ? जितने हमारे तहसील हैडक्वार्टर हैं, कम से कम उनको तो

स्टेट हाईवे से जोड़ना चाहिए। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इस काम के लिए क्या 10 अरब रुपया वर्ल्ड बैंक से हमारे मार्किटिंग बोर्ड के जरिये लेने का प्रयास करेंगे ?

श्री धरि श्रीमानन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, सड़कों की स्ट्रैनिंग के लिए ग्रॉर उनके रख रखाव के लिए हमारी हर साल कम से कम 70 करोड़ रुपए की डिमांड है लेकिन उसके अग्रेस्ट हमें 18-20 करोड़ रुपए मिलते हैं। इस पैसे से इतनी बढ़िया सड़कें बना कर देना नामुमकिन बात है। लेकिन उनको ठीक ढंग से रखना सरकार का दायित्व है और वह हम करेंगे। दूसरा इन्होंने पूछा कि स्टेट में कितने स्टेट हाईवेज हैं, वे 36 हैं।

श्री सुरज मल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दिल्ली और बहादुरगढ़ की जो बॉर्डर की रोडज हैं, वे तकरीबन चार पांच हैं। एक तो सोहटी से कुतबगढ़, दूसरी कानौदा से पंजाब खोड और वामराजी से निजामपुर बगरह बगरह। पंजाब खोड वाली सड़क की हालत बहुत खराब है। क्या सरकार का उस साईड की सड़कों की तरफ भी ध्यान देने का विचार है ताकि उस तरफ भी अच्छी सड़कें दिखाई दें ?

श्री धरि श्रीमानन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरज मल ने कल भी यह सवाल किया था और आज भी वही सवाल किया है। मैंने कल इनको यह जवाब दिया था कि हम उन सड़कों की देख लेंगे, अगर उन गांवों के लोगों की कोई दिक्कत है तो प्रायर्टी बेस पर उन सड़कों को ठीक किया जाएगा ताकि उन गांवों के किसानों को दिल्ली में अपना सामान ले जाने लाने में कोई दिक्कत न हो।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश के अन्दर जितनी भी स्टेट रोडज हैं, उन पर छोटे छोटे और बड़े-बड़े गांव बसे हुए हैं। जहाँ तक मुझे पता चला है, राज्य सरकार की यह पालिसी है कि उन रोडज पर स्पीड-ब्रेकर न बनाए जाएं। उन रोडज पर स्पीड ब्रेकर न बनने के कारण आए दिन गांवों में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और जवान, बूढ़े लोगों की मौतें होती हैं। इन दुर्घटनाओं को देखते हुए क्या मंत्री जी स्टेट रोडज पर जहाँ जहाँ पर गांव बसे हुए हैं, स्पीड ब्रेकर बनाने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री धरि श्रीमानन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, जैसे तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह हिदायत है कि रोडज पर स्पीड ब्रेकर न बनाए जाएं लेकिन फिर भी हमने जो ज्यादा आवादी वाले गांव हैं और जिन के बीच में से सड़क गुजरती है, उन पर अपनी मर्जी से स्पीड ब्रेकर बनाए हैं। अगर कहीं पर स्पीड ब्रेकर बनाने की ज्यादा जरूरत है तो माननीय सदस्य दलाल साहब बता दें, हम स्पीड ब्रेकर बनवा देंगे।

चौधरी सुरज भान काजल : स्पीकर साहब, रोड्ज की वाइडनिंग करने की बात है। जो सड़कें गांवों की आवादी तक गई हैं, उन को गांव और लाल डोरे के बीच में कच्चा छोड़ दिया गया है। उन सड़कों का फासला केवल एक या डेढ़ फुटिंग का आज भी कच्चा पड़ा है। ऐसे बहुत से गांव हैं। वे सड़कें ईंटों से बनी हुई हैं और ईंटें टूट जाने के कारण सड़क का बहुत बुरा हाल है उनका कच्चे रास्ते से भी बुरा हाल है। उनका इतना बुरा हाल है कि उनके ऊपर से कोई व्हीकल गांव के अन्दर दाखिल नहीं हो सकती। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन-जिन गांवों में ऐसी सड़कें हैं, क्या उनको पक्का करने का सरकार का विचार है ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : स्पीकर साहब, पी० डब्ल्यू० डी० का काम केवल गांव की फिरती तक सड़क बनाने का होता है, स्कूल या किसी धार्मिक स्थान तक जो सड़क बनाई जाती है, वह काम पंचायत डिपार्टमेंट का है। पी० डब्ल्यू० डी० गांव की फिरती तक सड़क बनाएगा उससे आगे पंचायत डिपार्टमेंट का काम है।

श्री मनी राम केहरवाला : स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश में 850 सड़कें ऐसी हैं, जो 12 फुट चौड़ी हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सिरसा से ऐलनाबाद सड़क 12 फुट चौड़ी है, वह स्टेट हाईवे है, उसको अब तक 22 फुट चौड़ी बनवा देंगे ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले बताया है कि 1992-93 और 1993-94 में लगभग 200 किलोमीटर स्टेट हाईवे की वाइडनिंग कर दी है। जिन सड़कों पर व्हीकल का लोड ज्यादा है, उनको अगले साल चौड़ा करने पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या स्टेट में 10 फुट चौड़ी सड़कें भी है ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, एप्रोच रोड्ज हो सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : मेरे इलाके में अराध से बाधा रसीना किरमच सड़क कुसकेल जाती है, वह सड़क रसीना से सातड़ तक 10 फुट चौड़ी है, उस को 10 से 12 फुट चौड़ा बनाने के लिए उस पर पत्थर डाल दिए थे। जो पत्थर डाले गए थे, उससे अगली सरकार ने 1987 में, वह पत्थर उठा लिए। क्या उस सड़क को अब सरकार 10 को बजाय 12 फुट बनाएगी ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें 10 फुट चौड़ी है, उनको 12 फुट चौड़ा करने का सरकार का प्रोग्राम है।

श्री अध्यक्ष : वह सड़क तो 1967 से बनी हुई है ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जो सड़कें 10 फुट चौड़ी हैं, उनको 12 फुट चौड़ा करने का प्रावधान है।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : स्पीकर साहब, पानीपत से बाया रोहतक, झज्जर, रिवाड़ी तक जो सड़क जाती है, उस पर हरियाणा प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बसिज बट्टक बगैरह चलते हैं, बहुत ज्यादा ब्हीकलज चलते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या उस सड़क को सरकार नेशनल हाईवे के रूप पर लाएगी? क्या सरकार उस सड़क के बारे में सैन्ट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके उसको नेशनल हाईवे बनाने पर विचार करेगी?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

Regularisation of the Services of Village Chowkidars

*666. **Prof. Chattar Singh Chauhan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the services of the Village Chowkidars and treat them at par with the Group 'D' employees of the State?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : जी नहीं। राज्य सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई मामला नहीं है। सरकार ने 1-9-93 से चौकीदारों का वेतन 150/- रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 300/- रुपये प्रति मास कर दिया है तथा उन्हें 250/- रुपये प्रति वर्ष बढ़ी भत्ता भी प्रदान किया गया है।

प्रो० छतर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, वह तो मुख्य मंत्री महोदय ने इन चौकीदारों पर इनायत कर दी कि उनको 300/- रुपये महीने के दिए जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस मंहगाई के युग में इन 300/- रुपये से वह अपना गुजारा कर सकता है? जहाँ तक चौकीदार का संबंध है, गांव में कोई तहसीलदार जाए, डी० सी० जाये या और कोई काम हो, उसको 24 घण्टे ड्यूटी देनी होती है। आज्ञादी से लेकर आज तक चौकीदार को सुविधा देने के बारे में किसी भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार चौकीदार को ब्यास फोर का एम्पलाई घोषित करने पर विचार करेगी ताकि वह अपना गुजारा अच्छी प्रकार से कर सके, जबकि सरकार दूसरे कर्मचारियों को 240 दिन के बाद रंगुलर कर देती है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौकीदार को सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जा सकता, वह पब्लिक की सेवा करता है और अपना भी काम करता है। यह ठीक है कि जन्म मरण का हिसाब-किताब रखने के लिए उसे सी० एम० सी० ऑफिस में जाना होता है या गांव में अगर कोई महामारी फैल जाए तो उसके

[चौधरी भजन लाल]

बाने में सरकार का क्या खिलाता होता है। हाऊस को मैं बताना चाहूंगा कि मेरे सिवाए आज तक, जब से हरियाणा बना है, यानि 1966 से अब तक किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मैं 1979 में मुख्य मंत्री बना तो उस समय चौकीदार को 40/- रुपये महीना मिलता था, मैंने उस समय बढ़ा कर 100/- रुपये किए और फिर 1985 में ही मैंने 100/- रुपये से बढ़ाकर इनको 150 रुपये महीने दिए और अब मैंने ही 1-9-93 से 300/- रुपये किए हैं। बीच में जितनी भी सरकारें आई, किसी ने इनकी तरफ देखा तक नहीं।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कुल कितने चौकीदार हैं ? दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन 300/- रुपये के अलावा भी उनको बोनस और वर्दी आदि की कोई सुविधा दी जाती है ?

श्री चौधरी भजन लाल : इनको 300/- रुपये महीने पे मिलती है और दूसरे हम वर्दी भी देते हैं। स्टेट में कुल 6735 गांव है और कुल 6701 चौकीदार हैं।

श्री सतबीर सिंह काबिधान : मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार चौकीदारों को मिनिमम वेजिज देने पर विचार करेगी ? इसके अतिरिक्त चौकीदार को जन्म मरण के सिलसिले में या दूसरे कारणों के लिए शहर जाना होता है तो क्या उनको टी०ए० वगैरा या एक्चुअल किराया देने पर भी सरकार विचार करेगी ?

श्री चौधरी भजन लाल : जब चौकीदार सरकार के काम या जीवन-मरण के सिलसिले में शहर जाता है तो उसको किराया मिलता है। जहाँ तक दूसरी बात है कि उन्हें मिनिमम वेजिज दिया जाये, उस पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, क्योंकि मिनिमम वेजिज उन्हीं को दिया जाता है जो कम से कम 10-12 घण्टे रोजाना ड्यूटी देते हैं। इनका लगातार काम नहीं है। इनका काम तो ऐसा है कि किसी दिन ज्यादा काम भी हो सकता है और कई दफा 5-5 दिन तक कोई भी काम नहीं होता, इसलिए इनको मिनिमम वेजिज नहीं दिया जा सकता।

श्री अमर सिंह : स्वीकर साहब, यह ठीक है कि चौकीदार को पहले 40 रुपये प्रतिमाह मिलते थे और अब 300 रुपये मिलते हैं, लेकिन चौकीदार को जो पैसे दिये जाते हैं, वे पहले ही रीवेन्यू माल के साथ उगाह लिए जाते थे और फिर भालिये में से चौकीदार को रुपया मिलता था। स्वीकर साहब, जो 300 रुपये चौकीदार को अब दिये जाते हैं, वह कैसे दिये जाते हैं ? मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि 1-9-93 से जो 300 रुपये चौकीदार को मिलते हैं, क्या ये खजाने से मिलते हैं, बजटोलिडेडिड फण्ड से मिलते हैं अथवा आबिधाना कलैक्शन बाद नम्बरदार उसको देता है ?

चौधरी मजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौकीदार को पैसे सरकारी खजाने से नहीं मिलते। पहले चौकीदार मालिया में उगाहा जाता था लेकिन अब मालिया तो खत्म हो गया है, इसलिये अब जो आविधाना इकट्ठा करते हैं, उसके साथ उगाह लिया जाता है और जहाँ पर नहीं नहीं हैं, वहाँ पर बाकायदा हर घर से, रहने वाले लोगों से चौकीदार लिया जाता है। गाँव में रहने वाले जो गरीब प्रगहीन आदमी हैं, उनका चौकीदार माफ होता है। यह पैसा नम्बरदार वसूल करता है और कई बार नम्बरदार चौकीदार को लिस्ट बना कर दे देता है और वह पैसा चौकीदार हर घर से खुद वसूल कर लेता है।

Sales Tax on Medicines

*679. **Shri Jai Parkash :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the Sales Tax on Medicines in the State, so as to bring it at par with the other States; and
- (b) if so, the time by which the sales tax as referred to in part (a) above is likely to be revised?

आवकारी तथा कराधान मन्त्री (बहन करतार देवी) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने दवाईयों पर टैक्स का ध्यौरा दूसरे राज्यों से लिया है कि उन में कितना-कितना टैक्स है? इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह है कि अगर दूसरे राज्यों में दवाईयों पर टैक्स कम है तो गरीबों को सस्ती दवाईयाँ उपलब्ध करवाने के लिए क्या सरकार ऐसे राज्यों से दवाईयाँ खरीदने वाले विकार करेगी जिनमें दवाईयों पर टैक्स कम है?

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने माननीय साथी की हरियाणा प्रान्त के आस-पास के राज्यों में जो दवाईयों पर देता है, उसके बारे में बताती हूँ। पंजाब में 8 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 8 प्रतिशत, राजस्थान में 6 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 6 प्रतिशत तथा दिल्ली में 5 प्रतिशत दवाईयों पर टैक्स है। (विद्य) हरियाणा में दवाईयों पर 8 प्रतिशत टैक्स है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने राजस्थान में 6 प्रतिशत टैक्स बताया है परन्तु मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहां पर 5 प्रतिशत टैक्स है, हिमाचल प्रदेश में 7 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 6 प्रतिशत और पंजाब में 7 प्रतिशत तथा यहां यू० टी० में 4 प्रतिशत सीटल सेल्स टैक्स लगाया जाता है तथा दिल्ली में 5 प्रतिशत टैक्स है। अगर हम दिल्ली से 100 रुपये की दवाई परवेज करके करनाल में लाएं तो करनाल के सेल डिप्टी पर वह दवाई 113 रुपये की मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछ जानना चाहूंगा कि यह जो डिफरेंस है, क्या उसको दूर करने के लिए मन्त्री जी कोई पग उठाएंगी ?

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट ने मुझे जी आंकड़े उपलब्ध करवाए हैं, उनके मुताबिक पंजाब में 8 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 8 प्रतिशत टैक्स है और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान का मैंने पहले ही 6 प्रतिशत बताया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक गरीबों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध करवाने का सवाल है, वह दूसरी बात है और उसे दूसरे एंगल से देखा जाना चाहिये। जो हरियाणा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब-सेन्टर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं उनमें दवाईयां फ्री दी जाती हैं। सरकारी कर्मचारियों की भी दवाईयां या उसके खर्च का अलग से प्रावधान है और सारा हाउस इस बात की जानता है। जो गरीब आदमी कारखानों में काम करते हैं, उनके लिए ई० एस० आई० के माध्यम से दवाईयां का अवन्ध होता है। जहां तक दवाईयां खरीद कर सस्ती दरों पर गरीबों को उपलब्ध करवाने का सवाल है, अगर टैक्स कम किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि दवाई निर्माता उसका लाभ उपभोक्ताओं को देंगे। इसलिये टैक्स कम करने से सरकार को आभद्रों पर फर्क पड़ेगा या दूसरी स्टेट्स से आने वाली दवाईयां खरीदेंगे तो स्टेट का टैक्स का लोड होगा इसलिए इस प्रकार की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री राम मजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा की मण्डियों में टैक्स ज्यादा होने के कारण भी लौस होता है, क्या सरकार इस बारे में कदम उठाएगी ? यह देख गया है कि नरेला में भी का टीन 818 रुपये में बिकता है और दिल्ली में भी का भाव जो है, वह.....
(विद्यत)

श्री अध्यक्ष : यह सवाल तो दवाईयां पर टैक्स के बारे में है, इसमें भी या दूसरी चीजों के टैक्स की बात नहीं है।

श्री राम मजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि दवाईयां पर जो टैक्स दूसरी स्टेट्स में है, क्या उसके मुताबिक ही हरियाणा में दवाईयां पर टैक्स की व्यवस्था करने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

बहन करतार देवी : स्पीकर साहब, जहाँ तक सभी स्टेट्स का समीकरण का 10.00 वजे सवाल है, सेल टैक्स तो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग है। कुछ चीजें तो ऐसी भी हैं जो बाकी स्टेटों में महंगी हैं और हमारी स्टेट में कम की हैं। दूसरे के पास तो दवाईयों के ही आकड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी आदमी का साल में टर्न-ओवर पांच लाख तक है तो उसके लिए हमने यह विध्या है कि उसे कोई हिस्सा बिकताव रखने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ लम्प-सम टैक्स ही देना पड़ेगा।

साथी लहरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ में दवाईयों पर आधा परसेंट टैक्स लगता है और पंचकुला में आठ परसेंट है। क्या मन्त्री जी चण्डीगढ़ और पंचकुला में जो टैक्सों में फर्क है उसको दूर करेगी ?

बहन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ यू० टी० है, दिल्ली भी यू० टी० है, इसलिये इन में टैक्स कम है। उनका कोई भी स्टेट मुकाबला नहीं कर सकती है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, जो दवाईयों का टैक्स है, वह तो फैक्टरी के सेल डिपो वालों से लिया जाता है जिसके कारण हमारे हरियाणा में भी लॉस हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जितने भी सेल डिपो हैं, वे या तो दिल्ली में हैं या चण्डीगढ़ में हैं, जिसकी वजह से वे कम टैक्स देते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो नान-लार्जिसेसिज हैं, वे दवाईयां दिल्ली से लेकर हरियाणा में सरती बेज देते हैं और लाईसेंसियों की महंगी मिलती है और उन्हें हमारा विभाग तंग करता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि जो दिल्ली और चण्डीगढ़ में टैक्स है, वही टैक्स हमारे हरियाणा में भी लगे, क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मसला है और मैं जम्मू भजन जी की बात से सहमत हूँ। इसके अलावा और भी कई चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली में सरती हैं और हमारी स्टेट में महंगी हैं। इसको तो भारत सरकार ही देखेगी कि पूरे रीजन में एक जैसे सेल टैक्स होने चाहिये।

दूसरे कंसाइनमेंट टैक्स की बात है। अध्यक्ष महोदय, कई फैक्ट्रियां तो हरियाणा में लगी हुई हैं लेकिन उन्होंने अपने हैंड आफिसिज दिल्ली में खोल रखे हैं और अपनी बिक्री दिल्ली में दिखा देते हैं जिससे स्टेट को नुकसान होता है। इस बारे में भारत सरकार विचार कर रही है कि हरेक रीजन का रेट एक जैसा होना चाहिए। पिछले दिनों सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने एन० डी० सी० की मीटिंग भी की थी और यह प्रान्ट उठाया था, मुझे उम्मीद है कि इस बारे में जल्दी ही कोई निर्णय हो जाएगा।

Land Irrigated by Agra Canal

*671. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Irrigation be pleased to state the total acreage of land of Faridabad and Gurgaon Districts being irrigated by Agra Canal ?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra) : The total acreage of land in Faridabad and Gurgaon districts irrigated by Agra Canal was 78330 and 1144 acres respectively during the year 1992-93.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आगरा कैनल हमारे जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण नहर है। जब भी सदन में कोई नहर की बात करता है, तभी वह एस० बी० एल० या बाकी नहरों का जिक्र करता है लेकिन आगरा कैनल का कोई जिक्र नहीं करता। आगरा कैनल फरीदाबाद और गुड़गांव के सेवात के इलाके को पानी देती है। जब मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने कहा था कि जब मैं जीत कर मुख्य मंत्री बनूंगा तो जो इसका मैनेजमेंट है, वह हरियाणा के हाथों में दोगे लेकिन ये अपना वायदा भूल गए। आज इन्होंने सरकार का मुँह हिसार और कालका की तरफ खोला हुआ है। जैसा मंत्री जी ने बताया कि आगरा नहर से फरीदाबाद जिले की 78330 एकड़ और गुड़गांव जिले की 1144 एकड़ भूमि की सिंचाई होती है लेकिन क्या यह बात सच है कि 1991-92 में इस नहर से इससे ज्यादा जमीन की सिंचाई होती थी तथा इससे और पहले भी ज्यादा सिंचाई होती थी ? स्पीकर साहब, क्या यह बात भी सच है कि आगरा नहर की कभी भी खूदाई नहीं की गयी ? इस नहर से निकलने वाले रजवाहों में बहुत गाद भरी हुई है, कीचड़ भरी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस नहर से फरीदाबाद और गुड़गांव जिलों में जो नहर का पानी आता है, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिये वे पुनः अपनी इस मांग की यू० पी० की सरकार से उठावेंगे ताकि आगरा नहर का जो हरियाणा के हिस्से का पानी है, उसकी मात्रा बढ़ाई जाए ? स्पीकर साहब, पहले इस नहर में अपर-नहर और लोअर नहर का पानी आता था लेकिन अब गंदी नहर का पानी भी आता है। स्पीकर साहब, जो पानी हमारी धरती से गुजरता है, उसके लिए हम देखते ही रह जाते हैं और वह पानी यू० पी० वालों के खेतों की सिंचाई करता है, क्या यह ठीक है ? उस पानी पर हमारा हक ज्यादा बनता है, इसलिये क्या मंत्री जी इस मामले की यू० पी० सरकार के साथ उठावेंगे ?

श्रीधर जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इसके बारे में असेम्बली में पहले भी सवाल आया था और उस समय भी यह जवाब दिया गया था कि आगरा नहर जो फरीदाबाद और गुड़गांव के एरिये में आती है, उस पर यू० पी० सरकार का मैनेजमेंट है और इस मैनेजमेंट को हरियाणा में लाने की कई बार बात भी हुई है। यमुना के पानी के बंटवारे का मामला यू० पी० के साथ दिल्ली के साथ, हिमाचल के साथ

और राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ है और शुक्ला जी ने इस मामले पर सभी कंसर्ड मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग भी बुलाई थी। उसमें भी यह मामला उठाया गया था। इसके अलावा, जब यू० पी० में बी० जे० पी० की सरकार थी, तब भी मीटिंग में इस मामले को उठाया गया था। स्पीकर साहब, हर बार यह मुद्दा उठाया जाता है कि इस नहर का मैनेजमेंट हरियाणा को दिया जाए। इसके अलावा, इन्होंने यह भी कहा कि इस नहर से फरीदाबाद जिले में जो पानी लगता है, उससे 78330 एकड़ जमीन की सिंचाई होती है तथा इससे पहले के सालों में यह पानी और ज्यादा था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 1991-92 में फरीदाबाद जिले को मिलने वाले पानी से 73266 एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी और 1990-91 में 81521 एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी। स्पीकर साहब, यह अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीकों से होती थी। इनकी यह बात ठीक है कि यू० पी० वाले इस नहर की सफाई ठीक ढंग से नहीं करते हैं लेकिन हमारी यह पूरी कोशिश रहेगी कि इसका मैनेजमेंट हरियाणा के पास आने के बाद इस की पूरी सफाई हो, पूरी गाद निकाली जाए तथा पानी को टेल तक पहुंचाया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, आगरा नहर का संबंध हमारे जिले से सम्बन्धित है। (विधन)

श्री हरि सिंह नलवा : स्पीकर साहब, जैसा पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री खुराना जी ने कहा था कि हरियाणा से जो पीने का पानी दिल्ली को आता है, उस पर हमारा हक बनता है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि इस पानी पर दिल्ली का हक नहीं बनता। लेकिन दिल्ली के लोगों की तकलीफों को देखते हुए हरियाणा ने दिल्ली को पानी दिया है। स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहूंगा कि जितना पानी हम पीने के लिए उनको देते हैं और जो गन्दा पानी यमुना का दिल्ली से हरियाणा में आता है, क्या आपने उतने पानी के लिए कभी भी दिल्ली की सरकार या भारत सरकार के द्वारा बात की है या ऐसी कोई सरकार के पास प्रॉपोजल है; क्योंकि दिल्ली के लिए पीने के पानी का राईट हरियाणा से नहीं बनता, फिर भी हम उनको पीने का पानी देते हैं। उनके सूखे पानी से हरियाणा की घरती की ज्यादा से ज्यादा सिंचाई हो सकेगी, इसलिये क्या ऐसा सरकार का बातचीत करने का कोई प्रॉपोजल है ?

श्रीधर जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, पिछले दिनों केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्रीमती शीला कौल ने मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली का गन्दा पानी है, वह आप ले लीजिए और साफ पानी हमें दे दीजिए। मुख्य मन्त्री जी भी उस मीटिंग में थे, हमने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो ट्रीटमेंट पानी का हुआ है, उसको भी हमने चैक करवाया है, उसकी ओ० बी० डी० ज्यादा थी, पानी में जर्म्स और कॅमीबैक्ज अधिक मात्रा में थे, उनके पास इच्छे ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हैं। हमने उनसे कह दिया कि इस्तेमाल किया हुआ पानी हम नहीं लेंगे।

चौधरी श्रीम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा सिंचाई मन्त्री जी ने बताया कि यमुना के पानी के बंटवारे के बारे में जब बात हुई तो आगरा कैनल का जिक्र आया। जैसा मुख्य मन्त्री जी ने बताया था, यह बात उससे भिन्न है। यमुना बाँटने की जोयोरिंग के बारे में 1954 में एग््रीमेंट हुआ था, वह 2004 में खत्म होगा उससे पहले इस तरह का कोई प्रश्न ही एराइज नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि यमुना बाँटने के बारे में कोई बातचीत न की जाए। रक्षा आगरा कैनल का सवाल, सतलुज के पानी के बारे में भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड पर कब्जा करने से पहले, क्या पंजाब सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत की थी? उसने कब्जा कर लिया था, इसी तरह क्या हरियाणा सरकार आगरा कैनल पर कब्जा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है ताकि गुडगांव और फरीदाबाद को पूरी मात्रा में पानी मिल जाए?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, इन्होंने जो पहला सवाल किया कि 1954 में जो एग््रीमेंट हुआ था उसमें यह था कि ताजेवाला पर जो पानी है उसमें से दो तिहाई हरियाणा को और एक तिहाई यूपी को मिलेगा, वह सन 2004 तक लेंगे। जो एग््रीमेंट हो रहा है, वो डैम बन जाने के बाद पानी की जो यूटिलिटी है, उसका एग््रीमेंट हो रहा है। जैसे भाखड़ा में पानी स्टोर हो गया जो फ्लड का पानी नहीं होता। अब सर्दियों में पानी की कमी होती है तो पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बारिश के दिनों में यमुना में एक लाख क्यूबिक से पांच लाख क्यूबिक पानी आ जाता है, जब लीन सीजन होता है और दिसम्बर के महीने में जब बर्फ नहीं पिघलती उस समय दो हजार क्यूबिक पानी रह जाता है। अब उस पानी को अधिक समय तक चलाने के लिए ऊपर डैम बनाने हैं, उन डैमों के बन जाने से हम 5-6 या 7 हजार क्यूबिक पानी ले सकेंगे। लीन सीजन की फ्लड को रोकने के लिए डैम बनते हैं। जब डैम बन जाएंगे, उसके बाद पानी के बंटवारे की बात है। इसके अतिरिक्त और बहुत सी बातें हैं, जैसे अब डब्ल्यू० जे० सी० की स्ट्रेप्टिग करके 12 हजार क्यूबिक पानी ले रहे हैं, फिर 23 हजार क्यूबिक पानी ले सकेंगे। जैसे हथिनीकुंड बैराज बनाने की बात है, सुचारु रूप से चलाने की बात है। जहाँ तक इनका दूसरा सवाल है

चौधरी श्रीम प्रकाश बेरी : हथिनी कुंड बैराज बनाने के काम में कितनी प्रोग्रेस हुई है और कब तक काम शुरू किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमेंटरी इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती।

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, जैसे इनका दूसरा सवाल है कि पंजाब वालों ने जैसे भाखड़ा पर कब्जा कर लिया, वैसे हरियाणा आगरा कैनल पर भी कब्जा कर ले। स्पीकर सर, थोखला भी यूपी की टैरिटरी है, वहाँ उन्हीं का कब्जा है, ऐसा तो नहीं है कि धक्के से कब्जा कर लें।

चौधरी जाकिर हुसैन : जैसे गुड़गांवा कैनल के बाणे में मंत्री महोदय ने बताया है कि लगातार बातचीत चल रही है, वे अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा और साथ ही जानना भी चाहूंगा कि आज जो आगरा कैनल में गाढ़ भरी हुई है और रजवाहों में पानी नहीं चल पा रहा है, इसकी सफाई कब तक करा देंगे? यही हालत गुड़गांवा कैनल की है, उसके साथ लगते हुए रजवाहों में भी पानी नहीं आता। क्या मंत्री जी इसके लिये कोई टाईम बाउन्ड प्रोग्राम बनाएंगे और प्रयास कैनल, गुड़गांवा कैनल और उसके रजवाहों की सफाई करवायेंगे ताकि रजवाहों में पानी आ सके और किसानों को पानी मिल सके? आजकल क्या होता है, जब भी वह पानी छोड़ते हैं तो नहर जगह जगह से टूट जाती है और किसान के ऊपर फर्जी कट के कस बनाये जाते हैं। क्या मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे?

चौधरी जगदीश मेहरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि हम किसानों को राहत देने की कोशिश तो करते हैं। आपको पता है कि आगरा कैनल और डब्ल्यू० जे० सी० हरियाणा में पैरेन्सीयल कैनल है। आगरा और जे० एल० एन० कैनल, दोनों नान-पैरेन्सीयल हैं, इनमें केवल बारिश के दिनों में पानी आता है, इसलिये इस बाणे में थोड़ी सी दिक्कत आती है। फिर भी हम यह कोशिश करेंगे कि जहां-जहां पर दिक्कत है, वहां पर पूरा पानी दिया जाये।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि 80 हजार एकड़ के करीब भूमि की सिंचाई होती है। एक बात इन्होंने यह भी मानी है कि इस इलाके की नहरों में पिछले काफी अर्से से सफाई नहीं हुई है और खासकर मेवात इलाके में इन नहरों की सफाई नहीं हुई है। कम से कम आगरा नहर वहां के डेढ़-लाख एकड़ एरिया को सैराब करती है। मुन्हाणा माईनर, बिच्छोर माईनर, हथीन माईनर, भुगरी माईनर और कोट माईनर सारी की सारी सूखी पड़ी हैं, चलती ही नहीं हैं। हथीन क्षेत्र का दू-बर्ड एरिया इससे सैराब होता है, आज वह इलाका बंजर हो गया है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। एक तो जगह-जगह पर लोगों ने दीवारें खड़ी करके डाफ बना लिये हैं और दूसरे यह माईनर जगह-जगह से टूटी पड़ी हैं, परिणामस्वरूप इससे पानी आगे नहीं जा पाता। आगरा कैनल का कन्ट्रोल लेने के लिये सरकार बार-बार यह कह रही है कि इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। आखिर यह बात कब तक होती रहेगी। एस० वाई० एल० पंजाब से गुजस्ती है, वह हमें पानी नहीं दे सकती और आगरा कैनल जो हमारे यहां से गुजरती है वह भी हमें पानी नहीं दे सकती। इसलिये हमारे इलाके के लोगों के सब्र का पैमाना लवरेज हो चुका है। हमारे खेत सूख रहे हैं और रोजी रोटी के लोगों को लाले पड़ रहे हैं। हो सकता है यहां के लोग नहर रोकने के लिये मजबूर हो जायें और रोक कर अपनी काम चलायें। इसलिये यह जरूरी है कि हर कीमत पर हम इसका इन्तजाम अपने हाथ में ले लें और साथ ही इस नहर की सफाई कराने का प्रबन्ध

[चौधरी अजमत खां]

जल्दी से जल्दी करें, वरना लोगों के सब का पैमाना लबरेज हो जायेगा। कभी भी कुछ हो सकता है।

चौधरी जगदीश नेहरा : मंत्री साहब ने जो कुछ कहा है, बाकई यह एक चिन्ता का विषय है।

श्री अध्यक्ष : आपको ग्रामीण हद तक सफाई करवाने से कौन रोकता है? आप वहाँ सफाई करवायें।

चौधरी जगदीश नेहरा : दिक्कत यह है कि इस नहर का कंट्रोल यू० पी० वालों के पास है। न यू० पी० वाले खुद इसकी सफाई कराते हैं और न ही इसका सिस्टम ठीक करते हैं। इसीलिये सरकार पूरी तरह से कोशिशरत है कि इसका मैनेजमेंट हमारे पास दे दिया जाये। पिछली बार मीटिंग में भी यह बात आयी थी। हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी इस नहर का मैनेजमेंट हमारे हाथ में दे दिया जाये। दूसरी बात जो इन्होंने कहा है कि 1960 से इस नहर के द्वारा डेढ़ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है, मैं इस बारे में यह बताना चाहता हूँ कि आगरा कैनल की जद में फरीदाबाद की जो जमीन आती है, वह केवल एक लाख 8 हजार एकड़ है, इसलिये डेढ़ लाख भूमि सिंचित होने का तो सवाल ही नहीं है। इस एक लाख आठ हजार में से तकरीबन 80 हजार एकड़ भूमि की ही सिंचाई होती है।

चौधरी अजमत खां : अध्यक्ष महोदय, इसमें गुड़गाँवा जिले की जमीन भी शामिल है जो इससे सिंचित होती है। मंत्री जी ने केवल जिला फरीदाबाद का सिंचित एरिया बताया है।

मुख्य मंत्री (चौधरी अजमत लाल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य इस बारे में बड़े चिन्तित हैं। बाकई यह एक चिन्ता की बात है क्योंकि आगरा नहर का कंट्रोल यू० पी० वालों के पास है। इसीलिए इस मैटर को बड़ी सीरियसली उठाया है पिछली दो मीटिंग में। हमने कहा कि हमारे किसानों की बड़ी भारी तकलीफ है और इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, अगर हमारा कंट्रोल न हो तो यू० पी० और हरियाणा का ज्वॉइंट कंट्रोल होना चाहिए ताकि नहर की सफाई हो जाए और पानी का बँटवारा ठीक हो जाए। जितना हरियाणा का हक है उतना पानी हरियाणा को मिल जाए। हमने यह भी कहा कि अगर इसका कंट्रोल हमें नहीं मिलता तो भारत सरकार कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। अध्यक्ष महोदय, जब तक यू० पी० वालों का कंट्रोल है, हम उसकी सफाई नहीं कर सकते क्योंकि कंट्रोल उनके पास है। जब तक कोई म्यूचुअल ऐग्रीमेंट नहीं होगा, तब तक सफाई के काम को

हम नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में बातचीत चल रही है कि नहर की सफाई और कन्ट्रोल भारत सरकार ले ले ताकि किसी की शिकायत न हो।

मोहम्मद असलम खाँ : अध्यक्ष महोदय, यू० पी० के साथ 1980 में एक झगड़ा शुरू हुआ था। आज उस बात को बीस साल हो गए हैं। 1954 में यू० पी० के साथ एक ऐग्रीमेंट हुआ था लेकिन 1980 में, जब झगड़ा हुआ तो दोनों तरफ की पुलिस राइफल लेकर बैठ गई और उस वक्त काम को रोक दिया गया और चाहे ताजेवाला है, चाहे हथिनी कुंड है, इनका कन्ट्रोल हमारे हाथ में है। जिस समय सम्पत सिंह जी इरीगेशन एण्ड पावर मिनिस्टर थे, उस समय मैं वहाँ देखने के लिए गया था। यू० पी० वालों ने हथिनी कुंड बैराज पर बहुत ऊपर जाकर एक रेगुलेटर लगा लिया जिससे पानी पर यू० पी० का कन्ट्रोल हो जाए ताकि हम उन पर डिपेंड करें कि वे पानी हमें दें या न दें। क्या सरकार ने इस समस्या को सुलझाने का कोई प्रयत्न किया है ?

श्रीधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि यू० पी० वालों ने एक हाईड्रल पावर हाउस हथिनी कुण्ड पर बनाया। इसको बनाते समय यू० पी० गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने वहाँ एक साइफन ट्राईप एरिया बना दिया ताकि ईस्टर्न जमुना कैनल से साइफन के जरिए पानी ले जाया जा सके। हमारी सरकार ने, सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने तथा हरियाणा की पहले वाली सरकार ने यू० पी० वालों के साथ मीटिंग करके तथा लिखकर इस बारे में एतराज किया कि यह कार्यवाही उनकी गलत है। अगर वहाँ हाईड्रल पावर हाउस बना दिया तो पानी के बंटवारे का कोई मतलब नहीं रह जाता। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वहाँ पर बनाया कुछ जरूर है लेकिन जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि साइफन से हथिनी कुण्ड बैराज को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मुख्य मन्त्री जी ने श्रीर गुब्बला जी ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा कि हम इस तरह से मिलने नहीं देंगे। ताजेवाला और हथिनी कुण्ड से कोई चीज मिलाने का कोई मतलब ही नहीं है और इस बारे में हमने लिखकर भी दिया है और मीटिंग में भी यह बात कही है।

श्री कर्ण सिंह इलाल : अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनल के कन्ट्रोल के बारे में काफी बातें यहाँ सुनने को मिली हैं। मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि कन्ट्रोल हमें नहीं मिल रहा है। लेकिन यू० पी० की सरकार यह कहती है कि आगरा कैनल का कन्ट्रोल हरियाणा अपने हाथ में ले ले, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन वे पैसा मांगते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की फिजूल खर्चियाँ इतनी हैं कि इस सरकार का नहरों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर नहर का कन्ट्रोल हरियाणा सरकार को नहीं मिलता, तो क्या वे हरियाणा को जितना पानी मिलता है, उसको बढ़वाने का प्रयास करेंगे ? दूसरी बात यह है कि अगर हरियाणा के हिस्से का पानी बढ़ जाए तो उस पानी को

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

आगरा कैनल में डालने की वजाएँ गुड़गांव कैनल में डाला जाएगा जिससे गुड़गांव के जमींदारों को फायदा पहुंच सके ?

श्रीधर जगदीश नेहरा : इसके लिये स्पीकर साहब, पिछले दिनों यमुना के चौक इंजीनियर से मैंने कहा था और उन्होंने अम्बूरा के एस० ई० से बातचीत की थी। दोबारा फिर मैंने उन से कहा, आपकी चाहे सख्त जाकर वहाँ के अधिकारियों के साथ चर्चा करनी पड़े, आप करें ताकि पानी का जो सिस्टम है, वह ठीक हो सके और जो हमारा हिस्सा है, वह हमें मिले। साथ में मैन्टीनेन्स के बारे में, सफाई के बारे में और बाराबन्की के बारे में भी हमने उन से बातचीत की है। हम तो चाहते हैं कि यह सिस्टम ठीक चले और किसानों की जो दिक्कतें हैं, वह सही तरीके से दूर हों। इन सब बातों के लिये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

Construction of Roads

*696. **Ch. Bharath Singh :** Will the Minister for P.W. D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the following roads of District Kaithal :

1. Balu to Gulyana ;
2. Kairam to Balu ;
3. Kala-sar to Kheri Sherkhana ;
4. Kolekhan to Gurusar ; and

(b) if so, the time by which the above-said roads are likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्रीधर अमरन्द सिंह डांगी) :

(क) नहीं, श्रीमान जी ।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिकोण प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीधर भरत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जब यह वायदा किया है कि हम हर गाँव की पक्की सड़कों से जोड़ेंगे, तो कब तक सरकार सभी गाँवों की पक्की सड़कों से जोड़ देगी ?

चौधरी प्रानन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केवल चार सड़कों बारे में सवाल पूछा है और यह चारों सड़कों पहले ही दूसरी सड़कों से जुड़ी हुई हैं। बालू रोड कस्तान के पास जीन्द रोड पर मिली हुई है, इसी तरह से गुल्याणा गाँव की जो सड़क है, वह भी कैथल जीन्द से मिली हुई है। कलौरम बालू नरवाना से कैथल रोड पर, गाँव अलग अलग सड़कों से मिले हुए हैं। नत्तासर से छोड़ो शेरखां वह नत्तासर कलायत रोड तथा शेरखां मण्डौकता से लॉडर सड़क के पास मिली हुई है। चौथी जो सड़क कालिखा से गुस्तर तक की है, वह पहले ही मैन रोड से मिली हुई है।

Outstanding Electricity Bills

*727. **Prof. Sampat Singh :** Will the Minister for Power be pleased to state the total amount of arrears on account of Electricity bills outstanding against the consumers in the State at present ?

Power Minister (Sh. A.C. Chaudhary) : Ending November, 1993, a sum of Rs. 492.20 crores was outstanding against electricity consumers of all categories, out of which Rs. 396.52 crores pertained to Government/Semi Government connections.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह जो 492.20 करोड़ रुपये के पैडिंग बिल्लज हैं, उनमें डोमैस्टिक, कमर्शियल, एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरी जो कंटेनरीज हैं, इनकी अलग-अलग राशि कितनी-कितनी है ? खासतौर पर इंडस्ट्रीज के लिए जो बलक सप्लाय होती है, उसकी कितनी राशि है ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इन बिलों की रिकवरी के लिये सरकार ने क्या स्टेप्स उठाये हैं ताकि यह रिकवरी जल्दी हो सके ?

श्री ए० सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिसने एरियर्स मैंने अपने जवाब में बताए हैं, उन में कुछ राशि सरकारी व कुछ राशि अर्ध सरकारी कुम्बेशनों से सम्बन्धित है। इसके इलावा जो लोग इलेक्ट्रीसिटी क्लब के मुताबिक एरियर्स में होते हैं, उनको बी० सी० ओ० ही आर्डर इशू करके कनेक्शन डिस्कनेक्ट करता है लेकिन इसमें बहुत सारे शायद 80 से पहले के हैं। शायद 1976-77 के हैं। वे बाई एण्ड लार्ज या तो लॉअर कोर्ट में चले गये हैं और जो हमारे काबू में आते हैं, हमने उनसे लैन्ड रवेग्यु एक्ट के तहत, इन्क्वैशन के द्वारा या रिशलाइजेशन के तौर पर एरियर्स बसूल करने की पूरी चेष्टा की है। जो केसिज कोर्ट में होते हैं, जब तक कोर्ट फैसला नहीं करती, हम बेवस हैं। मैं तो यह बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट में केसिज आलमोस्ट 1980 से चल रहे हैं। स्पीकर साहब, प्राइवेट कंटेनरी में जो जनरल है, उस में 60318, एग्रीकल्चर में 13018, इंडस्ट्रियल में 8981 डिफरेंड

[श्री ए. 0 सी. 0 चौधरी]

कॉज्यूमर्ज हैं। जहाँ तक अमाउंट की बात है, जनरल में 29.40 करोड़ रुपए, एग्जीक्यूटिव में 25.75 करोड़ रुपए और इंडस्ट्रियल में 40.51 करोड़ रुपए हैं।

श्री 0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि केंसिज कोर्ट में है और दूसरे कहा है कि एज एरियर्ज आफ लैंड रैवेन्यू रिकवरी की है। मैं जानना चाहता हूँ कि एज एरियर्ज आफ लैंड रैवेन्यू कितनी रिकवरी की है? कहीं ऐसा तो नहीं....

श्री अध्यक्ष : अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Upgradation of High School, Madlauda into 10+2 System School

*712. Shri Krishna Lal : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Government High School, Madlauda in District Panipat into 10+2 system during the year 1993-94 ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : जी नहीं।

Navodya School

*708. Shri Satbir Singh Kadian : Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Navodya School in District Panipat ; if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : जी हाँ, सिवाह में नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। परन्तु समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

Appointment made on Daily-wages Basis

*746. Smt. Chandravati : Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) the post-wise number of persons working on daily-wages in the Transport Department at present ; and

- (b) whether any persons have been appointed on permanent/daily-wages basis in Dadri Depot during the period from 1st January, 1993 to-date; if so, the names and addresses thereof?

***Interim Reply**

BALBIRPAL SHAH

D.O. No. 26/5/94-3TC
Minister of State for
Transport, Haryana,
Chandigarh.
Dated 4th March, 1994

**Subject :—Starred Assembly Question No. 746—Smt. Chandrawati,
M.L.A.**

Dear Shri

Kindly refer to the subject noted above.

2. The reply to the above mentioned Starred Assembly Question involves collection and consolidation of information pertaining to the persons working on daily wages in the Transport Department. This information is required to be collected from all the General Managers of Haryana Roadways, all Secretaries of Regional Transport Authorities, S.P. (Traffic), Flying Squad Officer (ISBT), Delhi etc., who are their appointing authorities. It would take considerable time to collect this information from as many as 29 different offices located in the State.

3. Keeping in view the circumstances explained above, I shall be grateful if an extension of one month's time is given for reply of this Starred Assembly Question.

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd/-
(Balbirpal Shah)

Shri Ishwar Singh,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh."

Construction of a Grain Market at Siwan

***734. Shri Amar Singh Dhanday :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a grain market at Siwan in Distt. Kaithal; and
(b) if so, the time by which the aforesaid market is likely to be constructed?

*Final reply to this question appears as Annexure A in this debate at page 85.

कृषि मन्त्री (श्री हरपाल सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) उक्त प्रयोजन हेतु भूमि अर्जन के पश्चात् निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा ।

Setting up of 132 K.V. Sub-Station at Pipli and Ladwa

*843. Dr. Ram Parkash : Will the Minister for Power be pleased to state—

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up a 132 K.V. (or more) Sub-station at Pipli and Ladwa in Distt. Kurukshetra; and
- (b) if so, the time by which the aforesaid Sub-stations are likely to be set up ?

विजली मन्त्री (श्री ए. सी. चौधरी) :

(क) हाँ, श्रीमान् जी ।

(ख) 132 के. वी. उपकेन्द्र, पिपली वर्ष 1996-97 तक तथा 220 के. वी. उपकेन्द्र लाडवा वर्ष 1997-98 तक ।

Molasses of Sugar Mill, Kaithal

*829. Shri Ram Kumar Katwal : Will the Minister for Co-operation be pleased to state the name of the persons/agency to whom the molasses of Sugar Mills, Kaithal was supplied during the year 1992 and 1993 separately together with the names of persons/agency to whom it is being supplied at present ?

सहकारिता मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) : ब्यौरे का विवरण सदन के पटल पर रखा है ।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान केवल सहकारी चीनी

नियम 46 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए त्वायिकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (8)23

मिल द्वारा पाटी अनुसार दिये गये शीरे का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	पाटी का नाम	मात्रा (किबंटलों में)
1	2	3
1991-92		
1.	शुशुका डिस्टिलरिज लि०, हृशीन	32965.40
2.	डी पानीपत सहकारी डिस्टिलरी लि०, पानीपत	19420.50
3.	ऐसोसिएटिड डिस्टिलरिज लि०, हिसार	18229.35
4.	हरियाणा फेरो ऐलोज लि०, रोहतक	7491.00
5.	केमी सेल्ज, सोनीपत	1369.10
6.	हरियाणा स्टील एण्ड ऐलोज लि०, सोनीपत	465.55
7.	डेवीको (इण्डिया) ग्रायरन फाऊंडरी एण्ड इन्जिनियरिंग वर्क्स, नरवाना	432.25
8.	भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	398.40
9.	सिंगला इण्डस्ट्रीज, सोनीपत	350.30
10.	किसान फीड्स प्राइवेट लि०, अम्बाला	333.25
11.	अमित फाऊंडरी एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, कैथल	267.85
12.	ऐनीमल ब्रीडिंग एण्ड जनेटिक्स, पालमपुर (हि० प्रदेश)	257.15
13.	आफिसर इन्चार्ज मिलिटरी फार्म, अम्बाला कैंट	242.85
14.	गगत फाऊंडरी उद्योग, कैथल	158.55
15.	जे भारत फाऊंडरी उद्योग, कैथल	150.65
16.	माया मशीन टूलज, फरीदाबाद	147.00
17.	चौधरी इस्पलत उद्योग, कैथल	146.35
18.	चौधरी इंजिनियरिंग वर्क्स, कैथल	141.60
19.	हर हर महादेव लम्बाकू कम्पनी, यमुनानगर	121.40
20.	जे प्रकाश कैलाश चन्द, यमुनानगर	82.00
कुल		83170.50

(8) 24

हरियाणा विधान सभा

[9 मार्च, 1994]

[श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया]

क्रम सं०	पार्टी का नाम	मात्रा (किबंटलों में)
1992-93		
1.	एसोसिएटिड डिस्टिलरिज लि०, हिसार	61544.05
2.	दो पानीपत सहकारी डिस्टिलरिज लि०, पानीपत	39659.05
3.	अशोका डिस्टिलरिज लि०, हथौन	15553.50
	कुल	116756.60
1993-94		
1.	दो पानीपत सहकारी डिस्टिलरिज लि०, पानीपत	6492.40
2.	एसोसिएटिड डिस्टिलरिज लि०, हिसार	4941.20
	कुल	11433.60

राज्यपाल महोदय का संदेश

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received a message from the Governor, which reads as under :—

"Hon'ble Speaker, Thank you so much for your communication No. HVS-LA-36/94/4290 dated the 4th March, 1994 sending there-with a copy of the "Motion of Thanks" on my address passed by Haryana Vidhan Sabha on 4th March, 1994".

विभिन्न विषयों का उठाया जाना

प्र० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आपकी इजाजत से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कल जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बोल रहे थे तो हमारे आदरणीय मंत्री श्री सुरेन्द्र कुमार मदान ने एक जमीन की आफर दी थी कि अगर कोई उस

जमीन को लेना चाहें तो मैं दे सकता हूँ। यह बात अखबारों में भी आई है। अखबार की खबर को पढ़ कर श्री हुकम चन्द कौंसलर ने आफर दी है। वे कहते हैं कि समाचार पत्र में श्री सुरेन्द्र कुमार मदान ने जो घोषणा की है, मैं उससे डबल रेट देने के लिए तैयार हूँ। यह एप्लीकेंट लिखता है कि हालांकि उस जमीन में वृक्ष उखाड़ दिए गए हैं, फिर भी मैं पांच साल के लिए उसे डबल रेट पर लेने के लिए तैयार हूँ। स्पीकर साहब, हुकम चन्द म्यूनिसिपल कौंसलर वार्ड नं० 15, कैंथल की यह आफर है। उन्होंने अपनी तरफ से रिकवैस्ट भेजी है कि मुझे अखबार से पता चला है और मैं डबल रेट पर लेने के लिए तैयार हूँ। उनकी रिकवैस्ट मेरे पास है जो मैं मुख्य मन्त्री के पास भेज रहा हूँ। (वह आफर मुख्य मन्त्री को दे दी गई)

लोक सम्पर्क राज्य संत्री (श्री सुरेन्द्र कुमार मदान) : स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी ने जो कहा है, वह मुझे भंगुर है। वे 34 हजार रुपए मुझे दे दें।

Prof. Sampat Singh : I do not want this land. Municipal Councillor wants this land. Whether you are accepting the request of the Councillor or not?

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान : स्पीकर साहब, उन्होंने 34 हजार रुपए कहा है, इसलिये 17 हजार रुपए सम्पत सिंह जी रख लें और 17 हजार रुपए मुझे दे दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, वह दरखास्त मुख्य मन्त्री जी के नाम पेड़ेंस की गई है और पहुंच रही है सम्पत सिंह जी के पास। मदान साहब ने उनकी आफर भी दी है कि आप 34 हजार रुपए में वह जमीन ले लें। अब सम्पत सिंह जी, आपको हाँ करनी चाहिए। अब आप भाग क्यों रहे हैं ?

श्री० सम्पत सिंह : सम्पत सिंह नहीं भाग रहा, भाग तो मदान रहा है।
You are protecting him.

श्री अध्यक्ष : ये तो बेनामी लेना चाहते हैं। (शोर)

श्री० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आपने यह जो कहा है कि बेनामी लेना चाहते हैं, यह बात एकसपज होनी चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : वह दरखास्त आपके पास किस लिए आई है ?

श्री० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, जिस आवमी ने यह दरखास्त दी है, वह विजोटर गैलरी में मौजूद हैं। आपने जो बेनामी कहा है, वह एकसपज बन जाए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आपके पास वह दरखास्त क्यों आई है ? (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, आप 'बिनामी' शब्द एक्सपेंज करवाएँ।
(शोर)

Mr Speaker : The remarks of Speaker cannot be expunged.

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, उसने वह दरखास्त मुझे दी है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : वाइडररेंज आपके पास आई है। आपके पास वह दरखास्त प्राने की कोई बजह नहीं है। (शोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ ऑर्डर है। कल शकरी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाया गया था।

प्रो० सम्पत सिंह : मेरी तरफ से एप्लीकेशन नहीं लगाया गया था। वह तो चौदाला साहब की ओर से लगाया गया था।

चौधरी भजन लाल : ठीक है, उनकी तरफ से लगाया गया होगा। हमारे मंत्री ने कल ही उनकी बात एक्सपेंज कर ली थी। अब इन्होंने अखबार में पढ़ लिया और कहते हैं कि उस जमीन को लेने के लिए इनके पास कोई दरखास्त आई है और वह दरखास्त मुख्य मंत्री जी के नाम है। आप मुख्य मंत्री के दलाल कब से हो गए? अध्यक्ष महोदय, जिस किसी आदमी ने वह दरखास्त दी है, उसने न उसके साथ कोई चैक लगाया है और न ही कोई एफेडेविट लगाया है। वैसे ही किसी से लिखवा कर वह दरखास्त दे दी। यदि वह आदमी उस जमीन को लेने के लिए तैयार है तो दरखास्त के साथ एफेडेविट लगाता। मंत्री जी ने कल भी यह आफर दी थी कि व, जमीन जितने की है, उतने पैसे में ले लो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?

प्रो० सम्पत सिंह : उस जमीन को म्यूनिसिपल कीसलर लेना चाहते हैं।

चौधरी भजन लाल : जो भी लेना चाहते हैं, वह आप बता दें। मंत्री जी देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी जिम्मेदारी की कोई बात नहीं है। अपोजिशन के लीडर का यह कर्तव्य बनता है कि कोई ठोस बात कहे। कोई ठोस उदाहरण दे। यह कोई शोभा नहीं देता कि एक कागज पर लिखवा कर ले आए। इस तरह के हम सौ कागज लिखवा देंगे, यह कोई अच्छी बात नहीं है। आपकी ठोस बात करनी चाहिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मंत्री जी ने आपन आफर दी है कि जो आदमी उस जमीन को लेना चाहे, वह आपन आवशन में ले ले। सबको यह अधिकार है कि आपन आवशन में जो भी आदमी लेना चाहे, ले सकता है। आपन आवशन में जमीन लेना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। मंत्री जी की मां ने वह जमीन ले ली, उसकी आपको तकलीफ हो गई। यदि और कोई आदमी

लेता तो आपको कोई तकलीफ न होती। यह कोई तरीका नहीं है। इस तरह के बेवनियाद इल्जाम लगाना आपको शोभा नहीं देता।

बिजली मन्त्री (श्री ए० सी० चौधरी) : स्पीकर साहब, यह सही बात है कि आज हाउस में लीडर आफ अपोजिशन ने एक पर्चा दिखा कर एक नयी चीज इमाटाइज करने की कोशिश की। ये भाई उस जमीन को बेनामी लेना चाहते हैं। स्पीकर साहब, आपकी यह ऑब्जर्वेशन सही है कि ये उस जमीन को बेनामी लेना चाहते हैं। मेरे भाई कौशल के म्युनिसिपल कांसलर के साथ क्यों लिंक रखते हैं? मैं समझता हूँ कि इनकी दलाली में जो पुराना खाता था, उसमें शायद यह खाता रहता था। इसलिए ये आस लगाए बैठे हैं, वरना 17 हजार रुपये में देने की बात है। कोई व्यक्ति जो अपनी आत्मा की आवाज बुनाने वाला है, और मंत्री के स्टेटस का है, 17 हजार रुपये के लिए अपने आपको कान्ट्रोलरों में डालेगा? (शोर) इस प्रकार प्राइवेट लोगों की गलत चिट्ठियाँ इस्तेमाल करने का इनका कोई अधिकार है? (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक एप्लीकेशन की बात है, अपोजीशन लीडर के नाते मेरे पास लोगों की दरखास्ते आती रहती हैं और इस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँ। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप वह एप्लीकेशन चीफ मिनिस्टर को दे दें।

प्रो० सम्पत सिंह : वह तो मैंने पहले ही दे दी है। (शोर)

चौधरी भजन लाल : यह है तो सी० एम० के नाम, फिर आपके पास कैसे आ गई? (शोर)

श्री ए० सी० चौधरी : एप्लीकेशन पर जो सिग्नेचर हुए हैं, उनको बैरीफाई कराया जाये कि असल में ये किसके सिग्नेचर हैं। (शोर)

श्री धीर पास सिंह : आज वह सुबह एम० एल० ए० होस्टल में आया था, उस समय उस काउंसलर ने यह एप्लीकेशन दी थी। (शोर)

श्री सुरेन्द्र कुमार मदान : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर हाउस में आकर देता हूँ अपने विपक्ष के नेता प्रो० सम्पत सिंह जी को कि आप इस जमीन को 34 हजार रुपये में ले लें और साथ में ये 10 परसेंट कमीशन भी ले लें। (शोर) मैं सारे अधिकार इस जमीन से छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ये लेने वाले तो बनें। (शोर)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, कमीशन-खोरी का काम इनका है, हमारा नहीं है। (शोर) इसमें ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। एक काउंसलर ने अपनी बाफर दे दी है इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अपोजीशन लीडर होने के नाते लोगों की प्रिवेंसिज और एप्लीकेशन मेरे पास आती रहती हैं। उनकी

[श्री० सम्पत सिंह]

ग्रिवेंसिज को रेज करना मेरा फर्ज बनता है। इस बारे में एक काउंसिलर ने अपनी आफर दे दी है और हो सकता है कि 10-20 लोगों की और आफर आ जाए। जब एक काउंसिलर की आफर आ गई है तो सी०एम० साहब को और मंत्री महोदय का फर्ज बनता है कि उसकी आफर को माना जाये और वह जमीन उसे दे दी जाए। (शोर) ये अपने गंजत कारनामों को छपाना चाहते हैं। इनका काम तो सिर्फ लैंड ग्रैबिंग का ही रह गया है। (शोर)

श्री ए० सी० चौधरी : इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है, इस पर किसके दस्तखत हैं, यह चेक कराएं। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाएं। अब सम्पत सिंह जी अपने कालिग अटेंशन के बारे में पूछ लें।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

श्री० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैंने 2-3-94 को एक कालिग अटेंशन मोशन अण्डर रूज 73 के तहत दिया था कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी खनिज हैं, मिनरल्स की माइन्स हैं, वे इस सरकार ने अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को दे रखी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उस कालिग अटेंशन नोटिस का क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। Sambat Singh Ji, it is under consideration. Nothing should be said about this. (Interruptions).

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो कालिग अटेंशन मोशन आपको दिए थे। एक तो यह था कि हरियाणा सरकार ने लाटरी डाल कर जो बस स्ट परमिट पंजीकृत सोलायटियों को दिए हैं, मैंने मांग की है कि 20 प्रतिशत अनुसूचित जातियों को और 10 प्रतिशत पिछड़े वर्ग को दिए जाएं, पर दिये नहीं गये। मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्ट परमिट्स कितने बैकवर्ड लोगों को दिए गए और कितने हरिजनों को दिए गए ?

Mr. Speaker : It has been disallowed. Now please take your seat.

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मेरा एक दूसरा कालिग अटेंशन मोशन मेह की छरपतवार नासक इन्फोर्मर क्वालिटी दवाई के बारे में था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, आपका कालिग अटेंशन मोशन regarding inferior quality of medicines has been admitted for 16th March, 1994.

श्री कर्ण दलाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के जूडिशियल आफिसर के बारे में मेरा कालिग अटेंशन मोशन था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपका यह कालिग अटेंशन मोशन सूबह 9.55 बजे प्राप्त हुआ है, आप अभी बैठिए। (विध्व)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मेरा एक और कालिग अटेंशन मोशन काष्ठ सेतली से होडेल तक सड़क के बारे में था। इस सड़क पर एक्सिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जीप का एक्सिडेंट हुआ था जिसमें 10 लोग मारे पर हीं मारे गए थे। आए दिन इस सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उन एक्सिडेंट्स में अनेकों लोगों की जानें चली जाती हैं। स्पीकर साहब, यह बहुत ही जरूरी मसला है।

Mr. Speaker : Dalal Sahib, your calling attention notice regarding road accidents occurring due to the negligence of officers has been disallowed.

श्री लहरी सिंह : स्पीकर सर, आलू की फसल को सुरक्षित करने के लिए मेरा एक कालिग अटेंशन मोशन था, उसका क्या बना ?

Mr. Speaker : It has been sent to the Government for comments

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, सीवरेज के बारे में मेरा एक कालिग अटेंशन मोशन था, उसका क्या हुआ ?

Mr. Speaker : It is admitted for today.

विभिन्न विषयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री धीरेंद्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सारे सदस्यों का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले दिनों पाकिस्तान में "तहरीके मुजाहीदीन" नाम की एक किताब छपी है जिसके अर्थर सादिक हुसैन हैं। इस किताब में सिख गुरुओं के खिलाफ कई आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं। पिछले दिनों सभी पोलिटिकल पार्टियाँ और पार्लियामेंट के सदस्यों ने भी इन शब्दों की भर्त्सना की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह कहना चाहता हूँ कि एक प्रस्ताव के माध्यम से भारत सरकार को लिखा जाए कि इस किताब पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। यह किताब भारत में नहीं आनी चाहिए और भारत में नहीं बिकनी चाहिए। इस किताब में हमारे बुजुर्गों और गुरुओं के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है इसलिए इसकी निन्दा की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आपका कोई नोटिस मेरे पास विचारार्थीन नहीं है।
(बिल)

श्री 0 राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, इस 'तहरीके मुजाहीदीन' किताब में 5वें, छठे, 9वें और 10वें गुरुओं के खिलाफ जो अपमानजनक शब्द कहे गए हैं, वे केवल मात्र गुरुओं का ही नहीं बल्कि सारी मानवता का अपमान है जिस पर सारे देश में प्रतिक्रिया हुई है और देशभक्त तथा धर्मनिर्पेक्ष लोगों को इससे भारी चोट पहुंची है। इससे पहले भी सलमान रशदी की किताब पर पाबन्दी लगाने की बात सबसे पहले भारत सरकार ने की थी, उसके खिलाफ आवाजें उठाई थी और भारत में उस पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि यह किताब प्रतिबन्धित कर देनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। पाकिस्तान में यह किताब स्कूल के बच्चों को दे कर उनके मन में जहर भरा जा रहा है। इस प्रकार की गन्दी किताब को छाप कर गुरुओं और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बहुत ही गन्दे शब्द इस्तेमाल करने की जितनी निन्दा की जाए वह कम है। बिल क्लैंटन जो ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स की बात करते हैं, आज वे इस पर चुप क्यों हैं? यह केवल गुरुओं और महाराजा रणजीत सिंह का अपमान नहीं है बल्कि समूची मानवता का अपमान है। ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग आज बहाने हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सारा सदन एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार तथा पाकिस्तान एम्बेसी को भेजे कि हमारी भावनाओं की कद्र की जाए और इस किताब पर पाबन्दी लगाई जाए।

श्री श्री अमन प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मुद्दा है और यह देश के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी भी गुरु की शान के खिलाफ, किसी भी स्तर पर अप-शब्द इस्तेमाल किये जाएं या उनकी शान में कोई गुस्ताखी की जाए तो यह किसी व्यक्ति विशेष का ही नहीं, पूरे देश का अपमान है। इसके लिए तो सारा सदन सहमत होगा और यह बहुत ही अहम मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बारे में दिलचस्पी लेकर इस सदन की ओर से एक रेजोल्यूशन पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जाए। मेरे स्थान से इस बारे में केन्द्र को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।

मुख्य मंत्री (श्री श्री भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ किताब में लिखा हुआ है, वह हमने देखा तक नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है तो यह बहुत ही निन्दनीय बात है। लेकिन हमें यह देखना है कि भारत सरकार इस पर क्या विचार कर रही है। इस बारे में हम आज ही भारत सरकार से पूछ लेंगे। अगर हमें कुछ करना भी है तो वह हमें भारत सरकार से पूछ कर ही करना चाहिए क्योंकि यह दूसरे देश का मामला है। भारत सरकार से बात करने के बाद जब भी अगला सेशन

आएगा तो उसमें यह प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं। चाहे कोई भी धर्म ही, अगर कोई उसके बारे में ऐसी कोई आपत्तिजनक बात कहे, तो ठीक नहीं है।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, अगर हम यहां पर आवाज पैदा करेंगे, तबमाम भारत एकमत होकर प्रस्ताव पास करेगा तो इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रायः हरेक संस्था ने, चाहे बड़े कितने भी धर्म की क्यों न हो, इसका विरोध किया है।

श्री अध्यक्ष : राम प्रकाश जी, मेरे विचार में अभी किसी ने भी वह कितना नहीं पढ़ी है, सिर्फ आपने अखबारों में ही पढ़ा है। हमें यह देखना है कि गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोच रही है और मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव दिया है, वह ठीक है। इस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके ही कुछ हो सकता है।

श्रीधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने श्रीर लीडर आफ दी हाऊस ने जो बात कही है, इस बारे में आपको जो भी करना है, वह रैजोल्यूशन पढ़कर करें या भारत सरकार से बातचीत करके करें, लेकिन मेरा सुझाव है कि अगर यह सत्य है तो डा हाऊस के विचार आज ही भारत सरकार को जाने चाहिए।

श्रीधरी मजन लाल : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव कंजीशनल नहीं होते, इस बारे में बहुत कुछ देखकर करना पड़ता है।

श्रीधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में प्रस्ताव पास होना चाहिए और भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से पूछे जिन्होंने हमारे गुरुओं की तिम्दा की है। सोकर से, यह विशुद्ध इतिहास की तरफ करके ऐसी बातें कही गयी हैं जिनकी पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का इतिहास अलग-अलग नहीं है, दोनों का इतिहास एक ही है।

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी, पूरी बात हो चुकी है और सभी इस बात से सहमत भी हैं कि जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, वह ठीक है। इसलिए अब आप बैठिये।

श्रीधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, किस बात से सहमत हैं ?

श्री अध्यक्ष : जो आपका विचार है, वही बाकी सबका विचार है। इसके बारे में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत कर ली जाये, फिर कार्यवाही की जाए तो अच्छा रहेगा।

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, वह बात कही जा रही है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछकर फिर प्रस्ताव पास किया जाए लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा किया गया तो फिर यह पाकिस्तान संसार

[डा० राम प्रकाश]

को यह कहेगा कि केन्द्रीय सरकार ही ऐसे रैजोल्यूशन पास करने के लिए तैयार कर रही है जनता की अपनी प्रतिक्रिया नहीं है। क्या इस तरह की छाप सबके सामने नहीं आएगी? क्या यह हाऊस इस तरह का एक रैजोल्यूशन पास करने में भी स्वतंत्र नहीं है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, बजाय इसके कि इस पर पहले कोई कार्यवाही की जाए, सबसे पहले सारे फैक्ट्स वेरीफाई करने ही पड़ेंगे। (विघ्न)

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष: चन्द्रावती जी, अभी आप बैठिये।

स्थगन प्रस्ताव—

Mr. Speaker: Now, the Hon'ble Members, I have received an Adjournment Motion from Shri Om Parkash Chauhala and 11 other members regarding signing of GATT agreement by the Central Government. As the subject matter relates to entry enumerated in the Union List at Serial No. 14 i.e. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing of treaties, agreements and conventions with foreign countries, hence the subject matter of the motion does not fall within the responsibility of the State Government. Therefore, on this account, the motion is ruled out.

श्री० सन्पत सिंह: स्पीकर सर, कल जो हमने अपना स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में आपने अपनी ख़लिय दे दी है। आपने कहा है कि यह मामला यूनियन लिस्ट में है और यूनियन लिस्ट में होने की वजह से ही आपने यह ख़लिय दी है। स्पीकर साहब, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम आपकी ख़लिय को रिजैक्ट करते हैं। सर, हम आपके फैसले को रिजैक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि यह कह रहे हैं कि एक रैजोल्यूशन इस हाऊस की तरफ से भेजा जाए। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, पहले भी इस तरह के सुजेशन स्टेट्स की तरफ से जाते रहे हैं। अगर हमारी तरफ से भी कोई ऐसा रैजोल्यूशन चला जाए तो इस पर सरकार को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको कौंसिल भी नहीं करना चाहिए। सर, हम आपके फैसले को रिजैक्ट नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है आपने अपना कल जो प्रस्ताव दिया था, मैंने उसके बारे में बता दिया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—

सब्जियों तथा फलदार पौधों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सीवरेज के पानी सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of calling attention motion No. 8 given notice of by Shri Amir Chand Makkar, M.L.A. regarding sewerage water being used for irrigation of vegetables and fruit plants. I admit it. Shri Amir Chand Makkar may read his notice and the concerned Minister may make the statement thereafter.

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि लगभग 7-8 वर्ष पूर्व भारत सरकार द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि सीवरेज का गन्दा पानी सब्जियाँ व फलों वाले पौधों के लिए प्रयोग में न लाया जाए क्योंकि इससे कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ फैलती हैं। परन्तु अभी तक कई शहरों में इस पानी को सब्जियाँ पैदा करने व फलों वाले पौधों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है। भारत सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिए गए थे कि जो भी व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा उसे दण्डित किया जाएगा। परन्तु इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए इन निर्देशों के पालन के लिए सभी नगर-पालिकाओं को तुरन्त निर्देश दिए जाएँ तथा सीवरेज के इस गन्दे पानी का सब्जियाँ पैदा करने व फलों वाले पौधों के लिए प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए। इस प्रान्त को साफ करने के लिए नगरपालिकाओं को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए निर्देश दिए जाएँ। गन्दा पानी केवल उन्हीं पेड़ों/पौधों के लिए प्रयोग में लाया जाए जो कि फलदार तथा सब्जियाँ देने वाले नहीं हैं।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस मामले में की गई कार्यवाही या की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में सदन में एक वक्तव्य दे।

वक्तव्य—

जन स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना सम्बन्धी

Mr. Speaker : Now I will request the Public Health Minister to make his statement.

P.W.D. Public Health Minister (Sh. Ram Pal Singh Kanwar) : Sir, out of 80 towns, at present, only 40 towns have the sewerage system which is in operation, where as in the remaining towns, the waste water from the houses is drained through

11.00 a.m.

[Sh. Ram Pal Singh Kanwar]

open drains. Even though the execution of various development programmes in the municipal area is the responsibility of the respective municipality, the Govt. on observing that the condition of water supply and sewerage services was becoming bad, decided to take over the maintenance of water supply and sewerage system in the towns w.e.f. 2-4-1993. Consequently, the Public Health Engineering Department has been entrusted with this work to be executed at the cost and on behalf of respective municipalities.

In the State of Haryana, at present there is no town, where sewerage treatment facility has been provided. However under the Yamuna Action Plan, with the assistance of the Government of India and a soft loan from the Government of Japan, six towns namely Yamuna Nagar-Jagadhri, Karnal, Panipat, Sonapat, Faridabad and Gurgaon will be extensively covered and the sewerage will be treated upto the desired norms. This project is likely to cost about Rs. 133 crores. For covering the remaining 74 towns, the amount required for providing sewerage treatment plants will be very high and the question of arranging finances for this work is very much engaging the attention of the Government.

The Sewerage, at present, is being discharged either into the natural drains or in certain areas where enough agricultural land is under command, it is being used for irrigation purposes. Till this year, the auction of sullage from most of the towns has been done by the respective municipalities and the municipal committees have been making an effort to ensure that the Sewerage water is not used for growing fruit and vegetables. But in many cases, it has been observed that there has been a violation of the terms and conditions of auction and the Government is concerned about the same. This issue was taken up in the meeting of the State Environment Protection Council, Haryana on 28th July, 1993 under the Chairmanship of His Excellency Shri Dhanik Lal Mandal, Governor of Haryana. The council approved that a ban should be imposed on use of sullage water for growing vegetables and accordingly, all the municipalities were directed to implement these instructions. They were advised to permit growing of cereal crops or cotton, Sugarcane etc. The instructions have been circulated to the concerned departments by Environment Department on 7th September, 1993 and the officers of the Public Health Engineering Department as well the municipalities are making sincere efforts for its implementation.

In the next financial year, when the sullage water is auctioned for use for irrigation, the agreement will have a dominant clause strictly prohibiting the use of sewerage for growing vegetables and any consumer violating these orders will be dealt with under the Law.

I share the concern of Shri Amir Chand Makkar, Member, Vidhan Sabha on this issue and assure the House and the Members that Government is aware of this problem and will make fullest efforts to implement the decision of the State Environment Protection Council, Haryana, in imposing a ban on use of sewerage water for growth of vegetables and fruits.

श्री श्रीमती ज्ञानदत्त मन्कड : स्पीकर सर, जैसाकि अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि करनाल अमनातनगर इत्यादि 5-6 नगरों में इन स्कीमों को चालू किया जा रहा है। इन्होंने यह भी बताया है कि कुछ नगरपालिकाएँ हरियाणा में ऐसी हैं जो फल व सब्जियों की फसल में गंदे पानी का इस्तेमाल कर रही हैं, उन नगरपालिकाओं का नाम मंत्री महोदय ने नहीं बताया है। सब्जियों में गंदे पानी के इस्तेमाल की वजह से आज कैंसर जैसी बीमारियाँ आम हो गई हैं, हर खाने वाला चीज में इसके क्रीटाणु प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ तक कि दूध देने वाले पशु को भी ये सब्जियाँ खिला दी जाएँ तो उसके दूध में प्रवेश कर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री श्रीमती ज्ञानदत्त मन्कड : स्पीकर सर, मंत्री जी ने जितने छः नगरपालिकाओं के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर बाकी सारी नगरपालिकाएँ ऐसे पानी का इस्तेमाल कर रही हैं। उन नगरपालिकाओं के नाम क्या हैं तथा कब तक गंदे पानी का प्रयोग रोक पाएँगे, यह बताने की कृपा करें? फाइनेंशियल दिक्कत तो आपने बताई है, लेकिन लोगों की सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है।

श्री राम पाल सिंह कंवर : अध्यक्ष महोदय, यह काम सीवरेज और अर्बन वाटर सप्लाई का हमें थोड़ा समय पहले ही सीपा गया है। फिर भी इन्होंने यह पूछा है कि कितनी म्युनिस्पल कमेटियाँ ने इस गंदे पानी को आक्शन करके देखा है। तो मैं इनको इस बारे में बताना चाहता हूँ कि रोहतक म्युनिस्पल कमिटी की अपनी जमीन है और उसको पानी देने के लिये म्युनिस्पल कमिटी ने इस पानी को आक्शन किया हुआ है ताकि उस जमीन पर खेती की जा सके। इसी तरह से हाँसी म्युनिस्पल कमिटी ने भी खेती के लिये इस पानी को आक्शन किया हुआ है। भिवानी म्युनिस्पल कमिटी की भी अपनी जमीन है और उसने भी अपनी जमीन पर खेती करने के लिये इस पानी को आक्शन किया हुआ है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने, सिर्फ एक छठराँवी म्युनिस्पल कमिटी ऐसी है, जिसको आक्शन किया है। इसके अलावा नारनौल की म्युनिस्पल कमिटी ने भी इस पानी को आक्शन किया हुआ है। इसके अलावा मेरे साथी ने दूसरा सवाल यह किया है कि पिछले 6-7-8 सालों से ऐसा क्यों किया जा रहा है। मैं आनरेबल मँबर की इन्फॉर्मेशन के लिये यह बता दूँ कि एक मिलीलीटर पानी को ट्रीट करने के लिये 15 लाख रुपया खर्च आता है। इतना धन हमारे पास इस वक्त नहीं है कि हम सारी की सारी म्युनिस्पल कमिटी के लिये ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा सकें। जैसे कि मैंने पहले भी इनको आक्शन दिया है, अब भी मैं इनको यह आश्वासन दूँगा कि यह काम चूँकि अब हमारे पास आ गया है इसलिए जब हम आईन्दा साल के लिये आक्शन करेंगे तो गवर्नर साहब ने जो फँसला किया है, उसको हम एग्जीक्यूटिव में डाल कर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आईन्दा के लिये यह पानी फ्रूट्स और वीजीटेबल्स पैदा करने के लिये इस्तेमाल न किया जाये।

श्री श्रीराम चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि कितनी नगरपालिकाएं इस पानी को अपनी जमीन में बैजीटेबल और फ्रूट्स लगाने के लिये इस्तेमाल कर रही हैं और कितनी फार्स्ट्स के लिये इस्तेमाल कर रही हैं ?

श्री राम पाल सिंह कंवर : यह पानी किसी भी म्युनिस्पल कमेटी ने सफेदे के लिये इस्तेमाल करने के लिये नहीं दिया है लेकिन इस पानी से लोग बैजीटेबल और फ्रूट्स न उगायें, बल्कि इससे चारा उगायें, काटन की खेती करें, गेहूं की खेती करें या ऐसी किसी चीज की खेती करें जो नुक्सानदेह साबित न हो, ऐसा हम कोशिश करते रहे हैं। जैसे मैंने कहा है, 31 मार्च के बाद जब पिछला आक्शन पीरियड खत्म हो जायेगा, तब हम जो अगला आक्शन करेंगे, उस समय एग्जीक्यूटिव में यह जरूर डालेंगे कि इस पानी का इस्तेमाल फ्रूट्स और बैजीटेबल की खेती के लिये न करें।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, सब्जियां गन्दे पानी में नहीं उगायी जानी चाहियें, ऐसा करना बहुत ज्यादा नुक्सानदेह है। इस बारे में मंत्री जी बतायें उन्होंने क्या स्टेप्स लिये हैं ?

श्री राम पाल सिंह कंवर : स्पीकर साहब, म्युनिस्पल कमेटी की जमीन में गन्दा पानी देने के लिये आक्शन अभी नहीं हुई है, यह तो पहले की हुई है। मैंने अभी यह अश्वोर किया है कि आईन्दा हम जो एग्जीक्यूटिव करेंगे, उसमें यह चीज डालने जा रहे हैं कि यह पानी सब्जियों-फलों के लिए प्रयोग न करें। जो व्यक्ति इसकी वाय-लेशन करेगा और इससे फ्रूट्स और बैजीटेबल उगायेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे और उसका एग्जीक्यूटिव कौंसिल किया जायेगा।

वर्ष 1994-95 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now general discussion on the Budget estimates for the year 1994-95 will be resumed. Shri Amir Chand Makkar was on his legs when it adjourned. He may resume his speech.

श्री श्रीराम चन्द मक्कड़ (हांसी) : स्पीकर साहब, हमारे वित्त मंत्री गुप्ता जी ने इस हाउस में जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आज प्रदेश के अन्दर विकास कार्य हो रहे हैं। ग्रामीण विकास कार्य चल रहे हैं। जब से यह सरकार बनी है, तभी से चारों तरफ विकास के काम चल रहे हैं। गांव में जहाँ दूसरे विकास के काम हुए हैं, वहाँ गांवों में स्कूल और अस्पताल भी खुले हैं, और खालें भी बनाई गयी हैं। कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण भाइयों की भलाई के लिये जितने काम हुए हैं, उनसे ग्रामीण इलाके के लोगों को काम भी

मिले हैं और उनका भला भी हुआ है। ऐसे काम इस सरकार ने शुरू किये हैं, मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वे भाई बड़ा शोर करते हैं। स्पीकर साहब, मेरे हल्के में बांडाहेडो एक गांव है। वहां पर साबिक चीफ मिनिस्टर के बहुत रिश्तेदार रहते हैं। वहां पर गांव वालों ने 26 कमरे स्कूल के लिए बनाकर दिए जिससे कि वहां पर स्कूल खुल सके। वे दो बार तो चौधरी देवी लाल को स्कूल मंजूर कराने का ऐलान करने के लिए ले गए और एक बार चौधरी श्रीम प्रकाश चौटाला को ले गए। तीनों बार वहां के लोगों ने लड्डू बांट दिए कि स्कूल मंजूर हो गया लेकिन हालत यह थी कि वहां पर एक क्लास का भी स्कूल मंजूर नहीं हुआ। उसके बाद वहां के लोगों ने मुझे अपना तुमाइन्दा चुना। गांव वालों ने मुझे स्कूल के बारे में बताया तो मैं वहां से श्रीमती शान्ति राठी को ले गया वे हमारी शिक्षा मन्त्री थीं। इन्होंने वहां स्कूल मंजूर होने का ऐलान किया और कहा कि एक हफ्ते के अन्दर मास्टर इस स्कूल में आ जाएंगे और इन्होंने वास्तव में ही एक हफ्ते में मास्टर वहां पर भिजवा दिए। वहां के लोगों की हैरानी हुई कि लोग यहां दावा करते थे कि चीफ मिनिस्टर उनके रिश्तेदार हैं लेकिन उन्होंने वहां पर एक स्कूल भी मंजूर नहीं किया। स्पीकर साहब, आज वह स्कूल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। स्पीकर साहब, आज हालत यह है कि हर गांव में विकास के कार्य हो रहे हैं। उसी गांव बांडाहेडो में एक-एक फुट पानी खड़ा रहता था। मैंने जब यह हालत देखी तो गांव वालों को कहा कि क्या पिछले चार साल में कोई सरकार नहीं थी जो विकास कार्य करती। आज हालत यह है कि जो विकास के कार्य अधूरे रह गए थे, इस सरकार ने वे सारे विकास कार्य पूरे किए हैं। वहां पर एक शीसर हाजमपुर गांव है जिसमें विकास कार्य अधूरे रह गए थे लेकिन इस सरकार ने आते ही सारे अधूरे काम पूरे किए। इसी तरह से कोठी मंगल खां और उमरा गांव हैं वहां पर काफी विकास कार्य किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, बजट में बताया गया है कि सिंचाई के क्षेत्र में खालों को पक्का करके पानी की बचत की जा रही है। रजवाहों को पक्का करके भी पानी बचाया जा रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अलखपुरा माइनर है, उसको चालू किया जाए। स्पीकर साहब अलखपुरा माइनर पर केवल दो लाख रुपया खर्च करके टेल पर पानी पहुंच सकता है। वहां पर एक डिपेल माइनर है, इसकी टेल को आगे बढ़ाया जाए। हमारे भाई बड़ा शोर करते हैं कि पानी देने में इंसाफ नहीं किया जा रहा है। स्पीकर साहब, जब पानी देने का प्रावधान किया गया था तो उस वक्त उन इलाकों के भाईयों ने ही पानी का प्रावधान किया था लेकिन आज वही लोग शोर मचा रहे हैं कि पानी का बंटवारा एकसा नहीं किया जा रहा है। यह बात ठीक है कि हांसी भी पानी से प्रभावित है और एस० ब्राई० एल० के बनने के बाद ही हमारे इलाके में पानी आ पाएगा लेकिन शोर मचाने से तो कोई फायदा नहीं है। स्पीकर साहब, वहां पर बिजली के बारे में भी काफी शोर मचाया जा रहा है कि बिजली की कमी है। स्पीकर साहब, हमारी कमेटी भाखड़ा गई थी। हमारी कमेटी ने वहां सारा इन्स्पेक्शन किया था। हमने देखा कि भाखड़ा में पानी का लेवल काफी

[श्री श्रीमती चन्द मक्कड़]

नीचे चला गया है और वहाँ पर केवल दो मशीनें ही काम कर रही थीं। अध्यक्ष महोदय, अखबारों में भी यह छपा कि हरियाणा में बिजली की इतनी कमी है कि हरियाणा अन्धेरे में डूब जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने कोशिश करके जहाँ से भी बिजली मिल सकती थी, मंहगे भाव पर बिजली खरीदी और आज हासिल यह है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली यह सरकार दे रही है। (इस समय सभापतियों की सूची के एक सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह पदासीन हुए।) यह बहुत अच्छी बात है। चैयरमैन साहब, जहाँ तक कानून एवं व्यवस्था की बात है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब से यह सरकार बनी है, हरियाणा के अन्दर पुरी तरह से अमन है। न किसी प्लाट पर कब्जा, न किसी की दुकान पर कब्जा, कहीं भी कोई कब्जा नहीं है। अभी जैसे मदान साहब और सम्पत सिंह जी आपस में प्लाट के सौदे में उलझ रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे यह विधानसभा न होकर, किसी प्लाट के सौदे की दुकान हो। चैयरमैन साहब, मैं एक बात चौधरी सम्पत सिंह जी को, जो अपोजीशन के नेता हैं, कहना चाहूँगा कि इनके एक पब्लिक जलसे में चौटाला साहब बोल रहे थे कि भजन लाल सरकार ने फलों कब्जा कर लिया। मैं तो यह कहूँगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूखों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। (शोर)

श्री राम कुमार कटवाल : चैयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है। सर, मक्कड़ साहब चौटाला साहब के बारे में क्या कह रहे हैं? ये सदन में जिस तरह की बातें करते हैं, यह इनकी शोभा नहीं देती। मेरे दिल्लू वाले गांव का लड़का * * * * * (शोर)

श्री सभापति : कटवाल साहब, बैठिये। यह कोई प्वायंट आफ ऑर्डर नहीं है। यह एक्सपन्ज कर दें।

श्री श्रीमती चन्द मक्कड़ : चैयरमैन साहब, तो ये पब्लिक जलसे में बोल रहे थे कि एक किसान ने खड़े होकर यह कहा था कि चौटाला साहब, आपकी नज़रों से कोई प्लाट बचा हुआ है क्या? सभी पर आपने कब्जा कर रखा है, आपने कोई प्लाट छोड़ा ही नहीं है। (शोर) और आप दूसरों की बातें करते हो (शोर) यह चैयरमैन साहब, झूठ नहीं है। एक नौजवान ने इनसे पूछा भी था तो इसका इनके पास कोई जवाब नहीं था।

श्री चौधरी श्रीम प्रकाश बेरी : चैयरमैन साहब, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है कि इस समय बजट पर जनरल डिस्कशन हो रही है और मੈम्बर साहेबान आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये बल्कि सही इशू पर ही बहस होनी चाहिये क्योंकि आज सारे हरियाणा की जनता की नज़रें इस हाउस पर लगी हुई हैं। ये लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हाउस का कीमती समय बरबाद होगा। मेरा कहना यह है कि आपस में आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाये जाने चाहियें।

*चैयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सभापति : बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। करक्टर असेसीनेशन से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है। हाउस में केवल बजट पर ही बोला जाए, यह अच्छी बात है, जो बेरी साहब ने कहा, बिल्कुल सही है। मांगे राम जी ने बड़ी मेहनत के साथ यह बजट बनाया है और मंत्री साहबाने कंस्ट्रक्टिव बहस न करके दूसरी बातें कर रहे हैं।

श्री श्री अमर प्रकाश चौटाला : चैयरमैन साहब, मेरा भी प्वायट आफ आर्डर है। मैं यह बात इसलिये आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि जो बात माननीय सदस्य ने कही है, उस क्षेत्र से आप भी और ये स्वयं भी सम्बन्धित हैं। मुझे यह नहीं समझ में आया कि ये कहना क्या चाहते हैं लेकिन मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं, वह एक सरकारी दौरा ही माना जाता है, बाकायदा दौरे का प्रोग्राम रिकार्ड में होता है। सदस्य भी जानते हैं और आपको भी पता होगा कि अमर प्रकाश मुख्यमंत्री के तौर पर कभी बाँडाहेडी गये भी हैं या नहीं। यह पता नहीं चल रहा कि क्या ये बजट की सराहना कर रहे हैं या फिर सरकार को खुश करके कुछ हासिल करना चाहते हैं या फिर मेरे खिलाफ इलजाम लगाने की उनकी सोच है? इलजाम लगाने से पहले कम से कम इनको यह सोच कर चलना चाहिये कि किसी के खिलाफ अगर कोई अनर्गल बात कही जाएगी तो वह अच्छा नहीं होगा और उसके परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे।

श्री श्री अमर चन्द भक्कड़ : चैयरमैन साहब, चौटाला साहब, धमकी दे रहे हैं। चौटाला साहब की जब सरकार थी तो इन्होंने दो चार मुकदमे मेरे और मेरे बेटों के खिलाफ बनाकर के देख लिया। इसलिये धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। (शोर) चौटाला साहब जो परिणाम होंगे, वह तो हम भुगतेंगे ही। (शोर)

श्री सभापति : भक्कड़ साहब, आप इन बातों पर न जाकर, केवल बजट पर ही बोलें।

श्री श्री अमर चन्द भक्कड़ : ठीक है, चैयरमैन साहब, मैं अब पशुधन के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूँ जिसका प्रावधान बजट में किया गया है। मैं समझता हूँ कि सरकार ऐसा करके बहुत अच्छा कर रही है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस हरियाणा सरकार के कारण ही आज हरियाणा के लोग सारे भारत से अच्छा और सुधरा दूध पीते हैं। 600 ग्राम दूध आज हरियाणा के अन्दर हर व्यक्ति को मिलता है। यह इसलिये कि सरकार पशुओं की देखरेख बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। पशुओं के रखरखाव के लिये हर बड़े गांव में हस्पताल और डिसपेन्सरीया खोलने का सरकार प्रावधान कर रही है और कई खोली भी हैं।

इसी तरह से शिक्षा के बारे में मैं सरकार से मांग करूँगा। जैसे शिक्षा के विस्तार के लिए उन्हें लड़कियों की तकनीकी शिक्षा तथा बी०ए० लेवल की शिक्षा

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

फ्री की है, यह एक बहुत अच्छा काम किया गया है। लेकिन आज जिस हिसाब से हरियाणा में जन संख्या बढ़ रही है, उसी लिहाज से शिक्षा पर पैसा खर्च किया जाए। मेरा निवेदन है कि मेरे हल्के में कालिजों में एम० ए० की कुछ क्लासें शुरू की जाएं ताकि हमारे बच्चों को हांसी से हिसार और भिवानी में पढ़ने के लिए न जाना पड़े। मेरे हल्के में उमरा गांव में लड़कियों का एक मिडल स्कूल है। उसकी पिछली सरकार के समय में हमने कालेज जैसी बिल्डिंग बना दी थी। मेरा निवेदन है कि उस स्कूल को मिडल से हाई किया जाए। इसी तरह से सिलवा गांव के हाई स्कूल को दस जमा दो बना दिया जाए। इसी तरह से मेरे हल्के के कुछ स्कूल प्राइमरी से मिडल किए जाएं। जैसे बांडाहेडो और खरबला का है, इसी तरह से मेरे हल्के ठठरे में एक बहुत पुराना हाई स्कूल है, उसको भी दस जमा दो किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े।

पीने के पानी के बारे में सरकार की मन्शा है कि हर व्यक्ति को पीने के लिए पानी पूरी मात्रा में मिले। हमारी सरकार ने कई जगहों पर 110 लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी देने का आश्वासन दिया है। मैं समझता हूँ कि आज गांव के लोगों के लिए पीने के पानी की कमी है। जन संख्या बढ़ गई है और दो-दो तीन-तीन गांवों को एक ही स्कीम से पानी दिया जा रहा है। मेरे हल्के के गांव सुल्तान पुर हाणी में पानी की कमी है। वहां पर 5-6 हाणियों को एक ही वाटर वर्कस से पानी दिया जा रहा है। अगर वहां पर दूसरा वाटर वर्कस नहीं बनाया जा सकता है तो वूस्टिंग सिस्टम से उनको पानी दिया जाए। इसी तरह से गढ़ी में भी पानी की दिक्कत है। इसी तरह से शहर में भी पानी की काफी दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक नए वाटर वर्कस की जरूरत है। अभी पीछे हमारे मुख्य मन्त्री जी प्रेम नगर गए थे। वहां के लोगों ने इनसे बात की थी कि वहां पर भी पानी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसको भी वाटर वर्कस की स्कीम के साथ जोड़ा जाए। इसके अलावा शहरों में जो हरिजन वस्तियां हैं, उनको भी पीने का पानी देने के लिए कोई सिस्टम बनाया जाए ताकि पीने के पानी की कमी को दूर किया जाए। इसके साथ-साथ सीवरेज की बात यहां पर कई बार चलती है। मैं समझता हूँ कि जब से यह काम पब्लिक हेल्थ के पास आया है, तब से सारे शहरों में इस बारे में काफी शिकायत है। मैं हरियाणा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस महकमे के अफसरान को अच्छी तरह से समझा दें ताकि वे अफसरान लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ न करें। मेरे हांसी शहर में सीवरेज सिस्टम बहुत ही खराब हालत में है। हमारे सी० एम० साहब ने कुछ अफसरान को यहां से भेजा है और वे 7-8 दिन से काम करवा रहे हैं। जब सीवरेज सिस्टम के बारे में शिकायत की गई, तब जा कर यहां से अफसरान को भेजा गया है। हमारे सी० एम० साहब ने इस महकमे के अफसरान को धमकाया, उसके बाद वे काम पर लगे हैं। यदि

किसी भी शहर का सीवरेज सिस्टम खराब हो जाता है तो बीमारी फैलती है। सरकार से प्रार्थना है कि हांसी शहर के सीवरेज सिस्टम को जल्दी से जल्दी ठीक कराए ताकि लोगों की सेहत खराब न हो।

श्री समापति : मन्कड़ साहब, आप वाइड अप करें।

श्री अमीर अन्द मन्कड़ : चेयरमैन साहब, सरकार की तरफ से पढ़े लिखे ग्रामीण नौजवानों को रोजगार देने की स्कीम है। आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बहुत भयंकर है। हमारे प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान नौकरी की तलाश में सड़कों पर फिर रहे हैं। इस बारे में मैं सरकार को एक सुझाव दूंगा कि बच्चों को शुरू से ही तकनीकी शिक्षा दी जाए ताकि बच्चे मैट्रिक पास करने के बाद अपनी कोई इंडस्ट्री लगाए या कोई और कारोबार करे। उसके लिए सरकार निश्चित तौर पर उनकी सहायता भी करे कि जो बेरोजगार बच्चा अपनी कोई इंडस्ट्री लगाए या कोई और कारोबार करे, सबसे पहले उसका माल बिकेगा, बजाय इसके कि वह नौजवान अपना माल कम्पीटीशन में बेचे, उसका माल सबसे पहले बिके। आज सभी पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का प्रावधान नहीं किया जा सकता। हरियाणा एक छोटा सा प्रान्त है, सभी पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा सकती। जब तक बच्चों को शुरू से ही तकनीकी शिक्षा दे कर अपना रोजगार कमाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा, तब तक बेरोजगारी की समस्या बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं। बच्चों को स्कूलों में एक दूनी दो, दो दूनी चार पढ़ाने की बजाय, शुरू से ही तकनीकी शिक्षा देने की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि बच्चे अपना रोजगार कमाने के लिए अपने पांवों पर खड़े हो सकें।

श्री समापति : मन्कड़ साहब आप वाइड अप करें। मेरे पास 4-5 मॅम्बर्ज के नाम और भी हैं जिन्होंने बोलना है। हमारे वित्तमंत्री जो 12.30 बजे जवाब भी देंगे।

श्री अमीर अन्द मन्कड़ : चेयरमैन साहब, मैं एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। सड़कों के बारे में बताया गया है कि सरकार 400 किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाएगी। इस सरकार के बनने से पहले हरियाणा में सड़कों की बहुत बुरी हालत थी लेकिन इस सरकार के बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में सड़कों की रिपेयर बहुत अच्छी तरह से की गई है। चेयरमैन साहब, जैसे बताया गया है कि हरियाणा प्रदेश के हर गांव को सड़क से जोड़ दिया गया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे गांव हैं जिनको सीधा सड़क से जोड़ने पर गांवों की आपस की दूरी बहुत कम ही जाएगी। मेरे हल्के में खरकड़ा गांव से अनाज मंडी, हांसी तक 5 किलोमीटर लम्बी सड़क बननी है, जिसमें से वह सड़क 3 किलोमीटर बन चुकी है, केवल दो किलोमीटर का टुकड़ा रहता है, उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि

[श्री श्रीमती चन्द्रावती] : उस गांव के लोगों को कोई दिक्कत न हो। इसी तरह से एक सड़क मुल्तानपुर से दमाना बनाई जाए ताकि उन गांवों के लोगों को कोई दिक्कत न हो। इस प्रश्नों के साथ चेयरमैन साहब आपका धन्यवाद आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रावती : चेयरमैन साहब, आपका धन्यवाद आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्री० राम बिलास शर्मा : चेयरमैन साहब, मुझे भी बोलने के लिए समय दिया जाए।

श्री सभापति : शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई मॅम्बर बोला ही नहीं है।

श्री० राम बिलास शर्मा : चेयरमैन साहब, बी० जे० पी० बहुत बड़ी पार्टी है इसलिए पहले मुझे बोलने दिया जाए। मेरी तरफ भी ध्यान दिया जाए।

श्री सभापति : आपकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। पहले आप बहन चन्द्रावती को बोलने दें।

श्रीमती चन्द्रावती (लोहा) : चेयरमैन महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसके लिए मैं इन्हे बघाई देती हूँ कि 74.8 करोड़ रुपये का घाटा होते हुए भी कोई नया टैक्स अपने बजट में नहीं लगाया। मैं समझती हूँ कि डिबैल्पमेंट के काम करने के लिए यह जरूरी था कि कई बार घाटे का बजट होते हुए भी बिना टैक्स लगाए बजट पेश करता पड़ता है, इसलिए यह बहुत बड़ी बात है। अगर टैक्स लगाया जाता तो उसका असर आम आदमी पर पड़ता। इन्होंने टैक्स नहीं लगाया इसलिए मैं पुनः इनको इस बात के लिए बघाई देती हूँ।

चेयरमैन महोदय, गवर्नमेंट प्राफ इण्डिया ने जो 73वां प्रमैडमेंट किया है उसके लिए अपने फाईनांस कमिशन तो नियुक्त करने की बात कही है लेकिन उस फाईनांस कमिशन का फण्ड बजट में नहीं रखा, जो कि रखा जाना चाहिए था। मैं समझती हूँ कि इस कमिशन के लिए इस बजट में ही कोई प्रावधान रखा जाना चाहिए था।

चेयरमैन महोदय, मैं दूसरी बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि नैचुरल कलैमिटीज की वजह से भी कई बार बड़े भारी नुकसान हो जाते हैं। पीछे हमारे इलाकों में दादरी और बाढ़डा के गांव अटला, सिसावल और दूसरे कुछ गांवों में पतल आने की वजह से जो बांध वहाँ पर काफी समय से बने हुए थे, उनके रख रखाव न होने के कारण बाढ़ के पानी से टूट गए जिसके कारण इति गांवों को काफी नुकसान हो गया। बांध के टूटने से लोगों की फसलें तबाह हो गईं, यहाँ तक

कि बादल गांव के कुएं भी बाढ़ में बह गए, पता ही नहीं चला कि कुएं कहाँ गए । इसलिए इस बारे में मेरा सरकार को कहना है कि जिन अधिकारियों को बांध का काम देखा चाहिए था, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया । परिणामस्वरूप बाढ़ से नुकसान हो गया । इसलिए मैं चाहती हूँ कि जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये बांध टूटे हैं, उनके खिलाफ भी सरकार कार्यवाही करे । जब बरसात को पानी अधिक आ जाता है तो लोगों को बहुत अधिक परेशानी हो जाती है । यह परेशानी इसलिए अधिक होती है कि जो नैचुरल फ्लो पानी का हो नहीं पाता, वह बाढ़ के कारण आगे बढ़ता रहता है । जब नैचुरल फ्लो खत्म हो जाता है तो सूडकें टूट जाती हैं, नहरें टूट जाती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर भी ऐसी संभावनाएँ हैं, वहाँ पर पानी के बहने का नैचुरल फ्लो का प्रावधान होना चाहिए ताकि नुकसान न हो, क्योंकि सबको व नहरों की वजह से पानी का नैचुरल फ्लो कम हो जाता है ।

चेयरमैन महोदय, गांव में उद्योग कुंज बनाने की जो बात सरकार ने की है, इस बारे में मेरा कहना है कि सरकार का यह बहुत अच्छा फैसला है । इसके साथ ही मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे उद्योग कुंज हर एक जिले में खोले जाने चाहिए कि कुछ जिलों में । हमारे लोहाह, दादरी, बाबड़ा, भिवानी आदि जिलों में भी सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि जितने छोटे छोटे उद्योग होंगे, उतने ही लोगों को अधिक काम मिलेगा । जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं, वहाँ पर बेरोजगारी ज्यादा है । इसलिए मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज की तरफ अधिक ध्यान दिया जाये ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके । जैसे बिहार में या बंगाल में बड़े बड़े उद्योग हैं लेकिन वहाँ पर ज्यादा गरीबी है बनाये पंजाब और हरियाणा के, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज ज्यादा है जिस के कारण लोगों को अधिक रोजगार मिल पाता है । इन छोटे उद्योगों में कम्प्यूमर्ज आईटमज भी बड़ी इण्डस्ट्रीज के मुकाबले में सस्ते होते हैं । चौधरी चरण सिंह जी ने जो इकोनॉमिक्स पर एक बुक लिखी थी "समाल इज ब्यूटिफुल", वह ठीक लिखी थी । इस पुस्तक को सारे विश्व में सराहा गया था । इसलिए सरकार को अधिक से अधिक छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके ।

चेयरमैन महोदय, हमारे इलाके लोहाह में टेक्निकल एजुकेशन की बहुत भारी कमी है । अगर प्र-कॉपीटा के हिसाब से देखें तो गवर्नमेंट सचिस में लोहाह के कम बच्चे जा पाते हैं । मेरे हल्के में स्कूल कम हैं, पॉलिटेक्नीक ही नहीं और एक आई०टी०आई० है जिसमें सिर्फ दर्जी का एक ही ट्रेड है । इसलिए इस आई०टी०आई० से ट्रेडज बढ़ाना भी जरूरी है । सभापति महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि जो आई०टी०आई० है, उसकी बिल्डिंग ठीक प्रकार से बने, एक पॉलिटेक्नीक कालेज भी खुलना चाहिए और इसी

[श्रीमती चन्द्रावती]

प्रकार और स्कूल भी वहाँ खोले जाएं ताकि बच्चों की शिक्षा अच्छी और ज्यादा मिल सके क्योंकि यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, अब मैं पानी के बारे में कहना चाहती हूँ। हरिशेखर के लिए बोरिंग वैलज बहुत ही जरूरी है। बोरिंग वैलज और एम0आई0टी0वी0 के कन्सर्टेड आफिसर्स तो मिलते ही नहीं, पता नहीं वह कहां बैठते हैं। बोरिंग वैलज जब खराब हो जाते हैं तो उनको कोई ठीक करने ही नहीं आता यह बहुत ही जरूरी चीज है। मैंने सुना है कि इसको बाईंड अप करने जा रहे हैं। सभापति जी, मैं सरकार से कहना चाहती हूँ और यह बहुत ही जरूरी चीज है कि इसको बाईंड-अप नहीं करना चाहिए। जहाँ पर मीठा पानी है, वहाँ पर ये बोरिंग कर के कुएँ लगा सकते हैं और जब कुएँ खराब हों तो उनको भाँव वाले ठीक नहीं कर सकते। इसलिए इन लोगों के द्वारा कुओं को ठीक करवाने का काम भी करवाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहती हूँ। हमारे प्रदेश में एग्रीकल्चर की काफी तरक्की हुई है लेकिन सभापति महोदय, कैमिकल खाद से बहुत नुकसान हो रहा है। एक सर्वे के जवाब में बताया गया था कि कैमिकल खाद से नुकसान होता है। सभापति महोदय, मैं तो कहती हूँ कि कैमिकल खाद बनाने वाले जो कारखाने हैं, उनको बन्द कर देना चाहिए, मैं कैमिकल खाद इस्तेमाल करने के खिलाफ हूँ। मेरे चाचा रामपत जी हैं, वह कभी भी अपने खेत में कैमिकल खाद नहीं डालते, बिजलीवास उनका गाँव है। गेहूँ में आज तक कोई आल नहीं रहता, यह देखना चाहिए कैमिकल खाद की वजह से इतना ज्यादा खरपतवार उगता है, यह क्यों उगता है, क्या कैमिकल खाद में कोई कमी है जिसकी वजह से यह ज्यादा उगता है? इस खाद में खरपतवार का बीज नहीं मिलाया जाता, इसलिए इस बात की कोई न कोई रिसर्च होनी चाहिए। इस बारे में जो प्रैक्टिकल फार्मर्स हैं, उनसे मदद लेनी चाहिए या हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से इस बात की खोज करवानी चाहिए कि कैमिकल खाद डालने से ज्यादा खरपतवार क्यों पैदा होता है? जहाँ कैमिकल खाद नहीं डाली जाती, वहाँ यह ज्यादा नहीं उगता। जैसे पहले अमरीका से पी0एल0480 गेहूँ मंगवाया था, उसके साथ ही कांग्रेस वास का बीज भी भारत में आ गया। (विष्णु) खरपतवार को जो बीज बढ़ाती है, उसको देखा जाना चाहिए और विदेशों से जो मंगवाया जाता है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है, कहीं कोई दूसरी चीज तो साथ में नहीं आ गई? यह देखा जाना चाहिए कि पैस्टिसाइड्स और विडीसाइड्स की वजह से कैसे ज्यादा होता है। जब एक जानवर मरता है, उससे इन्सान को भी बहुत नुकसान होता है। सभापति महोदय, मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि पैस्टिसाइड्स और विडीसाइड्स सब बन्द कर देने चाहिए और जो नैचुरल चीजें हैं, उन पर ज्यादा डिपेंड करना चाहिए। परिन्दे ज्यादा कीड़े खाते हैं। गन्ने को जो कीड़ा लगता है, परिन्दे उसको गन्ने के अन्दर से बाहर खींच

लाते हैं। पैस्टिसाईडज और त्रिडिसाईडज के इस्तेमाल से परिन्दे भी मर जाते हैं जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। परिन्दे कीड़े-मकोड़ों को खा कर फसल की रक्षा करते हैं, फसलों के लिए इससे कोई अच्छी चीज नहीं है।

श्री सतवीर सिंह कादयान : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

* * * * * (विष्ण)

श्री सभापति : कादयान साहब, आपकी बात ठीक टेस्ट की नहीं है इसलिए आप बैठिए। कादयान साहब, मैं जो कहा है वह रिकार्ड न किया जाए। (विष्ण)

श्रीमती चन्द्रावती : चैयरमैन साहब, अब मैं फॉरेस्ट के बारे में कहना चाहती। चैयरमैन साहब, फॉरेस्ट सिर्फ शुद्ध हवा के लिए ही नहीं बल्कि और भी कई काम आते हैं। अगर यमुना और भारकन्डा नदी के दो-दो किलोमीटर तक पेड़ लगा दिए जाएं तो बाढ़ कम आएगी। मैं कीकर और सफेदे को ना-पसन्द करती हूँ। यह बात ठीक है कि कीकर की लकड़ों जलाने के काम आती है। चैयरमैन साहब, आज गांव में जिनके पास जमीन नहीं और जो छोटे-छोटे किसान हैं, आज उन्हें बहुत ही मुश्किल से लकड़ी मिलती है और जो मिलती है, वह भी गीली मिलती है। मैं तो यह कहती हूँ कि उनके लिए गैस के चूल्हों का इन्तजाम होना चाहिए। अगर यह सबके लिए नहीं हो सकता तो उनके लिए चूल्हे जलाने की लकड़ी होनी चाहिए। आज उनको जहाँ पर लकड़ी मिलती है, वे गांवों में काट लाते हैं। चैयरमैन साहब, जहाँ पर खाली जगह है, वहाँ पेड़ लगाने चाहिए। इसी तरह से नदियों का पानी इकट्ठा करने लिए जोहड़ों को नहीं रखा गया है। चैयरमैन साहब, यह बहुत ही जरूरी है कि कुओं के लिए जोहड़ों में पानी रखना चाहिए ताकि कुओं में पानी आता रहे। आज पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं मिलता है। मैं तो यह कहती हूँ कि जोहड़ों के लिए दोबारा बजट बनना चाहिए।

चैयरमैन साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में एक बात कहना चाहती हूँ। आज मेरे हल्के में स्कूलों की बहुत ही कमी है। आज लड़कियों के पढ़ने के लिए लोहार, बहल और डिगावा में कोई स्कूल नहीं है। सिधड़ावा, जो मेरे हल्के में सबसे बड़ा गांव है, वहाँ पर मुख्यमन्त्री जी अनाऊंस करके आए थे कि वहाँ हाई स्कूल होना चाहिए। काकरौली और बाढ़ड़ा में लड़कियों के स्कूल की बिल्डिंग तैयार है, वहाँ पर दस-जमा दो का स्कूल होना चाहिए। बिसलवास और काजुवा में प्राईमरी से मिडिल स्कूल होना चाहिए। इसी तरह से मेरे हल्के अन्दर में दस जमा दो का स्कूल होना चाहिए। चैयरमैन साहब, जितने भी हाई स्कूल हैं, उनको 10 जमा दो कर देना चाहिए। यदि ऐसा कर दिया तो यह बहुत ही अच्छा होगा और आज

*चैयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्रीमती चन्द्रावती]

बच्चों को शहरों में जाना पड़ता है वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ बच्चों को बसों में जाने के लिए जो फी पास दिए गए हैं, उसको बन्द कर देना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। उनके लिए स्कूल की ही बस होनी चाहिए। (विष्णु) चेयरमैन सर, इन फी पासों से बच्चे बिगड़ते हैं और उनकी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं होती। इसलिए सरकार को उनके लिए स्पेशल बसिज चलानी चाहिए (विष्णु) मुझे इसलिए तकलीफ है क्योंकि सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। चेयरमैन साहब, लड़कियों और लड़कों के लिए वॉर्डिंग हाऊस होने चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी होनी चाहिए और लाइब्रेरी भी एयर कंडीशन्ड होनी चाहिए ताकि बच्चे वहाँ पर आसाम से कैंटेकर पढ़ सकें। मैंने देखा है कि सदियों में बच्चे एक एक कर्मिज ही पहन कर पढ़ने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोट सिलावे के लिए पैसे नहीं होते और न ही वे शर्म की वजह से बदर वगैरह ओढ़ कर आते हैं जिसकी वजह से उनको ठंड भी लगती है, इसलिए मेरी सरकार से सिफारिश है कि उनके लिए एयर कंडीशन्ड लाइब्रेरी होनी चाहिए। यह स्कूल और कालेज दोनों में होनी चाहिए।

श्री सभापति : चन्द्रावती जी, अब आप वाइन्ड अप करें।

श्रीमती चन्द्रावती : सर, मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगी। चेयरमैन साहब, हुड्डा इसलिए बना था (विष्णु)

श्री सभापति : यह आपको डिस्टर्ब करने में इसलिए इन्टरेस्ट है ताकि आपको कोई अच्छी बात रिकार्ड पर न आ जाए।

श्रीमती चन्द्रावती : चेयरमैन सर, हुड्डा इसलिए बना था कि जो प्राइवेट कालोनाइजर थे, वे किसानों की जमीन ऐक्वायर करते थे और उसको सस्ते दामों पर ले लेते थे। इस चीज को रोकने के लिए हुड्डा का गठन किया गया था लेकिन यह अपने मकसद को पाने में असफल रहा। सरकार इसको ठीक करे। चेयरमैन सर, आज आबादी बहुत बढ़ रही है और गाँवों से शहरों की तरफ लोग आ रहे हैं ताकि उनके बच्चे यहाँ पर ठीक ठाक पढ़ सकें लेकिन शहरों में सीवरेज की कोई सुविधा नहीं होती, चाहे वह रोहतक हो, अम्बाला हो या फिर छोटा शहर दादरी हो। इसलिए मैं सरकार से सिफारिश करूंगी कि वह यहाँ पर सीवरेज सिस्टम को ठीक करे। पानी खड़ा रहता है जिसकी वजह से रूग्ण होती है और कई बीमारियाँ फैलती हैं। कई डान्कर्स की दुकानें इसलिए खुल गयी हैं क्योंकि गाँवों की वजह से बहुत मच्छर मक्खी पैदा होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार को यह सारा काम करना चाहिए।

डा० राम प्रकाश : चैयरमैन साहब, मुझे भी बोलने का समय मिलना चाहिए। अभी काँग्रेस की तरफ से केवल चन्द्रावती जी ही बोली हैं इसलिए आप यह बताएं कि क्या आज मेरा भी नम्बर बोलने के लिए आएगा ?

Mr. Chairman : Ram Parkash Ji, I assure you, you will get the chance to speak. Chandrawati Ji, you please wind up.

श्रीमती चन्द्रावती : सर, मैं आंगनवाड़ी के बारे में थोड़ा और कहना चाहती हूँ। आंगनवाड़ी की जो लड़कियाँ हैं अगर सरकार उनकी तनख्वाह और बढ़ा दे तो बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही साथ आंगनवाड़ी का सुपरविजन करे, सरकार की तरफ से थोड़ा-सा पैसा भी होना चाहिए। क्योंकि जो पैसा आता है या जो चीजें दी जाती हैं, वह कई बार उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती जिसके लिए वह आती है। मैंने एक जगह बताया है कि किसी सुपरवाइजर के घर पर खिलाने बिखरे पड़े हैं। आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए जो खिलाने आते हैं, वे उन्हें न देकर अपने घर पर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी मैंने सुना है कि आंगनवाड़ी में बच्चों को बना-बनाया भोजन दिया जाता है, यह बहुत अच्छा काम है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट में जो कर्पस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ मॉनिटरिंग होनी चाहिए।

श्री श्रीमती श्रीम प्रकाश बेरी : चैयरमैन साहब, बोलने वालों की लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं ? मैं गवर्नर ऐड्रेस पर भी नहीं बोला हूँ।

श्री सभापति : बेरी साहब, आपका नाम लिस्ट में है और आपको बोलने का मौका जरूर दिया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : चैयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वित्त मन्त्री जी ने सदन में जो बजट पेश किया है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूँ। चैयरमैन साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हरियाणा के लोगों ने 1991 में जब सरकार बनी थी तब इस सरकार से काफी उम्मीदें लगाई थीं, लोगों को ऐसा नजर आ रहा था कि ये सरकार लोगों की भलाई के बारे में सोचेगी लेकिन पिछले दिनों जो बजट पेश हुआ, उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि सरकार लोगों की भलाई के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं है। एक तरह से लोगों की भावनाओं का सजाक उड़ाया गया है। मैं मोटे तौर पर कहना कि वित्त मन्त्री जी ने शहरी और ग्रामीण विकास के बारे में जो चर्चा की है, आप भली भाँति जानते हैं कि इस देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसी हुई है। गांवों में रहने वाले लोगों की सुविधाओं के प्रति यह सरकार अनदेखापन कर रही है। आज आप किसी भी शहर में जाएं, वहाँ जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है। मैं कहता हूँ कि अगर सरकार गांव के विकास की तरफ ध्यान दे तो जो लोग शहर

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

की तरफ भाग रहे हैं, उसमें कमी आएगी। ग्रामीण विकास के लिए मात्र 74.97 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है जो कम है, इसकी राशि बढ़ाई जानी चाहिए। अभी हुड्डा महकमे के बारे में चर्चा चल रही थी। सरकार हुड्डा महकमे पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हुड्डा के माध्यम से जो सैक्टर डिवेलप किए जा रहे हैं, उनमें इस प्रदेश के केवल 30 प्रतिशत लोग प्लाट लेकर मकान बनाते हैं, इनमें 70 प्रतिशत दिल्ली के या दूसरे प्रदेश के और एन०आर०आई० के हैं। इनके लोग इन सैक्टरों में आकर बसते हैं और हरियाणा सरकार उन पर व्यर्थ पैसा खर्च करती है। हरियाणा सरकार गांवों के विकास की तरफ ध्यान दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग गांवों से निराश होकर शहरों की ओर भाग रहे हैं, उसमें कमी आएगी। इसके अलावा, जो बड़े-बड़े गांव हैं, उनमें शौचालय की बहुत कमी है, इस बारे में बजट में स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान नहीं है। गांव की बहन बेटियों को शौचालय के लिए कई-कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर सरकार गांवों का विकास चाहती है तो बड़े-बड़े गांवों में कुछ जमीन एकत्र करके सुलभ शौचालय बनाने होंगे और दूसरी अथ सुविधाएं, जैसे चौपाल इत्यादि हैं, उनका निर्माण दोबारा से करना होगा। (इस समय समापतियों की सूची के एक सदस्य श्री मनी राम केहरवाला पयासीन हुए।) इन्होंने बजट में सिचाई के बारे में बात की है। बजट में यह कहा गया है कि जिस जमीन में खारा पानी है, उस जमीन के खारे पानी को सीठे पानी में तबदील करने के लिये एक स्कीम चलायी गयी है। मुझे यह कहते हुए बड़ा ही दुःख हो रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा खारा पानी अगर कहीं पर है तो वह जिला फरीदाबाद में है। लेकिन फरीदाबाद जिले को खारे पानी की उस स्कीम के तहत नहीं लिया गया है। हमारे फरीदाबाद जिले के लोग पीने के पानी के लिये तरसते हैं। उस स्कीम में फरीदाबाद जिले को अगर शामिल करते तो वहां के लोगों का भी कुछ भला होता और गांवों के लोगों को पीने का पानी मिल जाता जिस के लिए लोग तरसते हैं। इसके अलावा, जैसे थोड़ी देर पहले नहरों के बारे में कहा गया है, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस सदन में और राजनीतिक जलसों में जब कभी बात होगी या एस०आई०एल० की बात होती है तो उसमें फरीदाबाद और गुड़गाँवा का नाम नहीं लिया जाता। हम फरीदाबाद और गुड़गाँवा के निवासी भी हरियाणा प्रदेश का हिस्सा हैं लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा ही दुःख हो रहा है कि आगरा नहर के कन्ट्रोल को अपने हाथ में लेने के बारे में सरकार कतई गम्भीरता से काम नहीं कर रही है। जब आगरा कौन्सिल का कन्ट्रोल हमारे हाथ में आ जायेगा तो हमारे इलाके का भला हो सकेगा। इसलिये या तो आप आगरा नहर का कन्ट्रोल तुरन्त अपने हाथ में लें या फिर नहर में पानी की मात्रा में हरियाणा का हिस्सा बढ़वायें। मेरा कहना यह है कि फरीदाबाद

और गुडगावा की प्यासी जमीन को पानी दिया जाये। इसके लिये सरकार हवा में बात न करके कुछ प्रविटकल बात करे।

श्री सभापति : दलाल साहब, आप बजट पर ही बोलें, इधर-उधर की बात न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन सर, मैं हरियाणा के बजट पर ही बोल रहा हूँ। आज हरियाणा के अन्दर फिजूल बातों पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। ग्रीन बेल्ट के नाम से पहले तो हुड्डा द्वारा जमीन को छोड़ा जाता है लेकिन बाद में उसी जमीन में से डिस्कोशनरी कोटे के नाम पर प्लाट्स अपने-अपने आदमियों को अलग-अलग किये जाते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि किस वर्ग की यह भलाई की बात सोच रही है? यह तो केवल उच्च वर्ग या पैसे वालों के बारे में सोचती है। गुडगावा और फरीदाबाद में कितने ही ऐसे उद्योगपति हैं, जिनको कालोनीज बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ताकि वह वहाँ पर बड़े-बड़े नगर स्थापित करें। चेयरमैन साहब, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। यँभी आपको यह जानकर ताँजुब होगा कि इनकी आबादी कम होती जा रही है। इन नगरों को बसाने में केवल चन्द लोगों को छोड़कर, किसी की भलाई नहीं होगी। सरकार भी वहाँ पर अन्वयधुन्य पैसा खर्च करने में लगी हुई है। आप खुद ही देखिये, इससे क्या लोगों का भला हो रहा है?

चेयरमैन साहब, इसके अलावा यहाँ पर टूरिजम की बात भी आयी है। यह टूरिजम हरियाणा, अब हरियाणा का नाम आगे बढ़ाने के लिये नहीं रहा है। कोई समय था जब हरियाणा टूरिजम का नाम लोगों के मनो में था लेकिन अब वह बात नहीं है। आज चेयरमैन साहब, इस हरियाणा टूरिजम के बड़े-बड़े होटल इस प्रदेश के बड़े-बड़े अफसरों के, मुख्य मन्त्री के या दूसरे बड़ों के रिश्तेदारियों की साँठ-गाँठ के लिये रह गये हैं। आज इनमें परिवार के रिश्ते-नाते, शादी-ब्याह और दूसरे फंक्शन किये जाते हैं। इसके बारे में वित्त मन्त्री महोदय ने एक बात का बड़ा दावा किया है, बशक पता का लें, वहाँ पर सूरजकुड में हरियाणा टूरिजम का जो "पाँच सितारा" होटल है, उसमें बड़े-बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के शादी-ब्याह या संबन्ध तय होते हैं। चाहे वह अधिकारी या कर्मचारी सीनियर का रहने वाला हो, चाहे चण्डीगढ़ का रहने वाला हो, लेकिन वह ऐसा काम सूरजकुड में करते हैं। ऐसे फंक्शन का बिल जो नौमंजो एक लाख रुपया का आता होता है, वह केवल 10-20 हजार रुपये का ही दिया जाता है। यह सरकार के साथ बड़ा धोखा है।

इसके अलावा इन्होंने होम डिपार्टमेंट के बारे में फिजूल खर्चा दिखाया है, मैं उस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वित्त मन्त्री महोदय को बताता चाहता हूँ कि आज हरियाणा में जंगल का राज है। पुलिस ने हरियाणा में जंगल राज कायम

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

किया हुआ है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने या इनकी मौजूदा सरकार ने इस बारे में जानने की कभी कोशिश की है कि कितनी हरिजन लड़कियों के बलात्कार पुलिस की मिल्की भ्रष्ट से होते हैं या कितने हरिजन या बैकवर्ड क्लासिज के या गरीब लोगों को पुलिस ने नाजायज तरीके से तंग किया है? मुझे एक बात कहते हुए बड़ा शर्म आती है। हमारे जी मौजूदा डी 0 जी 0 पी 0 हरियाणा के हैं, इनके नाम एक मकान तो दिल्ली में है और एक मकान चण्डीगढ़ में है लेकिन इन्होंने आफिसरज मैस पर कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा चेयरमैन साहब, 12:00 बजे | यहां मन्त्री महोदय बैठे हुए हैं। वे अपनी छाती पर हाथ रखकर देखें कि क्या उनको जहरत के हिसाब से कार आदि की सुविधा मिलती है लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा का जो डी 0 जी 0 पी 0 है, उसके पास तीन कारें हैं। एक तो कन्टेसा कार है और दूसरी इससे जो छोटी कार होती है, वह है, और इतना ही नहीं

सिचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, जो आदमी इस सदन का मम्बर नहीं है और अपने आफको डिफेंड नहीं कर सकता, उसका बार बार इस ढंग से नाम लेना ठीक नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं कोई नाम तो नहीं ले रहा हूँ।

चौधरी जगदीश नेहरा : डी 0 जी 0 पी 0 तो हरियाणा में एक ही है। चाहे आप नाम लें या न लें। आप बेमतलब की बातें कह कर क्यों कन्ट्रोवर्सी पैदा करते हैं? अगर आपने कोई सुझाव देना है, तो दीजिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, मेरा तो यह सुझाव है कि जनता का जो पैसा सरकारी खजाने में आता है, उसका चाहे आफिसर है, चाहे मन्त्री है और चाहे विधायक है, कानूनी तौर पर उसका सदुपयोग होना चाहिये और जो ठीक बातें हैं, उन्हीं पर वह पैसा खर्च होना चाहिए। किसी को भी अपनी पोस्ट का दुुरुपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वह मन्त्री है, चाहे वह विधायक है और चाहे वह आफिसर है। चेयरमैन साहब, यह सरकार, सरकार चलाने के अभिप्राय से नहीं बनी हुई है, यह तो टुक यूनियन चलाने के लिये लिए सरकार बनी हुई है। फरीदाबाद में इतनी बड़ी टुक यूनियन है और जो हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं या उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उनको पचास-पचास लाख रुपए की आमदनी वहां से होती है।

चौधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। चेयरमैन साहब, अगर ये कोई सुझाव देना चाहें तो दें। अगर ये बगैर मतलब की कन्ट्रोवर्शियल बात करेंगे तो इनके लिए यह कोई शोभा की बात नहीं है। टुक यूनियन की बात कहना

बगैर मतलब की बात है। मैं अपने फाजिल दोस्त से अर्ज करूंगा कि बगैर मतलब की और बेबुनियाद बात करने का कोई आँचिह्य नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, पिछले से पिछले साल हमारे मुख्य मन्त्री जी ने इसी सदन में बड़े गर्व के साथ यह बात कही थी कि जून 1992 तक हरियाणा की एक-एक सड़क की मरम्मत करा दी जाएगी। चेयरमैन साहब, आप अपने हल्के में जाकर देखें कि सड़कों की क्या हालत है ?

श्री सभापति : आपके हल्के में अगर कोई स्पेसिफिक सड़क हो, जिसकी हालत खराब हो तो डांगी साहब को पर्सनली मिल लेना, आपकी समस्या सुलझ जाएगी। सारे हरियाणा में सड़कों पर बहुत काम हुआ है और सड़कों की हालत काफी अच्छी है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, बजट स्पीच में कोआपरेटिव शूगर मिल्स का जिक्र किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा में कोआपरेटिव शूगर मिल्स बनें लेकिन सरकार की लापरवाही और धींगामस्ती के कारण कुछ ऐसे आफिसर्स इन मिल्स में नियुक्त कर दिए जाते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। चेयरमैन साहब, पलवल में एक शूगर मिल है। वह मिल हरियाणा की बेहतरीन शूगर मिल मानी जाती है। वर्ष 1993 में वहाँ पर एक ऐसा एम0डी0, जिसका नाम रमेश कौशिक था, को लगा दिया गया। उसको काम का कोई तजुर्बा नहीं था और उसने उस मिल का इतनी बेदुर्ती से सत्यानाश किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अपनी धींगामस्ती से इस मिल को सत्यानाश के कगार तक पहुँचा दिया और आज हालत यह है कि जहाँ यह मिल मई, जून तक चला करती थी, वहाँ आज इस मिल के अधिकारी गन्ने के लिए धूम रहे हैं जबकि अभी मार्च भी खत्म नहीं हुआ है। वे अधिकारी आज गन्ने के लिए भागे फिर रहे हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि भविष्य में ऐसे अधिकारी को लगाया जाए जो अपने काम में लापरवाही न करे। इसके अलावा, चेयरमैन साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में ए0एस0आई0 की भर्ती हुई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि * * * यह कितनी खराब बात है।

श्री सभापति : यह रिकार्ड न किया जाए। अब आप बैठ जाएं। आपने बहुत टाइम ले लिया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चेयरमैन साहब, मैं अभी वाइड अप कर रहा हूँ। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें।

श्री सभापति : अब आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : चैयर्मैन साहब, मैं एक दो मिनटों में ही अपनी बात कहकर वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं इस सरकार की कारगुजारी का जिक्र कर रहा था। चैयर्मैन साहब, हरियाणा के अन्दर पटवारियों की भर्ती भी हुई * * * * * (शोर)

श्री सभापति : यह बात रिकार्ड न की जाए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : चैयर्मैन साहब, मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजियेगा। (शोर)

श्री सभापति : दलाल साहब, आप बैठिये। आप यूँ ही ऐसी बातें करके हाउस का समय बरबाद कर रहे हैं। (शोर)

श्री धरम जगदीश नेहरा : चैयर्मैन साहब, ये जो इस तरह की गलत बातें यहाँ पर कह रहे हैं, यह ऐक्सपन्ज होनी चाहिए (शोर) कोई बजट पर बात करें, कोई अपना उचित सुझाव सरकार के सामने रखें तो हम मानेंगे लेकिन बिना मतलब के, बिना किसी मकसद के ऐलोगेशन लगाना उचित नहीं है। (शोर) कोई सुझाव दे या बजट पर कोई फिगर दे, आक्रिडे दे, सरकार की किसी गलती को यहाँ पर बताएँ, तब तो सही है। यूँही इधर उधर की फिजूल बातें करने से इन्हें जरा संकोच करना चाहिए। यह इनको शोभा नहीं देता। (शोर)

दूसरा बेरा, प्वायंट चैयर्मैन साहब, यह है कि जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी अग्रपक्ष महोदय से प्रार्थना की थी कि हर पार्टी को प्रोपोजनेटली, मॅम्बरज की तादाद के लिहाज से बोलने का समय देना चाहिए लेकिन आज आप देख रहे हैं कि चौधरी वंसी लाल जी भी काफी समय तक बोलते हैं और अब इनको बोलते हुए भी बड़ा टाइम हो गया है। हमारी ओर से अभी तक सिर्फ दो मॅम्बर ही बोल पाए हैं। इसलिए आप पार्टी के मॅम्बरान की तादाद के मुताबिक ही मॅम्बरज को बोलने का समय अलाट करें।

आयकारी तथा फ़राधान मंत्री (बहन करतार देवी) : चैयर्मैन साहब, ये विपक्ष के भाई इस तरह से बोल रहे हैं, जैसे अकेले इनको ही जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है और कांग्रेस के सदस्यों को चुनकर जनता ने नहीं भेजा है। मैं इनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हर सदस्य का अपना अपना मान सम्मान है। इस तरह की बातें इन्हें किसी माननीय सदस्य के बारे में नहीं कहनी चाहिए कि सब ने पॅसा ले रखा है। इस तरह से कहना सारे माननीय सदस्यों की बदनामी है। इसलिए मैं चैयर्मैन साहब, यह कहूँगी कि इन शब्दों को सदन की कार्यवाही में से निकाल दिया जाए। इतना ही नहीं, दलाल साहब को इन सभी बातों के लिए सदन के सामने खेद भी प्रकट करना चाहिए।

*चैयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री समापति : मैंने पहले ही इन सारी बातों को रिकार्ड न करने के लिए कह दिया है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह बलाल : चेयरमैन साहब, यह मैं नहीं कह रहा, यह सारे हरियाणा की जनता कह रही है। (शोर)

श्री समापति : कर्ण सिंह जी, आप बजट पर बोल रहे हैं। (शोर) आप मेहरबानी करके बैठिए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह बलाल : हरियाणा की आम जनता के मुँह में ये शब्द हैं कि हरियाणा के सभी * * * * *

श्री समापति : ये शब्द रिकार्ड न किए जाएँ। बलाल साहब, आपसे मेरी रिकवैस्ट है कि आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह बलाल : चेयरमैन साहब, हम सब ने यहाँ हाउस में आकर यह आपस ली थी कि हम ईमानदारी से लोगों के हितों को देखें और भलाई के काम करेंगे, लेकिन यह सरकार अपनी शपथ लेने के बाद कोई अच्छा काम, ईमानदारी का काम नहीं कर रही है। इसलिए इसे हस्तीफा दे देना चाहिए। (शोर)

श्री समापति : आप का समय समाप्त हो गया है, आप बैठिए। (शोर)

डा० राम प्रकाश (थानेसर) : चेयरमैन साहब, हरियाणा के बजट वर्ष 1994-95 पर कहस चल रही है। केन्द्रीय सरकार ने माननीय नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आर्थिक ढाँचे को दुरुस्त बनाने के लिए कुछ कदम उठाए। उनका ध्यान गया है उन संस्थानों की तरफ, जो घाटे में चल रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमें भी ऐसी संस्थानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं कोआपरेटिव शूगर मिल, कैथल के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ष 1991-92 में उसमें 7.81 करोड़ रुपए का घाटा था और 1992-93 में 5.48 करोड़ रुपए का हुआ। कुल मिला कर यह घाटा 13.29 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1991-92 में इसके ग्रीस सीजन दिन 154 थे और 1992-93 में घट कर 111 रह गए। इसके एक्जुअल क्रिशग डेज 1991-92 में 123 थे और 1992-93 में ये केवल 95 रह गए। इसकी रिकवरी पेशो 1991-92 में 8.9 प्रतिशत थी और 1992-93 में 9.3 प्रतिशत थी। ग्रेना जो कटा किया गया, वह 1991-92 में 23.46 लाख क्विंटल था और 1992-93 में 21.17 लाख क्विंटल रह गया। इसी तरह भूना के मिल का घाटा 1991-92 में 5.57 करोड़ रुपए था और 1992-93 में 8.04 करोड़ रुपए था। उसका दो सालों का कुल घाटा 13.61 करोड़ है। उसके 1991-92 में ग्रीस सीजन डेज 178 थे जो 1992-93 में घट कर 95 रह गए।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री 0 राम प्रकाश]

उसकी रिकवरी रेगो 1991-92 में 9.02 प्रतिशत थी और 1992-93 में 9.36 प्रतिशत थी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैथल मिल की 1992-93 में 76.03 प्रतिशत थी और शाहवाव की 156 प्रतिशत थी। मेहम शूगर मिल की स्थिति भी ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि कैथल और भूना के दोनों मिल दो साल घाटे में रहे हैं, ये दोनों सिक हैं। इन्होंने पहले दो सालों में ही पेड-ग्रुप शेयर कैपिटल तथा फ्री रिजर्व को बाईप ऑफ कर दिया है। इन दोनों मिलों का कुल घाटा 26.9 करोड़ रुपया बनता है। मन्ने के अभाव में भविष्य में मिलें और भी कम समय चलेंगी और घाटा बढ़ेगा। दूसरी तरफ हरियाणा में चार और मिल लगाने की बात की जा रही है। एक जिला कुसक्षेत्र में ज्योतिसर के निकट लुहार माजरा में जो परपोज्ड मिल है, उसका और भी असर पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि विभाग द्वारा इन घाटे वाले मिलों को सुधारा जाये और यदि क्लोज डाउन के पक्ष में हैं तो इनको किसी प्राईवेट संस्था के हाथ में दिया जाए तो बेहतर रहेगा। इसके लिए एक कमेटी बना कर फैंसला किया जाए।

चेयरमैन साहब, अब मैं पब्लिक अडरटेकिंगज की एक पालिसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ जो बोनस/एक्स ग्रेजिया/इसैटिक्ज के लिए है। इसको किसी कम्पनी या मिल की फाइनेंशियल परफार्मेंस के साथ जोड़ना चाहिए। जिस संस्था में मुनाफा बेहतर हो, वहां पर तो बोनस दिया जाना चाहिए और जहां पर घाटा हो, वहां नहीं मिलना चाहिए। कोआप्रेटिव शूगर मिल कैथल, भूना तथा मेहम में 1992-93 में क्रमशः 5.47 करोड़ रुपया, 8.04 करोड़ रुपया और 2.82 करोड़ रुपए का घाटा रहा है और ये मिलें केवल तीन महीने तक चलीं। उसके बावजूद भी वहां बोनस दिया गया है। वहां पर दस-सित का अतिरिक्त वेतन दिया गया। मैं समझता हूँ कि यह काम मिल की परफार्मेंस के साथ जोड़ कर करना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक सवाल हरको बैंक के बारे में किया था। उसके उत्तर में मुझे बताया गया कि बैंक के निदेशक-मण्डल के सदस्यों को अढ़ाई लाख रुपए तक कार खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है। सदन के सदस्यों को तो दो लाख रुपए मिलता है और वहां पर अढ़ाई लाख रुपए कर दिया है। आज तक किसी कोआप्रेटिव सैक्टर की संस्था के डायरेक्टरों को कार खरीदने के लिए लोन देने की व्यवस्था नहीं की गई थी। हरको बैंक, कोआप्रेटिव बैंक या कोआप्रेटिव सोसाइटीज को या एम्प्लाइज को अंडर सविस रूज तो कर्जा दे सकता है लेकिन डायरेक्टरों को नहीं दे सकता। इसलिए हरको बैंक को सोच विचार कर काम करना चाहिए। फिर चेयरमैन साहब, हरको बैंक के डायरेक्टरों को उनकी फैंमिलीज के साथ दोरे पर भेज दिया गया। यह भी घाटे का एक कारण है।

श्री समापति : डाक्टर साहब, उसमें ऐसा है कि डायरेक्टर बैंक के खर्च पर गए हैं और उन्होंने अपनी फैंमिली का खर्चा अपने आप दिया है।

डॉ० राम प्रकाश : चैयरमैन साहब, हरद्वीन को पिछले साल 6.83 लाख रुपये का मुनाफा हुआ, उसमें से 1.4 लाख रुपए की एक्स ग्रेडिया पेमेंट कर दी गई। इसी तरह से एच० एस० आई० डॉ० सी० ने अपने कर्मचारियों को 18 दिन की अतिरिक्त तन्खाह और गिफ्ट दिए हैं। एच० एस० एस० आई० सी० ने अपने कर्मचारियों को 15 दिन की अतिरिक्त तन्खाह दी है। एच० एफ० सी० ने भी अपने कर्मचारियों को 18 दिन की अतिरिक्त तन्खाह दी है। इस बारे में मेरी अर्ज है कि जो संस्थाएं घाटे में हैं, उनको इस तरह से बोनस नहीं देना चाहिए। जो संस्थान बोनस देना चाहें उनको उसकी वित्त विभाग से प्रायर एप्रूवल लेनी चाहिए। वित्त विभाग के प्रतिनिधि के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरज पर होने से काम नहीं चला अतः कोई नया काम करना हो तो उसके लिए वित्त विभाग से पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए।

अब मैं बिजली बोर्ड का जिकर करना चाहूंगा। बिजली बोर्ड के बारे में बहुत चर्चा चलती रही है। इस बोर्ड में 31-3-93 तक 1358 करोड़ रुपए का घाटा है। बिजली बोर्ड में हर साल का घाटा 325 करोड़ रुपये है, जिसका मतलब है कि इसे एक दिन में 90 लाख रुपए घाटा होता है। इस पैसे से प्रतिदिन कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें सरकार बना सकती है, यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं। बिजली बोर्ड में लगातार घाटे से बचने के लिये कैपिटल री-स्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। इस बोर्ड की बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। इस के घाटे को पूरा करने के लिए किसानों पर बोझ डालने की बजाये जो दूसरे उपाय हो सकते हों, वे करने चाहिए। उसके घाटे को पूरा करने के डंग सोचने चाहिए। मेरे कुछ सुझाव हैं। एक मैगावाट बिजली पैदा करने के लिये राष्ट्रीय औसत 4 कर्मचारियों की है जबकि हरियाणा बिजली बोर्ड में 6 कर्मचारी कार्यरत हैं। हरियाणा बिजली बोर्ड में 863 मैगावाट बिजली पैदा करने के लिये 50 हजार पद हैं और 45 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। बी० बी० एम० बी० में 2706 मैगावाट बिजली पैदा करने के लिये 16500 कर्मचारी कार्यरत हैं यानि हरियाणा बिजली बोर्ड में बी० बी० एम० बी० से तीन गुणा कर्मचारी ज्यादा हैं और बिजली का उत्पादन एक तिहाई है। बी० बी० एम० बी० में तीन गुणा ज्यादा बिजली का उत्पादन है। मेरा कहना है कि इस पर नजर रखी जानी चाहिए। बिजली बोर्ड का 190 करोड़ रुपया केवल कर्मचारियों/अधिकारियों की तन्खाह पर खर्च हो रहा है। हरियाणा बिजली बोर्ड ने 1-1-1986 और 1-5-90 में अपने कर्मचारियों के वेतनमान रिवाइज किए हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमान राज्य सरकार के सिमिलर केडर के कर्मचारियों के वेतनमानों से ज्यादा हैं। उन वेतनमानों की फाइनल डिपार्टमेंट से कोई प्रायर एप्रूवल नहीं ली गई। मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि घाटे में चलने वाली कोई संस्था जब अपने कर्मचारियों के वेतनमान रिवाइज करने लगे तो उसकी एप्रूवल

[डा० राम प्रकाश]

वित्त विभाग से अवश्य ले। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लोसिज राष्ट्रीय स्तर पर 18 परसेंट हैं और हरियाणा में 26 से 30 परसेंट हैं। बिजली बोर्ड के बारे में मेरा एक सुझाव है कि बिजली बोर्ड को दो हिस्सों में बांटा जाए। एक बोर्ड रहे जो बिजली पैदा करने का काम करे और दूसरा रहे जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करे ताकि पता लग सके कि कितनी बिजली दी गई और कितनी बचे गई। पानीपत थर्मल प्लांट को स्टेज चार के डिजाइन, प्रोजेक्ट को एम्प्लीकेशन का काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। उसके लिये 1993-94 में 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है लेकिन सितम्बर तक उस पर केवल 1.35 करोड़ रुपये खर्च हुए बताए हैं। पावर जनरेशन की दर प्रति वर्ष घट रही है। पिछले वर्षों में जो तेल से बिजली पैदा करने का ढंग है, उसमें तेल की खपत बढ़ी है परतदानुसार बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा। कोयला घटिया किस्म का मिल रहा है जिसके कारण खर्च बढ़ रहा है, पर बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इससे बिजली उत्पादन का प्रति यूनिट खर्च बढ़ता है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार बिजली बोर्ड को दो हिस्सों में बांटेगी यानि दो बोर्ड बनाने पर विचार करेगी? क्या सरकार एक ऐसी कमेटी गठित करेगी जो खर्च घटाने और एफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके बताए? यदि यह कर दिया जाता है तो मुझे लगता है किसान के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिजली बोर्ड का काम बेहतर होगा। हरियाणा में विभिन्न थर्मल प्लांट्स का प्लांट लोड फैक्टर बहुत कम है। पानीपत के थर्मल प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर 47 प्रतिशत है। फरीदाबाद के थर्मल प्लांट का पी०एल०एफ० 62 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर पी०एल०एफ० 80 प्रतिशत है। बदरपुर पावर स्टेशन का 82 प्रतिशत है। हमें इन सारे तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात एच०एस०एम० आई० टी० सी० के बारे में कहना चाहता हूँ। यह कारपोरेशन सिचाई के क्षेत्र में लाभप्रद गतिविधियों के लिए बनाई गई थी। इस कारपोरेशन को प्रति वर्ष साढ़े छः करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। मार्च, 1993 तक इसमें 51 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। अप्रैल 1993 में इस कारपोरेशन के कामकाज की देखरेख के लिये एक इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स कन्सलटेंट्स की कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने दो महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी। यह तो मुझे पता नहीं कि उसकी रिपोर्ट आई या नहीं लेकिन यदि रिपोर्ट आ गई हो और उसको यह रिपोर्ट हो कि इस कारपोरेशन को बन्द किया जाये तो इस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जो सीड कारपोरेशन है, इसमें भी 2.6 करोड़ रुपये का घाटा चल रहा है। मेरा सरकार को सुझाव है कि घाटे

को कम करने के लिये इसको हरियाणा एग्री-इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के साथ मिला दिया जाये। इसी प्रकार से हैण्डलूम एण्ड हैण्डिक्राफ्ट्स कार्पोरेशन में 2.07 करोड़ रुपये का घाटा है, इसे कार्पोरेशन को हैण्डलूम वीवर्ज एपैक्स तथा हरियाणा स्माल इण्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन के साथ मिला दिया जाये ताकि घाटे को कम किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब दोबारे शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। हरियाणा के बहुत से स्कूलों में मुख्याध्यापकों के और प्रिंसिपलों के काफी पद रिक्त पड़े हैं। इन स्कूलों में इन खाली पड़े पदों को भरा जाये। जहाँ इस से एक तरफ स्टाफ की परमिशन का मौका मिलेगा वहाँ दूसरी ओर हरियाणा के इन स्कूलों में पढ़ाई भी अच्छी प्रकार से होगी और बच्चों का भविष्य भी सुधरेगा। मेरा यह भी कहना है कि पिछले दिनों डाईट की एक स्कीम चलाई गई है। इस स्कीम के लिये केन्द्र सरकार से पैसा आता था। इसमें यह भी प्रावधान है कि सीनियर लेक्चरर को उनकी बैसिक से का 20 प्रतिशत अधिक दिया जायेगा। जब इस स्कीम के लिये केन्द्र सरकार से पैसा मिल रहा है तो हमें इसका अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहिए। इस स्कीम में कुछ लोगों को तो 20 प्रतिशत पेंशन में भी लगा दिया गया पर आजकल अतिरिक्त 20 प्रतिशत देना बन्द है। मैं चाहता हूँ कि डाईट में चुन करके पूरा स्टाफ लगाया जाना चाहिए ताकि केन्द्र सरकार की इस स्कीम का अधिक से अधिक फायदा हो सके। शिक्षा के बारे में यह भी कहना चाहता हूँ कि गाँव के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उनके पास वित्तीय साधनों का अभाव होता है। गाँव में गरीब के घर में एक ही कमरा है, उसी में माँ चूल्हे पर रोटी बनाती है और उसी में एक तरफ भैंस आदि बंधी होती है, वहीं पर उसका बूढ़ा बाप बीमार पड़ा होता है जिस के कारण पढ़ने वाला बच्चा पढ़ नहीं पाता। मेरा सरकार की सलाह है कि गाँवों में सेमी-रैजिडेशियल स्कूल बनाए जाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे अच्छी तरह पढ़ सकें। इन स्कूलों में बच्चों के बैग व बिस्तरे रखने का और सैने का प्रबंध वहीं पर ही सकता है। ये बच्चे छुट्टी के बाद अपने घर जा कर खाना वगैरा खा कर स्कूल में वापिस आ जाएं और कुछ अध्यापकों को पाँच प्रतिशत अधिक तनखाह देकर उनकी देखरेख के लिए लगाया जाये ताकि बच्चे अधिक पढ़ लिख सकें। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि गाँवों में सेमी-रैजिडेशियल स्कूल खोले जाएं। यदि सरकार ऐसी व्यवस्था कर देती है तो बच्चों की पढ़ाई का स्तर ऊँचा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, सभी को पता है कि शहरों की अपेक्षा गाँवों के बच्चों का प्रतिशत परीक्षा परिणाम काफी कम होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात भूतमाजरा के गाँव की 2 कन्याओं को, जिनको उठा लिया गया था, के बारे में कहना चाहता हूँ। इनका अभी तक

[डा० राम प्रकाश]

कुछ पता नहीं चला है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ सख्त से सख्त कदम उठाए। उपाध्यक्ष महोदय, 4 नवम्बर 1993 को लाडवा से अमृतसर के लिए ट्रक नं० एच० वाई० ए० 9947 जा रहा था वह रास्ते में चोरी हो गया और इसके बारे में पुलिस स्टेशन पंजीबरा (अम्बाला) में पूरी डिटेल् दर्ज है। फिर भी मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि उस ट्रक में 2 लाख 15 हजार का चावल था। ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को मार दिया गया। इन दोनों का आज तक कुछ भी नहीं पता कि वे कैसे मारे गए और कहाँ चले गए। इसको पड़ताल करके दोषियों को दण्ड दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं एक बात की और विशेष ध्यान आकषित करना चाहता हूँ कि हमारे एक भूतपूर्व विधायक एवं मन्त्री जौधरी रण सिंह जी का साला रवि प्रकाश, जो यहाँ सिविल सचिवालय में काम करता था, उसको यहाँ से दिन दहाड़े उठा लिया गया, वह बेहोशी की हालत में पाया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी हत्या का आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। अगर सचिवालय में बैठे हुआ व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तो फिर कहाँ सुरक्षित महसूस कर पायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं हरियाणा के छोटे स्टेट्स पर बसों के परमिट देने के बारे में कहना चाहता हूँ। इस बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था कि हरियाणा में जो छोटे मार्ग हैं, उन पर बसें चलाने के लिए प्राइवेट सीसाइटीज को परमिट दिए जा रहे हैं। यह रोजगार देने का एक ढंग है, इससे न केवल वत सेवा बेहतर बनेगी अपितु लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस बारे में एक बार यह निर्णय हो गया था कि 20% परमिट ऐसी सीसाइटीज को मिलेंगे जिसके सभी सदस्य अनुसूचित जाति के हों। अगर सम्भव हो तो 27% देंगे। अगर 27% परमिट देना संभव न हो तो कम से कम 10% परमिट तो ऐसी सीसाइटीज को दिए जाएँ जिनके सभी सदस्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हों। इस ढंग से काम करने से रोजगार बढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार उन पर गम्भीरता से विचार करते हुए उन पर अमल करेगी जिससे सारी स्टेट की अर्थव्यवस्था चुस्त/दुरुस्त बन सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मुझे बोलने के लिये आपने जो समय प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री० राम बिलास शर्मा (महेन्द्राढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामे राम गुप्ता जी ने जो बजट सदन में रखा है, मैं उस पर बोलने के लिये उड़ा हुआ हूँ। (हस)

समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।) जिस तरह का यह बजट रखा है, अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा में इस तरह का बजट पहले कभी नहीं रखा गया। इसमें कोई दिशा नहीं है, इसमें कोई संकल्प नहीं है। इसमें कोई इच्छाशक्ति भी नहीं है। Budget is a document of the Government, which is governed by the election manifesto of the ruling party. स्पीकर सर, एक समस्या हरियाणा में बहुत देर से चल रही है और उस समस्या का जिक्र आज भी सदन में कई बार आया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह बजट स्पीच है जो वित्त मन्त्री श्री कटार सिंह छोकर ने 1987-88 में बजट प्रस्तुत करते हुए की थी। इस स्पीच के संकल्प पंरे में इस समस्या की बाबत लिखा गया है। स्पीकर साहब, उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार ने कहा था कि इस राज्य में एस० वाई० एल० का न बनना एक गम्भीर बात है, यह हरियाणा की लाईफ लाइन है और किसानों के हित के लिये है। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर खेत में हरियाली होगी तो किसान के मुँह पर मुस्कान होगी और बाजारों में रौनक होगी, अगर खेत में हरियाली नहीं होगी तो किसान के मुँह पर मुस्कराहट नहीं होगी, जब मुस्कराहट नहीं होगी तो बाजार की रौनक फीकी रहेगी। श्री कटार सिंह छोकर ने बजट स्पीच में कहा था कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। केन्द्र सरकार ने एस० वाई० एल० को प्राब्लम को समझा है। यह बजट स्पीच भी कांग्रेस के वित्त मन्त्री की है, इसमें किसानों को राहत देने और एस० वाई० एल० के निर्माण के लिये प्रावधान है। 1987-88 की बजट स्पीच में एस० वाई० एल० के बजट का प्रोवोजन किया गया। उसके बाद 1988-89 में चौधरी देवी लाल जी की सरकार आई जो जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सांझी सरकार थी। उस समय चौधरी देवी लाल की सरकार के वित्त मन्त्री श्री बनारसी दास गुप्ता जी थे। उन्होंने जो बजट स्पीच पढ़ी थी, उसमें एस० वाई० एल० के बारे में कहा गया था कि यह हरियाणा की लाईफ लाइन है। प्रधान मन्त्री जी ने पिछली सरकार के समय आश्वासन दिया था कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जून तक यह नहर पूरी होने की संभावना है। फिर भी उस सरकार ने 34.50 करोड़ रुपये का प्रावधान एस० वाई० एल० के लिये किया था। स्पीकर सर, फिर कांग्रेस का 1991 में मनिफेस्टो आया और कांग्रेस ने जनता से वायदा किया कि इस नहर को पूरा करवाया जाएगा। हरियाणा वर्ष 1966 में हिन्दुस्तान के नक्शे पर आया था और उस वक्त 60:40 के अनुपात से भवती, सड़कों, नहरी जल का वितरण हुआ था परन्तु हरियाणा को उस बंटवारे में अपना पूरा हिस्सा नहीं मिला। इन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हरियाणा के 90% काम पूरे करके दिखाएगी। अध्यक्ष महोदय, दक्षिण के इलाके हैं, उनके बारे में तो आप भी जानते हैं। अपने यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर खेती की जमीन की कमी है, लेकिन बाकी इलाकों में जमीन की भी समस्या नहीं है। हमारे इलाके में पाने के पानी की प्रब्लम है।

[श्री० राम बिलास शर्मा]

इनकी सरकार आने के बाद वहाँ के लोगों को बहुत ही उम्मीद थी कि एस० वाई० एल० का मामला चूक मैनिफेस्टो में रखा गया है और बनने के लिये 90 दिन का समय दिया है, इसलिये बन जायेगी। लेकिन आज कपिस की सरकार को आए हुए अढ़ाई साल हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री जी और श्री मांगे राम गुप्ता जी ने बजट में कहीं पर इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। इन्होंने जाट पेज पर हरियाणा के लोगों को एक सपना दिखाया है कि "हमें आशा है कि पंजाब में कानून और व्यवस्था में सुधार होने से नहर का निर्माण कार्य जल्दी से दोबारा शुरू होगा और शीघ्र ही पूरा हो जाएगा"। But there is no time limit और एस० वाई० एल० के लिए बजट में एक नए पैसे का प्रावधान भी नहीं रखा है। इन्होंने जो प्रावधान किया है, वह टूट फूट और गाद निकलवाने के लिये रखा है। इन्होंने गाद निकलवाने के लिये 14.82 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत नहीं है कि इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात किया है क्योंकि इस सरकार ने अपने बजट में एस० वाई० एल० नहर के निर्माण के लिये एक नए पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा है। It is only the people of Haryana, the great people of Haryana who always act patiently. इन्होंने इस बजट में हरियाणा की जनता को यह सपना दिखाया कि जब पंजाब के हालात ठीक होंगे, तब एस० वाई० एल० का निर्माण होगा। यानी पंजाब के हालात के साथ हरियाणा के भविष्य को जोड़ा गया है, यह बहुत ही गलत बात है। आप सब जानते हैं, जब पंजाब की हालत खराब थी तो हरियाणा में भी सड़कें लोगों की जानें गई हैं। उसके बाद भी इन्होंने नान-सीरियस बात कही है। अध्यक्ष महोदय, 1986 में जन-आन्दोलन हुआ था और 1987 में चुनाव हुए थे तो उसके बाद एक सरकार बनी थी। 90 में से 85 एम० एल० एंज० एक ही मुद्दे पर जीत कर आए थे और वह मुद्दा यह था कि रावी व्यास का पानी लेना, एस० वाई० एल० को पूरा करना और अंबाहर फाजिल्का के 107 गांवों को हरियाणा में मिलाना आदि। अध्यक्ष महोदय, जब पंजाब में हिंसा हुई थी, आतंकवाद का जोर था और पंजाब में हिन्दुस्तान के संविधान की कापी जलाई गई थी, तो पंजाब में राजीव-लीगावाल ने एक समझौता किया था। आज वे दोनों महापुरुष इस दानया में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आज के मुख्य मंत्री उस समझौते के समय बाहर बैठे रसगुल्ले चाट रहे थे। अध्यक्ष महोदय, राजीव लीगावाल समझौते के खिलाफ धारा 7 और 9 के खिलाफ हरियाणा की डेढ़ करोड़ जनता ने ऐसा किस्टल क्लीयर शान्तिपूर्वक तरीके से विरोध किया और कहा कि — "We hereby reject this accord" हम हरियाणा के लोग प्रजातान्त्रिक तरीके से राजीव लीगावाल समझौते को ठुकराते हैं और 90 में से 85 लोगों को जीता कर भेजते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिये हरियाणा की जनता लड़ रही है

और इन्हीं मुद्दों पर हरियाणा में दो तीन बार चुनाव हो चुके हैं। 1987 में भूदंड दिया जा चुका है। 1981 में जो मुद्दे कांग्रेस ने चुनाव मैनीफेस्टों में रखे थे आज इस बजट में कौन आदमी उस मैनीफेस्टों को कितनी गम्भीरता से लेता है, यह इस बजट से ही जाहिर है। हरियाणा के हितों के मुद्दों को कांग्रेस सरकार जानबूझ कर भूल रही है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के जो अहम मुद्दे हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी राजनैतिक मजबूरी है जो यें उन अहम मुद्दों को भूल रहे हैं? श्री 0 सम्पत सिंह जी एक प्रस्ताव लाए थे और हम सबने बड़ी एकाग्रता से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था कि इस प्रस्ताव पर बहस हो। आज पंजाब विधानसभा का सेशन भी चल रहा है। दोनों असेम्बलीज के सेशन से पहले यानी हमारा बजट पेश होने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री जानबूझकर उन्हीं मुद्दों पर बोल रहे हैं। वे इन मुद्दों पर जालन्धर या लुधियाना में नहीं बोले बल्कि फरीदाबाद में ही रहे जाल इन्डिया कांग्रेस वकिंग कमेटी के सेशन में बोले थे जहाँ पर कांग्रेस के बहुत से नेता और स्वयं प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। उन्होंने हरियाणा की क्षरती पर खड़े होकर कहा था कि एस 0 वाई 0 एल 0 नहीं बनायी जा सकती, सभी व्यास का पानी अभी नहीं दिया जा सकता। आज वह जमुना के पानी में से भी अपना हक मांग रहे हैं। Things are not so simple to solve स्पीकर सर ये चीजे इतनी सामान्य नहीं हैं बल्कि जानबूझ कर स्कावट डालने के लिये खड़ी की जा रही हैं। जब हरियाणा की जनता इस बजट को पढ़ती है तो उसके अन्दर एक भय की भावना पैदा होती है और पूछ रही है कि कांग्रेस की यह कमजोर सरकार इस बजट के माध्यम से क्या प्रस्तुत करना चाहती है? स्पीकर सर, इस बजट में कोई बिल नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। यह सरकार हरियाणा के हितों के साथ अनदेखी कर रही है। हरियाणा की जनता अपना जो खदसा प्रकट कर रही है, वह इस बजट से और साफ हो जाता है। स्पीकर सर, अयोधर फाजिल्का लेने की बात तो दूर रही, चण्डीगढ़ के मामले में भी आए दिन यह कहा जा रहा है कि बेशाखी पर या लोडी पर चण्डीगढ़ पंजाब को जा रहा है, अब जा रहा है, जब जा रहा है। कभी किसी और ट्पीहार का नाम ले लिया जाता है, कभी किसी का, और कभी कहा जाता है कि नरसिम्हाराव जी यहाँ पधारेंगे और वे चण्डीगढ़ पंजाब को दे देंगे। स्पीकर सर, हरियाणा सरकार की अपनी मंशा तो बजट से ही प्रकट हो जाती है और यह बजट इस बात को जाहिर करता है कि इस कांग्रेस सरकार को कोई विशेष राजनैतिक भय सता रहा है जो सामने से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन पर्दे के पीछे वह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। स्पीकर सर, यह इस बजट से ही साफ हो जाता है कि यह सरकार हरियाणा के हितों को बेचने जा रही है।

स्पीकर सर, इस बजट में महिलाओं के कल्याण की बात कही गयी है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में सदन के नेता ने भी एक प्रस्ताव रखा था और सभी लोगों ने इस का समर्थन भी किया था लेकिन स्पीकर साहब, the performance

[श्री० राम बिलास शर्मा]

of this Government इस बात की ताईद नहीं करती कि इस सरकार के हाथों हरियाणा के हित सुरक्षित हैं। जैसे कि हमारे भाई डा० रामप्रकाश जी ने, जो कि कांग्रेस के साथी हैं, ने अपने चुनाव क्षेत्र की घटनाओं के बारे में चर्चा की है। इससे पहले भी उस घटना की चर्चा कई बार इस सदन में हो चुकी है। 28 अगस्त, 1991 को कुसम और विमला नाम की दो लड़कियाँ, जिनकी उम्र क्रमशः 18 और 16 साल थी, इनमें से एक लड़की की लाश मिली थी, चप्पल मिली थी और दूसरी लड़की का कोई अंतापता नहीं चला। इसी तरह से नारायणगढ़ में सप्रेड़ी गाँव की एक लड़की संतोष, जो गरीब हरिजन की बेटी थी, की अस्मित लूटी गयी और जब उसका घरवाला रघुवीर सिंह शिकायत करने गया तो उसकी भी गला घोटकर जान ले ली गयी, उसको न्याय नहीं मिला। इसी तरह से लाडवा के पास भूखेड़ी गाँव में फिर एक हरिजन के साथ अत्याचार हुआ। इसी तरह से स्पीकर सर, आपके ही चुनाव क्षेत्र में लोहाकू माजरा में लच्छो नाम की लड़की थी। उसके साथ क्या क्या हुआ, यह वह नहीं बता सकी। सर, इस मामले को आपसे अधिक कोई नहीं जान सकता। लेकिन वह बता नहीं सकी कि उसकी अस्मित लूटी गयी या नहीं लूटी गयी, लेकिन उसकी जान चली गयी। स्पीकर सर, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ अस्तरदार लोगों ने यह कहा कि लच्छो के बाप ने अपनी लड़की के साथ मुँह काला किया है, इसलिए उसने लड़की को मार दिया।

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, यह मामला सबजूडिस है। साथ ही इसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि यह क्या मामला है।

श्री० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैंने पहले ही कहा था कि यह आपके क्षेत्र का मामला है इसलिए आपको ही ज्यादा पता होगा। लेकिन मेरे पास, जो एफ० आई० आर० दर्ज की गयी थी, उसकी नकल है। स्पीकर सर, उसके बाद उसके बाप ने प्रतिवेदन किया, तब एस०पी० रैंक के आदमी ने इक्वायरी की और उस गाँव में जाकर कहा कि this I know, मैं यह बात साबित करता हूँ कि लच्छो के साथ, उस के बाप ने, कोई कुकर्म नहीं किया। वह इसमें शामिल ही नहीं है। उसका दोष केवल यही है कि वह गरीब है, हरिजन है। स्पीकर सर, वह मजदूरी के लिए गया हुआ था और आते समय उसने देखा था।

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, जो आप कह रहे हैं, यह किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, जो रिपोर्ट लिखवायी गयी है, उसकी मेरे पास नकल है। साथ ही एक महिला समिति ने भी जो प्रतिवेदन किया है, उसकी भी नकल है और मैं उसी के आधार पर यह बात कह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं ये सारे कागजात आपको भिजवा सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, यह पुलिस का काम है। पुलिस ने इक्वायरी की है और उन्होंने जालान पेश कर रखा है। यह सब-जुडिस मामला है, इसके बारे में आप हाउस को मिसलीड करने की कोशिश न करें।

Prof. Ram Bilas Sharma : I am not misleading Sir, I am speaking on the basis of hard facts. के 0के 0 शर्मा ताम के आई० पी० एस० ऑफीसर ने जो इक्वायरी की है, उसने कहा है और अदालत में इर्बास्त दो है कि यह जालान रोक दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, आप किसी ऑफीसर का नाम न लें। यह पुलिस की अपनी इक्वायरी है। पुलिस के भी एक से एक बड़े ऑफीसर हैं। आप इस ढंग से किसी भी ऑफीसर के बारे में न कहें।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, आपने मिसलीडिंग वाली जो बात कही है और मैं जो कह रहा हूँ (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सब-जुडिस मामला है और कोर्ट अपने आप फैसला करेगी। पुलिस के भी एक से एक सुपर ऑफीसर हैं, यह उनकी अपनी इक्वायरी है। वे किसी फाइंडिंग पर पहुँचे हैं और उनके मुताबिक उन्होंने केस दर्ज कराया है और जालान पेश किया है।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैंने तो अपनी बात उन फैक्ट्स के आधार पर, इस सदन को अवगत कराने के लिए कही है, जो मेरे पास कामजात हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आपके पास होंगे, लेकिन सारे फैक्ट्स नहीं हैं।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैंने तो आपसे कहा है कि यह आपके आसपास का मामला है, आप इस बारे में सबसे ज्यादा जानते होंगे। परन्तु इतनी बात जो मैंने कही है, काइम ब्रांच की जो रिपोर्ट आई है, उसका भी यह मानना है कि इसमें रामस्वरूप को जानबूझकर फंसाया गया है। खैर, जो सब-जुडिस मामला है।

श्री अध्यक्ष : काइम ब्रांच की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, आपने सरकारी डीक्यूमेंट्स कैसे पढ़ लिए ?

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैंने सरकारी डीक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हैं परन्तु जो काइम ब्रांच का एस० पी० वहाँ गांव में गया है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : काइम ब्रांच के एस० पी० ने आपको बताया है ?

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, वहाँ गांव के लोगों ने बताया कि 500 लोगों के बीच में काइम ब्रांच के आदमी ने बताया कि यह जितनी प्रोसीडिंग हुई

[श्री० राम विलास शर्मा]

है, इसमें उसकी असहमति है। इस में राम स्वरूप कतई गुनहगार नहीं है, कुछ फेक्ट्स और हैं जिनको छिपाया जा रहा है। यह जो 500 लोगों के सामने कहा गया है, वह मैं आपके सामने कह रहा हूँ। (विपत्त)

श्री अध्यक्ष : राम विलास जी, जो आप कह रहे हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि आपके फेक्ट्स बिल्कुल गलत हैं। मैं भी उस गांव में गया था। पांच सौ आदमियों के मुताबिक और जो सरकमस्टेंशियल ऐबीडिसिज हैं, उनसे साबित होता है कि उसका बाप ही उसके अंदर है, हालांकि वो केस बलात्कार का नहीं है। सेक्टोरिय टेस्ट जो आए हैं, उनके मुताबिक यह बलात्कार का केस नहीं है, बलात्कार करने की श्रावद उसने कोशिश की है, वह पहले शराब पीकर भी आया है, उसका पहले भी करैक्टर इस ढंग का है। डी० एस० पी० ने कुत्ते उसी वक्त बुलाए, कुत्ते ने भी उसी को पकड़ा, और किसी को नहीं पकड़ा। उसने जिस हथियार से कत्ल किया है, वो हथियार भी उसने दिया है और वो खून में लथपथ था, उसके कपड़ों पर भी उसके छीटे लगे हुए हैं, और किसी के नहीं हैं। राम विलास जी, आपको पूरी बात का पता नहीं है, इसलिए आप मिसलीड न करें, यह मामला सब-जूडिस है। जालान्त कोर्ट में पेश है इसलिए आप इस पर कोई बात न कहें। यह यहाँ कहने की बात नहीं है, यह कोर्ट डिसाइड करेगी।

श्री० राम विलास शर्मा : उन्होंने 7-8 बेज का रिप्रेजेंटेशन डी० जी० पी० को दिया है, उसकी कॉपी भी भेजे पास है।

श्री अध्यक्ष : रिप्रेजेंटेशन तो कोई खुद भी दे सकता है, उस पर इन्क्वायरी होती है। एक से एक बड़े प्रॉफेसर हैं जो इन्क्वायरी करते हैं।

Power Minister (Shri A. C. Chaudhri) : As per the established norms जो सब-जूडिस केस है, उस पर बहस नहीं हो सकती। एक आदमी जो किसी केस में इन्वॉल्व है, उसका वर्शन जब तक अदरवाइज प्रूव न हो, उसे अर्थिटिक मानना कहीं भी वाजिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : राम विलास जी, आप और बात कहें।

श्री० राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, महिलाओं के साथ ज्यादती के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस सरकार ने शुरू में कहा था कि कानून की ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे जिसमें सेर सोना पहनकर 16 साल की लड़की रात के 12 बजे वहाँ भी जा सकती। रात तो अलग रही, सोना पहनना तो अलग रहा, आज तो गरीब गुरबे की केटी, छप्पर की झोंपड़ी में रहने वाली, मजदूरी करने वाली लड़की भी सुरक्षित नहीं है। कुछ संस्थाओं के बारे में डा० राम प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी चर्चा की।

स्पीकर सर, कोई भी सरकारी संस्था आज मुनाफे में नहीं है। हेफेड में मुनाफा नहीं है। बीटा दूध बनाने वाले मिल्क प्लांट में मुनाफा नहीं है। बीटा घी जहां पर बनता है, उसके साथ ही प्रिंसिपल्स से लगभग 10-20 किलोमीटर की दूरी पर, एक रिटायर्ड आई० ए० एस० अधिकारी मधु घी बनाता है, वह साल में करोड़ों रुपया का मुनाफा कमा रहा है लेकिन हमारा प्लांट घाटे में जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम गुप्ता जी, आप जवाब देने के लिये कितना समय लेंगे ?

श्री मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : सर एक घंटा लूंगा। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, अब आप खत्म करें।

श्री० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैंने अभी तो शुरू ही किया है। अब आप कह रहे हो कि खत्म करें।

श्री अध्यक्ष : आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गये हैं। आप 5 मिनट और ले लें और खत्म करें।

श्री० राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैं आपके आदेश की अनुपालना करूंगा। मेरी बात बीटा के बारे में चल रही थी। आस-पास की गाय-भैंसों के दूध से वह मिल्क प्लांट घाटे में जा रहा है लेकिन नजदीक ही एक रिटायर्ड आई० ए० एस० अधिकारी वहां की गाय-भैंसों के दूध से करोड़ों रुपया कमा रहा है। स्पीकर साहब, हमारी कुछ संस्थाएँ, कुछ व्यक्तियों के लिये चल रही हैं। एच०एम० टी० की जो इंडस्ट्री पिजौर में है, उस के बारे में कुछ लोगों ने और वहां के कुछ कर्मचारियों ने मुझे यह बताया है कि इसको भी सरकार प्राइवेट लोगों को देने जा रही है। एक बात का यह सरकार हवाला जरूर देती है कि बाहर के लोग अच्छे टेलेन्टिड हैं। प्रशासन चलाना उनको अच्छा आता है। उद्योग भी वह अच्छे तरीके से चला सकते हैं और एन० आर० आईज० के नाम पर यह इंडस्ट्रीज चलाना चाहते हैं। स्पीकर साहब, यह जो यहां पर ट्रेंड चल रहा है, It is just to demoralise Indian talents, just to demoralise Indian minds. यह ट्रेंड बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड है। हेफेड घाटे में है, बीटा मिल्क यूनियन में भी घाटा है। मिल्क के मामले में स्पीकर साहब पिछले साल मार्च के महीने में हमारी सरकार द्वारा दूध का दाम 88 पैसे पर फेड के हिसाब से दिया जा रहा था। स्पीकर साहब, आप खुद किसान हैं, आपको पता है कि फीड के दाम बढ़ गये हैं। जो पशुओं को चारा खिलाते हैं, उस सब के दाम बढ़ गये हैं परन्तु दूध के दाम घटा कर 85 पैसे प्रति फेड के हिसाब से दिये जा रहे हैं। स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें हो सकता है कि दूध से सम्बन्धित इंडस्ट्रीज अगाड़ी जायें।

[प्रो० राम बिकास बर्मा]

सरकार को भी इस मामले में सोचना चाहिये। लेकिन हरियाणा सरकार तो हैफेड को नहीं चला सकती, बीटा को नहीं चला सकती और न ही बिजली को चला सकती है। बिजली के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं। हरियाणा में बिजली का घाटा 30-35 परसेंट लाईन लोसिज की वजह से हो रहा है। इसके मुकाबले में आप सारा हिसाब-किताब देखें कि वन्वई में टाटा भी बिजली जनरेट करता है। वहां पर कमी बिजली जाती नहीं है। आप वहां के किसी भी आम आदमी से यह पूछें, उनका कहना यह है कि पिछले 40 साल में शायद ही कभी एक-आध मिनट के लिये बिजली गयी होगी। इससे ज्यादा जाती नहीं है। वहां पर आप सुबह अगर दरखवास्त देकर आते हैं कि मेरी लाईन में सर्किंग है, तो 24 घंटे के अन्दर अन्दर वह लाईन चेंज कर देते हैं। जब टाटा बिजली को इतनी अच्छी तरह से मॉन्टैनिंग कर सकता है और अच्छी सर्विस दे सकता है तो आपका बिजली बोर्ड क्यों नहीं दे पाता? इसमें घाटा लगभग 1155 करोड़ रुपया है जो बिजली बोर्ड ने लोन के रूप में लिया हुआ है और जिसके लिये हरियाणा के लोगों की तरफ से, हरियाणा सरकार ने गारन्टी दी हुई है। यह जो बजट पेश किया गया है, यह कोई बजट नहीं है। यह तो बजट का अडंगा है। बिजली के दाम पिछले दो-अढ़ाई साल में तीन बार श्री मंत्री राम गुप्ता जी ने बढ़ाये हैं। हर वर्ष यह बिजली के दाम बढ़ा देते हैं। फिर वहां पर आकर वह कहते हैं कि टैक्स-फ्री बजट है। इस बजट को देखने से ऐसा लगता है कि आपकी सरकार किसी अदृश्य श्रय से प्रस्त है। किसी न किसी दिखने वाले उद से श्रयभीत है, आतंकित है। इसलिये इन्होंने ऐसा नीरस और बिना इच्छा शक्ति के यह बजट पेश किया है। इस बजट को देखने से तो ऐसा लगता है कि हरियाणा के अन्दर पैसा लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। आज हरियाणा में बिजली की छपत पिछले वर्षों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बढ़ रही है। बिजली की छपत के मामले में हम निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज हालत यह है कि धन के अभाव के कारण हम कोयला नहीं ला सकते, एन०टी०पी०सी० का बिल पे नहीं कर सकते। हमारे मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि हम बिजली ज्यादा जनरेट नहीं कर सकते और बिजली की ठीक सप्लाय नहीं कर सकते, इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। जैसा पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश में किया, जैसा राजस्थान सरकार ने लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी कमी को स्वीकार करते हुए प्राइवेट क्षेत्र में जो बिजली जनरेट कर सकता हो, उसके साथ हिसाब किया। स्वीकर साहब, आज जब भी हम कोई बात कहते हैं तो मुख्य मन्त्री जी एक ही बात कहते हैं कि पिछली सरकार ने ऐसा किया। स्वीकर साहब, उन भारी बातों को अढ़ाई साल हो गए। जो बात थी वह समाप्त हो गई। अढ़ाई साल का समय किसी सरकार को परखने के लिए, किसी सरकार की कारगुजारी को देखने के लिए कोई कम समय नहीं होता। सारे गुनहारे पिछली सरकार पर डालकर हम अपने गुनाहों से बरी नहीं हो सकते। पिछले राज को यह चर्चा करते हैं। स्वीकर साहब, वहां

पर कोआपरेटिव का मामला आया। कोआपरेटिव में एक शास्त्री सोसायटी अम्बाला में है। यह रिटायर्ड कर्मचारियों की है। उसमें कोई बपला हुआ। वहां पर इस सोसायटी की इन्कवायरी होती है, जांच होती है और इन्हीं की सरकार की जो जांच रिपोर्टें हैं, उसको यह सरकार लागू नहीं कर सकती। उस रिपोर्ट को दूसरी तरह से खिसटोट करते हैं। उसमें लाखों रुपए के गबन का मामला पकड़ा गया है। दो तीन अच्छे ऑफिसर्स ने उसकी जांच की परन्तु आज भी उस सोसायटी के मामले में कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। स्पीकर सर दिक्कत तो यह है कि जब कोई ऐसे मामले आते हैं तो उसमें कोई न कोई ऐसे तरीके से संलिप्त हो जाता है और फिर सरकार की कोई ऐसी मजबूरी अड़ जाती है जिससे लोगों को न्याय नहीं मिलता।

स्पीकर सर, एक बात डकल प्रस्ताव के बारे में हम जानना चाहते थे, लेकिन उसको नहीं माना गया। आज भी कांग्रेस के एक साथी ने एक अच्छा प्रस्ताव रखा था। हमारी गृह परम्परा के बारे में पाकिस्तान टिप्पणी करता है। यह ठीक है कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि यह मामला विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। पर स्पीकर साहब, यह मामला एक ऐसे देश से जुड़ा हुआ है जिसने कदम कदम पर हमारे पंजाब की शान्ति भंग कर दी। जो आज भी आई०एस०आई० के माध्यम से हमारे जन जीवन को अस्त व्यस्त करने की कोशिश कर रहा है। भारत अपने मुकद्दमें की परवा करने के लिए जनैवा में डटा हुआ है। स्पीकर सर, जान बूझ कर अगर हमारा सामाजिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी सामाजिक संरचना है, उसको ध्वस्त करने की साजिश ही रही है तो इस मामले में हरियाणा की असेम्बली, हरियाणा की जनभावना को अभिव्यक्त कर सकती है और इसके लिए *this august House is competent in itself*. स्पीकर साहब, कर्नाटक के हाउस में और एक दूसरे प्रान्त के हाउस में डकल प्रस्ताव के बारे में प्रस्ताव पास किया और उन्होंने कहा कि यह डकल प्रस्ताव हिन्दुस्तान के लिए ठीक नहीं है। यह हिन्दुस्तान के किसान और शरीब आदमी को मारने का, दफनाने का षड़यन्त्र है। अमरीका भारत में आर्थिक गुलामी में जकड़ने के लिए प्रेशर टेक्टिक्स अपना रहा है। वह पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखकर हिन्दुस्तान में ईस्ट इंडिया कम्पनी का रोल अदा करना चाहता है। स्पीकर साहब, सोलह सौ ईसवी में पांच दस लोण चाय की पत्ती बेचने कलकत्ता के बड़े बाजार में ईस्ट इंडिया कम्पनी बनाकर आए थे और धीरे-धीरे हमारी रियासतों के नवाबों को

श्री अध्यक्ष : चाय तो यहां से जाती थी न कि वे लेकर आए थे।

श्री० राम विलास शर्मा : अपने काबू में कर लिया और पूरे हिन्दुस्तान पर पचास साठ साल में कब्जा कर लिया। इसलिए यदि डकल प्रस्ताव के विरोध में हमारी हरियाणा की असेम्बली यह प्रस्ताव पास करे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यहां पर सी में से 85 आदमी छेती करते हैं। इस सरकार की प्राथमिकता क्या है,

[श्री० राम विलास जर्मा]

यह इस बजह से पता नहीं लगता। यह शहर की सरकार है, यह गांव की सरकार है, यह गरीबों की सरकार है या अमीर की सरकार है, कहीं से भी यह बात प्रकट नहीं होती। ऐसा लगता है कि यह सरकार सिर्फ मन्त्रियों की सरकार है और आज हर काम में मन्त्री शामिल हैं। आज उनकी सुख सुविधा के लिए सारा सरकारी अमला-तमला लगा हुआ है। जनसेवा के लिए आज कोई जुटा हुआ नहीं है और आज श्री लोभ सरकार में बैठे हैं, उनमें जनसेवा की भावना बिल्कुल नहीं है। अभी ए० एस० आई० की भर्ती की बात हुई, स्कूल अपग्रेड करने की बात कही गई। मुख्य मन्त्री जी काफी समय से मुख्य मन्त्री हैं। पिछली बार जब स्कूल अपग्रेड करने की बात आई तो सबसे ज्यादा स्कूल अपग्रेड हुए हिसार जिले के, सबसे ज्यादा ए० एस० आई० लगने हैं तो हिसार जिले के। स्पीकर साहब, इनको बोझा-सा बड़प्पन दिखाना चाहिए। इनको पूरे हरियाणा का प्रोमोशनल विकास करना चाहिए। अब तो दो ही जगह विकास की दिक्कत आ रही है—एक कालका और दूसरे हिसार में। बाकी हरियाणा में बिजली मिले या न मिले, पानी मिले या न मिले, इसकी कोई चिन्ता नहीं है। स्पीकर साहब, जिस इलाके से मैं आता हूँ, वहाँ मैं चार-पांच तारीख को था। हमारे महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरी का पानी आगे जा रहा है। वहाँ के एक्स० ०३०एन० को मैंने कहा कि महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी में दो महीने से पानी नहीं आया, यहाँ गेहूँ की फसल सारी सूख जाएगी। हमें नहर विभाग के उस अधिकारी ने बताया कि हमें तो ऐसे आदेश हैं कि महेन्द्रगढ़ में पानी नहीं रोकना है, उसको आगे पहुंचाना है। मैंने कहा आप इस डिस्ट्रीब्यूटरी को खोल दें। मैंने सिवाई मन्त्री श्री नेहरा के नोटिस में यह बात ला दी और उन्होंने बड़ी अजीबो गरीब बात बताई कि एक दस जमुना में पानी ज्यादा आ गया और किसी मन्त्री ने उस अधिकारी से इंडेंट करवाया है कि तुम महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रीब्यूटरी में जल रोकने का इंडेंट मत भेजो। स्पीकर साहब, राजनीति आती जाती रहती है। कभी कोई मन्त्री बन जाता है, कभी कोई एम० एल० ए० बन जाता है लेकिन हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। स्पीकर साहब, सभी चुनाव क्षेत्रों का सरकार को एक-समान ध्यान रखना चाहिए। जरूरत के हिसाब से हर क्षेत्र में काम सरकार को करने चाहिए। स्पीकर सर, यह सरकार केवल मात्र मन्त्रियों की ही सरकार है, इससे हरियाणा की जनता में भरपूर गुस्सा बढ़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : राम विलास जी, आपका समय हो गया। (शोर)

(इस समय श्री सतबीर सिंह कादयान बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : कादयान साहब, कलिंग पार्टी का टाइम 252 मिनट और आपकी पार्टी के मੈम्बर 365 मिनट बजट पर और गवर्नर एंड्रेस पर बोल चुके हैं और राम विलास जी का टाइम इससे अलग है। (शोर)

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं एक दो बातें कहकर के ही वाइंड-अप कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकार के घाटे के संस्थान हैं, इन सब के लिए सरकार को एक समान नीति बनानी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक संस्थान पर एक नीति लागू हो और दूसरी पर दूसरी नीति लागू हो। स्पीकर सर, मेरा एक सुझाव है। स्पीकर सर, अब यह चुंगी-कर सरकार समाप्त करने जा रही है अच्छी बात है लेकिन इनमें जो हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं, उनका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जो लोग 15-15, 16-16 साल के ज्यादा अवधि से लगे हुए हैं, उनको इस तरह से रिट्रैन्च नहीं किया जाना चाहिए। (शोर) हरियाणा कंकास्ट है, हैफड है, ये जो घाटे के संस्थान हैं, इनको बन्द करके कोई न कोई दूसरा विकल्प ढूँढना चाहिए। घाटे के सौदे को चलता रहने का कोई औचित्य नहीं है।

स्पीकर सर, ये संस्थानों डायरियां छपवाती हैं और दूसरे कई कामों पर फिजूल खर्ची करती हैं लेकिन कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार की जो फिजूल खर्चियां हैं, उनको कम करना चाहिए। जो भी दूसरे साधन हैं, उनको अपनाकर हर लिहाज से बच खर्च सरकार को करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जब कभी प्रिवेनासिज कमेटी की मीटिंग होती है तो एक ही सब-डिविजन से तहसीलदार बी-0डी0ओ0 वर्ग रह सभी जाते हैं और वे सभी अलग अलग अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं। यह एक तरह से फिजूल खर्ची ही है। आज स्पीकर सर, हर आदमी पेट्रोल वर्ग रह के दाम बढ़ने से परेशान है लेकिन दूसरी ओर ये सरकारी अधिकारी कैसे पेट्रोल खर्च कर रहे हैं? इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कर्मचारियों से सम्बन्धित कुछ बातें कहूँगा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने कर्मचारियों से जो वादा किया था इसके लिए बजट के अन्दर भी उसका प्रावधान किया गया है परन्तु उनकी केवल एक दो बातें ही मानी। एक तो 100 रुपया इंटेरिम रिलीफ के तौर पर दिया और दूसरा 45 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए की राशि मीडिकल ग्रांटांसे के रूप में की है। बाकी जो बातें थीं, वे मुख्यमन्त्री महोदय ने मानी थीं। उसमें एक डिमांड पंजाब के समान वेतनमान की भी थी। उसके ऊपर भी सरकार को गौर करना चाहिए।

स्पीकर सर एक ओर तो सरकार यह घोषणा कर रही है कि जो कर्मचारी पांच-छः सालों से काम कर रहा है, उसको रेगुलर कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारियों की छूटनी कर रहे हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। हमारे यहाँ एक ऐन्सिअर श्री रामपाल सिंह से मेरी बात हुई। मैंने उन से चर्चा भी की थी कि जो 40 लोग 6-7 सालों से लगे हुए हैं, उनको रिट्रैन्च कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आपके लगाए हुए थे क्या ?

श्री 0 राम विलास शर्मा : नहीं जी, हमारे से पहले के लगे हुए थे और उनकी इस सरकार ने रिट्रैन्च कर दिया और वह ऐक्सीजन इस बारे में क्या कहता है—रात को मैं गया था, वहाँ पर टैकी चल रही थी पानी की, मोटर भी चल रही थी। मेस्टूल पर बैठा ऊँच रहा था। स्पीकर सर, अगर रात के 12 बजे ऊँच रहा था तो उसको सावधान कर दो। अगर ज्यादा ही करना है तो दो दिन की हाजरी काट लो। अगर वह ऊँच रहा था तो नौकरी ही खत्म कर दो, यह कहां का इन्साफ है? वहाँ पर तो सारी सरकार ही ऊँच रही है। अभी सम्पत सिंह जी ने लछमन दास अरोड़ा को बड़ी मुश्किल से जगाया है, वह छरटें भर रहे थे। देशक वीची को भी डिस्टर्ब कर रहे थे। तो स्पीकर साहब, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ तो सरकार यह कह रही है कि हम रेगुलेशन्स करेंगे और एक तरफ कर्मचारियों को हटावा जा रहा है। कम से कम सरकार को अपने बचत का पालन करना चाहिए और इस नारनील के पब्लिक हेल्थ के मामले को गौर से देखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : राम विलास जी, आपका समय हो गया, आप बैठिए।

श्री 0 राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, हम आपको नाराज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप नाराज हो गए तो समझो हमारा तो भगवान ही नाराज हो गया। यही दो चार शब्द कहने की बात होती है, जो आपकी अनुमति से, आप के संरक्षण से बोल पाते हैं। स्पीकर साहब, इसी तरह से यहाँ पर शूगर मिलों की बात भी चली।

श्री अध्यक्ष : आपके एरिया में कौन सा शूगर मिल है?

13.00 बजे

श्री 0 राम विलास शर्मा : स्पीकर साहब, शूगर मिल की बात आई है, अगर इनकी कृपा रही तो मेरे इलाके में शूगर मिल नहीं लगेगा। वहाँ पर तो बाजरा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। सारे देश के अन्दर शूगर मिल मुनाफे में चल रहे हैं और चीनी के दाम इतने बढ़े हुए हैं लेकिन हमारे हरियाणा में ये मिल बाटे में चल रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा किसानों की महीनों तक गन्ने की पेमेंट नहीं होती। मुझे नहीं पता कि मशीनरी में डिफिकट है, नियत में डिफिकट है या नीति में डिफिकट है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।

विजली मन्त्री (श्री ए 0 सी 0 चौधरी) : स्पीकर साहब, अपने भाषण के दौरान मैं भी श्री 0 प्रकाश चौटाला ने अपनी बात रखते हुए विजली डिपार्टमेंट के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो सच्चाई से कोसों दूर हैं। पहली बात उन्होंने यह कही कि विजली की प्रोडक्शन डाउन हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे वक्त में विजली की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी। मैं आंकड़े देकर कहना चाहता हूँ कि 1989-90 में 209 लाख यूनिट प्रति दिन पैदा हुई थी और 1990-91 में 229 लाख यूनिट पैदा हुई थी। आज की सरकार को यह क्रेडिट जाता है कि 1991-92 में 268 लाख यूनिट विजली प्रति

दिल पैदा हुई और 1992-93 में 297 लाख यूनिट्स। आज के दिन जबकि पॉंग डैम में पानी की कमी हुई है और वहाँ पर हमारे लिए बिजली की जनरेशन 40 लाख यूनिट कम हुई फिर भी 285 लाख यूनिट्स हमने सर्कुलेशन में दी।

चौधरी श्रीम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, ये प्रोजेक्शन की परसेंटेज के हिसाब से बताएं, ये अब भी हाउस को गुमराह कर रहे हैं। आप जो सेंट्रल पूल से ले रहे हैं, वह न बताएं।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, दूसरी बात इन्होंने कह दी कि चार पांच और प्लांट इनके वक्त में लगे। ये अगर कह देते कि आपने लगाए थे और गलती से इनके पोरियड में चालू हो गए तब तो ठीक था, मैं मान लेता। चौथा प्लांट जो हमारा 110 मैगावाट का है, उसको बनाने में कम से कम तीन साल से ज्यादा लगे। वह भी तब अगर उस पर दिन रात काम चले। वह चालू हुआ जनवरी 1987 में। इनका दावा केवल इस हद तक सही है। पांचवां प्लांट 210 मैगावाट का है जिसको पूरा करने में पांच साल चाहिए। इसका कूलिंग टावर ही डेढ़ साल से कम में पूरा नहीं हुआ था। वह मार्च 1989 में चालू हुआ था।

श्री सतबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, पांचवां यूनिट अक्टूबर 1990 में चालू हुआ था, इसके बारे में मन्त्री जी कन्फर्म कर लें।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, वह 28-3-1989 को कमिशन कर दिया गया था। उसको फाउंडेशन चौधरी भजन लाल ने रखी थी। इसके अलावा, इन्होंने कह दिया कि बिजली न होने की वजह से पानी नहीं मिल रहा है और किसानों की सारी फसलें जल गईं। मैं रिकार्ड की बात कहूंगा कि इस साल भगवान की कृपा से जितना धान हुआ है, उसने अब तक का हरियाणा का रिकार्ड तोड़ा है। इसी तरह से गेहूँ और सरसों की फसल भी रिकार्ड तोड़ेगी। इसके अलावा इन्होंने कह दिया कि इनके वक्त में प्लांट लोड फैक्टर कम थे। स्पीकर साहब, पानीपत अर्मल प्लांट में 1989-90 में 43.64 परसेंट लोड फैक्टर था, 1990-91 में 30.26 परसेंट था और उसके बाद जब हमने 1991-92 में टेकओवर किया तो 43.07 लोड फैक्टर थे। उसके बाद 1992-93 में 46.97 परसेंट और 1993-94 में इस वक्त 36.26 परसेंट है जबकि पॉंग डैम में पानी कम था। आज के दिन बिजली जनरेशन की 50 परसेंट की एवरेज है। इस हालत में यह कहना कि बिजली इन्होंने दी, यह बिल्कुल सरासर गलत बात है। इन्होंने कह दिया कि अर्मल प्लांट एन० टी० पी० सी० को सीमा जा रहा है। स्पीकर साहब, सरकार के पास तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इनकी पार्टी के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि एन० टी० पी० सी० को दे दो और कुछ मंत्री कह रहे हैं कि न दो। अब इस बात का ये आपस में निपटारा कर लें।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मंत्री जी हाउस को गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज के दिन हमारी स्टेट में कोई भी थर्मल प्लांट ऐसा नहीं है, जो बंद पड़ा हो। मैं इनको बताना चाहूंगा कि पानीपत के थर्मल प्लांट की एक से तीन यूनिट आज भी बंद पड़ी हैं और चौथी यूनिट एक दो दिन में बंद होने वाली है।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, थर्मल प्लांट के बारे में तो मैंने अभी कोई जिक्र किया ही नहीं है।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने कहा कि 210 मेगावाट का यूनिट इनके वक्त में कमिशन हुआ था, यह गलत बात है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि उस यूनिट को चालू करने के लिए हमारी पार्टी के राज में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इनसैटिव दिया गया था। हमने इस यूनिट को बहुत जल्दी तैयार किया है। इसलिए अक्टूबर 1990 में वह यूनिट तैयार हो गया था, चालू हो गया था। उस यूनिट को 1990 में चालू करने पर हमारी सरकार ने कर्मचारियों को बतौर इनसैटिव ईनाम दिए थे।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य के प्वायंट ऑफ आर्डर को समझ नहीं पाया, शायद माननीय सदस्य अपनी मौजूदगी यहाँ लिखवाना चाहते हैं। इसके अलावा, इन्होंने कह दिया कि बिजली की चोरी है और लाइन लोसिज बहुत ज्यादा हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आपके वक्त में भी लाइन लोसिज बहुत ज्यादा थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 1989-90 में 29.01 परसेंट लाइन लोसिज थे। वर्ष 1990-91 में 27.58 परसेंट थे। वर्ष 1991-92 में 27.27 परसेंट थे। 1992-93 में 25.22 परसेंट थे। 1993-94 में 27.97 परसेंट हैं। यह मैं आपको रिकार्ड की बात बता रहा हूँ। स्पीकर साहब, इन्होंने कह दिया कि 20 हजार ट्रांसफार्मर डैमेज हुए। ट्रांसफार्मर डैमेज होने का टेक्नीकल प्रोसेस है। ट्रांसफार्मर बिजली के ओवर लोड होने के कारण डैमेज होते हैं। जिन हालात में पांच हाई पावर की मोटर चलानी चाहिए, उन हालात में लॉग 10 और 12 हाई पावर की मोटरें जलाते हैं तो वह लोड ट्रांसफार्मर पर ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी यह क्रेडिट हमारी सरकार को जाता है कि आज के दिन एप्रैकल्वर सैक्टर में डैमेज हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में 3 या 4 दिन नहीं लगाते, केवल दो ही दिन में बदल देते हैं। इसके अलावा, इन्होंने कह दिया कि मैटीरियल सब-स्टैंडर्ड है। स्पीकर साहब, जहां तक थर्मल प्लांट के मैटीरियल का ताल्लुक है, थर्मल प्लांट का मैटीरियल हम बी० एच० ई० एल० से लेते हैं, उससे अच्छा मैटीरियल सप्लायर कोई और नहीं हो सकता। जो जनरल मैटीरियल है, उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, उसको हम समय समय पर चेक भी करते रहते हैं। स्पीकर साहब, इन्होंने एक बात कह दी कि एप्रैकल्वर सैक्टर में बिजली की मोमीनल चोरी हो रही है लेकिन

इंडस्ट्रीयल सेक्टर में सबसे अधिक चोरी हो रही है और कह दिया कि वह चोरी ये खुद करवा रहे हैं। स्पीकर साहब, जो बिजली के बल्क कंज्यूमर हैं, उनके लिए हमने डिजिटल मीटर लगा दिए हैं। उस मीटर के अन्दर मीमोरी है यदि कोई आदमी उसको छेड़ने की कोशिश करेगा तो वह रीडिंग के बक्त पकड़ा जा सकता है। बिजली की चोरी के मामले में उनकी बात सही है। मैं उसको डिताई नहीं करता लेकिन हम बिजली की चोरी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको चेक करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी ने हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में सुझाव दिया कि हाइडल प्रोजेक्ट अधिक से अधिक लगाये जाने चाहिये। हमने इस बारे में जागरूकता बरती है और हमारी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक हाइडल प्रोजेक्ट लगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सिज प्राप्त हो सकें। अध्यक्ष महोदय, साथ ही चौधरी बंसी लाल जी ने बताया कि जब भाखड़ा के पानी में हमारा 52 परसेंट डेयर है तो बिजली में भी उसी हिसाब से शेयर होना चाहिये। यह बात कल ही ये नोटिस में लाये। इसको एग्जाभिन करेंगे और इस सुझाव पर पूरी तरह से विचार करेंगे। बोलते हुए राम विलास शर्मा जी ने टाटा वालों का जिक्र किया कि उनके वहां पर बिजली कभी भी नहीं जाती। इस बारे में मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उनको जितनी बिजली की जरूरत है, उससे ज्यादा उनकी प्रोडक्शन है, इसलिए वहां पर बिजली जाती ही नहीं। हम 55 से 65 परसेंट बिजली एग्रीकल्चर साइड में देते हैं, जिसके ऊपर हमें किसानों को सबसिडी देनी पड़ती है जबकि उनके यहां पर ऐसा नहीं है। साथ ही इन्होंने बोलते हुए कहा कि महेन्द्रगढ़ में फसल सूख गई है। मैं इस बारे में सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि इस साल महेन्द्रगढ़ में भी इतनी अधिक फसल पैदा होगी जो आज तक कभी भी नहीं हुई होगी। जहां पर पानी की कमी है, वहां पर हमने बिजली भी पहुंचवाई है ताकि लोग अपने ट्यूबवैलों से सिंचाई कर सकें। इसलिए इस मामले में इतकी कोई इत्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। जब फसल आयेगी तो पता चल जायेगा कि वहां पर फसल कम हुई है या अधिक। धन्यवाद।

वित्त मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैंने 7-3-94 को इस हाउस में 1994-95 का बजट अनुमान पेश किया। माननीय सदस्यों ने बजट अनुमानों पर विस्तार से चर्चा की है। जहाँ ट्रेजरी बेंचिज के माननीय सदस्य हैं, स्वाभाविक है कि उन्होंने सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना की और विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी अपने कर्तव्य को निभाने का पूरा-पूरा प्रयास किया है। विरोधी पक्ष के भाइयों ने बोलते हुए कुछ सुझाव भी दिए और अपनी नाराजगी भी जाहिर की है, साथ ही कहा गया कि इस बजट में आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई और साथ ही कहा गया कि न तो किसानों के हितों का ध्यान रखा गया, न व्यापारियों का ध्यान रखा गया, न हजिजों का हित ध्यान में रखा गया।

[श्री मंगे राम गुप्ता]

राम बिलास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस बजट में किसी के लिए कोई भी सुविधा या लाभ नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जब बजट हाउस में पेश किया जाता है और अगले दिन अखबारों में छपता है तो उस वारे में आम लोगों की प्रतिक्रियाएँ और प्रस की अपनी प्रतिक्रियाएँ होती हैं कि बजट अच्छा है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपने किसी भी अखबार से यह नहीं पढ़ा होगा कि इससे आम लोगों का हित नहीं होगा। हर तरफ इस बजट को सराहा गया है। (तालियाँ) हमारे बजट की व्यापारियों ने सराहना की, किसानों ने की, और आम तबके के लोगों ने की। अध्यक्ष महोदय, सदन में दो ही प्रमुख विरोधी पार्टियाँ हैं, एक सजपा और दूसरी हरियाणा विकास पार्टी, जिसके लीडर चौधरी बंसी लाल जी हैं, वे भी मुख्य मन्त्री रहे हुए हैं। दोनों नेताओं ने इन बजट अनुमानों पर काफी चर्चा की। चौधरी ओम प्रकाश जी ने बड़ी गहराई से इस बजट को पढ़ने का प्रयास किया या किसी अच्छे सलाहकार ने इनको बजट के बारे में ब्रीफ करवाने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी स्पीच में आँकड़ों की चर्चा की है, स्पीकर साहब, बजट आँकड़ों से ही बनता है और आँकड़ों की तरफ ध्यान दिलाना एक अच्छी बात है। मैं इसमें कोई दुराई नहीं मानता। बजट में अगर कोई खामियाँ रह गई हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश जी को जिस व्यक्ति ने ब्रीफ करवाया या तो वह जल्दी में था या ओम प्रकाश जी खुद जल्दी में थे। बजट फिगरज को समझना आसान काम नहीं है। चौधरी साहब को ब्रीफ करवाने वाले ने जितना ब्रीफ करवाया, उतनी बात इन्होंने कह दी। इन्होंने इस बात को माना कि वैसे तो यह बजट टैक्स रहित है परन्तु इन्होंने संशय जाहिर कर दिया कि टैक्स पहले से ही लगा दिए गए हैं और इन्होंने इस बातचीत में, खाद और तेल का जिक्र कर दिया। स्पीकर साहब, इन चीजों पर टैक्स लगाने में हरियाणा सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, हम लोग इन चीजों पर टैक्स लगा ही नहीं सकते। (विष्णु) बिजली के बारे में भी ए० सी० चौधरी ने विस्तार से जवाब दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पीने के पानी की चर्चा भी इन्होंने की। इन्होंने कहा कि बजट अनुमानों में इस पर 8.50 प्रतिशत का खर्च है जबकि प्रावधान 2.00 का किया गया है, इसलिए ये इसको किस प्रकार से करेंगे। इन्होंने संशय जाहिर किया कि पीने के पानी के रेट्स बढ़ाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी ओम प्रकाश जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि पीने के पानी के रेट्स बढ़ाने का हमारा कोई प्रावधान नहीं है और न ही पानी के रेट्स बढ़ाए जाएंगे। पिछले साल हमने म्युनिसिपल कमेटियों का वाटर सिस्टम बदल दिया था और म्युनिसिपल कमेटियों की वाटर बक्स सप्लाई पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दी गई थी। वाटर बक्स की सप्लाई का सारा खर्च अब पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा इसलिए वाटर रेट्स को बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इरिगेशन पर चर्चा करते हुए उन्होंने संशय जाहिर किया है कि इसके खर्च को कैसे पूरा किया जाएगा जब कि खर्च 42.63 का है और बजट प्रावधान 21. कुछ का किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य इस बारे में चिन्तित हैं और हमारी इस बारे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हरियाणा प्रान्त एक कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिये जब तक हरियाणा के किसान के खेत को पानी नहीं मिलेगा, तब तक अनाज कम पैदा होता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के किसान ने काफी कोशिश की है और केन्द्र में बहुत बड़ा अनाज का भण्डार भेजा है। अगर किसान के खेत को पूरा पानी मिले तो पैदावार और भी ज्यादा रिकार्ड तोड़ ही सकती है। जितनी पैदावार अधिक होगी, उतना ही प्रदेश का विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, नहरों में पानी लाने के लिए, नई नहरें बनाने के लिए, खालों को पक्का करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। स्टेट के जो आमदन के साधन हैं, वह इतने ज्यादा नहीं हैं कि इन सारे कामों को पूरा करने के लिए पूरा पैसा सरकार इरिगेशन डिपार्टमेंट को डिस्ट्रिब्यूट कर सके। अध्यक्ष महोदय, जो खाल टूट गए हैं उनको मरम्मत करने की जरूरत है, नई खालें बनानी हैं और डी-सिल्टिंग के बारे में भी यहाँ पर बार-बार चर्चा होती रही है और माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि नहरें अटी पड़ी हैं, उनको डी-सिल्टिंग करवाई जाए। इसके लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना कर सरकार को भेजा है, एक योजना बना कर सरकार को दी है। सरकार के पास अपने साधन इस वक्त इतने नहीं हैं कि इन सारे कामों को करवा सके। इसलिये सरकार ने योजना बनाई है कि इन कामों के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया जाए। उसी के मुताबिक आठ सौ करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। यह प्रोजेक्ट पांच साल में नहरों के लिए, डी-सिल्टिंग के लिए और खालों को पक्का करवाने के लिए बना है। कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक की टीम हमारे यहाँ पर आई थी। उसने हरियाणा की कारगुजारी देखकर कहा कि हम पैसे तो दे देंगे लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी। उन्होंने कहा कि 1970 में टेक्स रेज करने की कोई स्कीम नहीं बनाई। तो उन्होंने हमारे इरिगेशन मिनिस्टर के साथ बैठकर बात की और इसको थोड़ा-सा इन्क्रीज करने का फैसला हो गया। हमने इरिगेशन सेक्टर में 10 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया है। हमारा जो पानी किसान को सप्लाई होता है, उससे मार्केट बोर्ड को आमदनी होगी, उसमें 42 करोड़ रुपए हमारे इन्क्रीज होंगे। जब हमने वर्ल्ड बैंक को यह प्रोजेक्ट दिया तो वे खुश ही गए और आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि वर्ल्ड बैंक ने हमारी आठ सौ करोड़ रुपए की स्कीम मान ली है। अध्यक्ष महोदय, 10 प्रतिशत बढ़ाने से हरियाणा के किसानों के ऊपर 1 करोड़ 42 लाख रुपए पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, जब भी इस हाउस में चर्चा होती है तो एस0 वाई0 एल0 के बारे में बड़ी चर्चा होती है। ये एस0 वाई0 एल0 के बारे में बहुत चिन्ता करते हैं, यह अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, इस नहर का बनना हरियाणा के लिए जीवन, मरण का सवाल है। उन्होंने पंजाब का भी जिक्र किया है। मेरे विरोधी पक्ष वाले साथी कहते हैं कि इस

[श्री मांगे राम गुप्ता]

पर जो कुछ खर्च किया है, वह इन्होंने ही किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने ही प्रस्ताव पास करवाया है और पूरी गारन्टी के साथ प्रस्ताव पास किया है। श्रीम प्रकाश जी बोलते हैं कि हमारी सरकार पंजाब से दबती है, केन्द्र से दबती है। अध्यक्ष महोदय, 26 सितम्बर को जालन्धर में एक बहुत बड़ा प्रहीदी दिवस मनाया गया। उसमें पंजाब के मुख्य मन्त्री जी अध्यक्षता कर रहे थे और हरियाणा के मुख्य मन्त्री जी को चीफ गेस्ट के तौर पर जाना था, लेकिन जहूरी मीटिंग होने की वजह से वे नहीं जा पाए। वहाँ पर बहुत से विरोधी पक्ष के लोग भी गए हुए थे। लेकिन कुछ दिन पहले एक बहुत जहूरी मीटिंग सेंटर में आयी जिसकी वजह से आदरणीय मुख्य मन्त्री जी उस फंक्शन में नहीं जा सके और इन्होंने दिल्ली से मेरे को आदेश दिया कि चूंकि इन्होंने वह न्यौता स्वीकार किया हुआ है इसलिए मैं ही इनके बिहाफ पर उस फंक्शन में चला जाऊँ। इसलिये मैं 26 सितम्बर के फंक्शन में गया। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर अकाली नेताओं ने बोलते हुए पंजाब के मुख्य मन्त्री पर एक चोट कर दी और वे कहने लगे कि बेअनत सिंह जी, पंजाब की जनता ने आपको यह सोचकर मुख्य मन्त्री बनाया है कि पंजाब के हितों की रक्षा करें। हरियाणा, पंजाब के साथ बड़ी बेइन्साफी कर रहा है। जो पंजाबी भाषी इलाके हैं और चण्डीगढ़ का इलाका है, वह हरियाणा आज तक भी पंजाब को नहीं दे रहा है लेकिन पंजाब के लोग इस बेइन्साफी को बढ़ाई नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वहाँ पर हरियाणा की तूमाइन्दगी कर रहा था। हरियाणा की धरती पर तो सब लोग बोलते होंगे, जैसे अभी दो दिन पहले ही ये प्रस्ताव पारित करने की बात कर रहे थे लेकिन मैंने पंजाब की धरती पर ही कहा था, जिस धरती पर उग्रवादियों ने श्री बिट्टा पर बमों से हमले किए थे। बिट्टा भी उस सम्मेलन में मौजूद था, जिसको उग्रवादियों ने मारने का षडयन्त्र किया था। उसी पंजाब की धरती आनि जालन्धर में हमने जवाब दिया था, जिस पर पंजाब का एक भी अकाली लीडर नहीं बोल सका था। जो कुछ मैंने कहा था, वह एक अखबार में छपा हुआ है जिसका हेडिंग है "राजनीतिक नेता नाइन्साफी के नाम पर पंजाब व हरियाणा के विवादों को न उठाए"। अध्यक्ष महोदय, जो इस अखबार में दिया है, मैं आपको उसकी चन्द लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। यह मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि हरियाणा की सरकार नपुंसक है। अध्यक्ष महोदय, अखबार में लिखा है— श्री मांगे राम गुप्ता, जो अपने से पूर्व कुछ वक्ताओं द्वारा पंजाब से नाइन्साफी का मामला उठाए जाने के दृष्टिकोण अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, ने कहा कि वह यह नहीं सोच कर आए थे कि इस समारोह में ये राजनीतिक मुद्दे उठाए जाएंगे। अब जब यह मुद्दे उठाए ही गए हैं और विशेषकर पंजाब से नाइन्साफी के नाम पर, तो उनके लिए कुछ कहना अनिवार्य हो गया है। श्री गुप्ता ने कहा कि पहली बात तो यह नहीं समझ पा रहे कि पंजाब के साथ नाइन्साफी क्या हुई और यह किसने की है? उन्होंने कहा कि हरियाणा तो पंजाबी बुरा भोगने

वालों ने जबरदस्ती बनवाया और वह कह सकते हैं कि पंजाब बड़ा भाई है और हरियाणा छोटा भाई। इस दृष्टि से यह ध्यान में रखना भी जरूरी है कि पुनर्गठन के समय जो दोनों राज्यों की लेन-देन की जिम्मेदारियां तय हुई थीं, वह हरियाणा पूरी तरह निभा रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि पंजाब व हरियाणा के बीच पानी आदि के मामलों को भी उच्चस्तरीय नेताओं ने दोनों राज्यों की सहमति से निपटाया, किन्तु उन पर अमल नहीं किया गया और उसमें पंजाब का ही हाथ रहा, हरियाणा का नहीं। इसलिए वे कह सकते हैं कि नाइन्साफी यदि हुई है तो हरियाणा से हुई है। पानी तो अभी भी सारा पंजाब के पास है, मगर हरियाणा की नहर का निर्माण रुका हुआ है।

श्री गुप्ता ने कहा कि वह श्री बेअंत सिंह से कहेंगे कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि बड़े भाई के नाते पंजाब हरियाणा से न्याय करे, इन्साफ दे, नहर का पानी दे।”

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी यही मान्यता है कि इन मुद्दों को जल्दी ही निपटाया जाए। इन मुद्दों को राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। आगे इस अखबार में कहा गया है—“श्री गुप्ता ने कहा कि पानी का मामला राजनीति व वोट का नहीं, किसान की भूमि को पानी देने का है, चाहे वह किसान पंजाब का है या हरियाणा का। यदि हम देश की एकता की दृष्टि से विचार करेंगे तो इस मामले को निपटाने में भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती।”

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक लाइन और पढ़ना चाहूंगा। मैंने जो कुछ वहां पर कहा था, उसके जवाब में सरदार बेअंत सिंह जी ने कहा—“गुप्ता जी, मुझे दुख है कि हमारे कुछ नेताओं ने इस तरह की बातें कही जो इस समय नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार हरियाणा के साथ विवाद-वार्ता से हल करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार एस० वाई० एल० नहर के निर्माण के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बादल का नाम लेकर कहा कि जो लोग उसका विरोध करते हैं, यह वही हैं जिन्होंने इस नहर के लिए अपनी सरकार के समय भूमि अधिग्रहण की थी और नहर निर्माण के लिए उस समय के हरियाणा के मुख्य-मन्त्री से एक करोड़ रूपया लिया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एस० वाई० एल० के निर्माण के लिए वचनबद्ध है। (शोर) मैं यही कह रहा हूँ, आप यह कैसे कह रहे हैं? आप किसानों को जाकर भड़काएँ कि हरियाणा सरकार एस० वाई० एल० के निर्माण के लिए कोशिश नहीं करती। हम लोग तो अपनी जान की बाजी लगाकर एस० वाई० एल० के निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप कितना टाईम और लेगे ?

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : दो बजे तक बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये ।

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1994-95 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनराारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) अध्यक्ष महोदय, एस0 वाई0 एल0 के लिए हमने इस बजट में 16 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान किया है

श्री0 राम विलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। गुप्ता जी ने बड़ा ठीक फर्माया। इन्होंने जालन्धर में जाकर बड़ी बहादुरी की बात कही। परन्तु जो बजट इन्होंने खुद बनाया है, खुद प्रस्तुत किया है, उसमें एस0 वाई0 एल0 के लिए जो प्रावधान रखा है, वो मैंने पढ़ा है, उसमें कोई पैसा नहीं रखा है, इन्होंने सिर्फ उम्मीद जाहिर की है कि हमें आशा है कि पंजाब में कानून और व्यवस्था में सुधार होने के बाद नहर का निर्माण होगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बहुत से सवालियों का जवाब आप रोज देख रहे हैं। गवर्नर ऐड्रेस पर बहस हुई। विरोधी पक्ष के लोगों ने स्कूलों की अप-ग्रेडिंग के, हॉस्पिटल के, रोड्स के मसले उठाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब देते हुए बहुत सी बातों का जवाब दे दिया। वैसे बीच में भी बहुत-से जवाब आए हैं जिनसे माननीय सदस्यों की तसल्ली हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो कर-देते हैं। अध्यक्ष महोदय, संपत सिंह जी ने और श्रीम प्रकाश बेरी जी ने चर्चा करते हुए कहा कि लाटरी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है लेकिन मूनाफा थोड़ा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, लाटरी बन्द होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमने यह लाटरी बन्द कर दी थी तो संपत सिंह ने यह कहा था कि इससे 4-5 करोड़ का लाभ होता था, इन्होंने सत्यानाश कर दिया और नौकरीपेशा लोगों को हटा दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने उसी वक्त इनको हाउस में चैलेन्ज करते हुए कहा था कि अगर प्रोफेसर संपत सिंह जी यह चाहते हैं कि हम एक बार फिर लाटरी को दोबारा वापस करें-

तो हम इसको दोबारा भी चालू कर देंगे। डेली लाटरी में कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, पिछली बार भी इस बारे में यहाँ पर जिक्र आया था। मैंने उस समय यह कहा था कि ऐसे एजेंट के हाथ में इन्होंने लाटरी की टिकटें दे दीं जो इनके पैसे खाकर भाग गया, रफ्तू चक्कर हो गया और इनकी सरकार को चूना लगा गया। इस वजह से इनके अधिकारी फंसे पड़े हैं। इस बारे में बाकायदा मेरा इन्टरव्यू भी टी० वी० पर आया और श्री मांगे राम गुप्ता जी का इन्टरव्यू भी टी० वी० पर आया था। मैंने उस वक्त यह कहा था कि यह लाटरी बन्द करनी चाहिये। चूंकि यह सेंट्रल एक्ट के तहत है, इसलिये हम इसको अपने आप बन्द नहीं कर पायेंगे, इसलिये हम अपनी रिजोर्मेंटेशन दे सकते हैं और उनसे यह कह सकते हैं कि इसे बन्द करें आज भी हम उसी स्टीड पर कायम हैं कि इसको बन्द करना चाहिये।

बौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, कल रात को जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो मैंने यह देखा कि राजस्थान सरकार की कोई डेली लाटरी थी, वह उन्होंने बन्द कर दी है। उन्होंने यह लाटरी यह कहते हुए बन्द कर दी है कि इससे गरीब आदमी मारे जाते हैं। आपको भी डेली लाटरी को बन्द करने पर विचार करना चाहिये। आप बेशक लम्बी लाटरी चलाने दो लेकिन डेली लाटरी को बन्द करने पर आपको विचार करना चाहिये।

श्री मांगे राम गुप्ता : न तो यह हमारी आमदनी का जरिया है और न ही इसमें कोई इन्कम का सवाल है। इस के बारे में जैसे प्रो० सम्पत सिंह ने यह कहा है कि इसको बन्द किया जाये, इसके लिये पार्लियामेंट एक्ट बना हुआ है। बाकायदा सेंट्रल एक्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। यह तो पार्लियामेंट की पावर की बात है, हम यह पास नहीं कर सकते कि इसको बन्द किया जाये। हम तो हरियाणा सरकार की तरफ से चलने वाली लाटरी को ही बन्द कर सकते हैं। हम तो अपनी तरफ से चलने वाली लाटरी को ही बन्द कर सकते हैं लेकिन जो दूसरे प्रदेशों की लाटरी है, उसको हम बन्द नहीं कर सकते। जितनी प्राइवेट लाटरीज थीं, जो पहले कुछ लोगों ने खोल रखी थीं, वह हमारी सरकार ने बन्द कर दी हैं, इनसे लोगों के साथ ठगती होती थी। इसके अलावा, एम० पी० ने लाटरी बन्द कर दी है। मैं यह विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यह जो डेली लाटरी चल रही है, हम उसको बन्द करने के बारे में विचार कर सकते हैं लेकिन समस्या तो इस बात की है कि हमारी इसके अन्दर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस काम में 100 तो रंगुलर लड़के लगे हुए हैं, 350 डेली बेजिज पर लड़के काम कर रहे हैं। इस तरह साढ़े चार सौ लड़के इसी वजह से रोजगार पर लगे हुए हैं। इसके अलावा, इन्डायरेक्ट तरीके से भी बहुत से लोग इस काम में लगे हुए हैं। इसे बन्द करना कोई समाधान नहीं है। कल की अगर हम बन्द कर देंगे तो इन लड़कों को कहाँ पर सेनायें ?

प्रो० सत्यत सिंह : और महकमों में लगा दो ।

श्री मंगे राम गुप्ता : यह इतना आसान नहीं है ।

श्रीधरी श्याम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी ने यह कहा है कि स्टैल गवर्नमेंट का आदेश है, इसलिये हम इसको बन्द नहीं कर सकते । आपकी यह बात तो हम समझ सकते हैं लेकिन हम इसका तरीका तो बदल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इनका कहना यह है कि अगर हम बन्द कर देंगे तो भी बाहर की लाटरीज तो वहाँ पर चलेगी ।

श्रीधरी श्याम प्रकाश चौटाला : इनकी यह बात ठीक है कि बाहर की लाटरीज की तो ये बन्द नहीं कर सकते लेकिन सरकार जो डेली लाटरी चला रही है, सर्व-प्रथम तो इसकी प्रिंटिंग के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन 80 हजार रुपये अधिक देते हैं, जबकि दूसरे लोग जो प्राइवेट लाटरीज चलाते हैं, वे टिकटों को सस्ते में छपवाते हैं । वे कम में छपवाते हैं जबकि सरकार 80 हजार रुपये से ज्यादा देती है । ये तो यह कह रहे हैं कि साढ़े चार सौ कर्मचारी एजेंट्स किये हुए हैं लेकिन 80,000 रुपये से ज्यादा, सरकारी रिकार्ड के मुताबिक, रोझाना अकेले इस बात पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं जबकि दूसरे प्राइवेट वाले इनसे कम पैसों में छपवाते हैं । साईज टिकटों का वही है, कागज वही है और उनकी टिकटों की शक्ल भी ज्यादा सुधरी है । दूसरी तरफ यह भी माना है कि 90 करोड़ रुपये का लाभ इससे होता है । 800 करोड़ रुपये गरीब लोगों से ले जाते हैं और उसमें से 600 करोड़ रुपये कमीशन एजेंट्स को दिया जाता है । आपकी बजह से कमीशन एजेंट्स भी कमा लेते हैं । सरकारी खजाने में तो केवल 90 करोड़ रुपये ही आता है । वित्त मंत्री जी जरा स्पष्ट करें कि हरियाणा सरकार यह लाटरी क्या कमीशन एजेंट्स के लिये चला रही है ?

श्री मंगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, श्याम प्रकाश चौटाला ने जो फरमाया, उसके बारे में इन्होंने गहराई से नहीं सोचा । जहाँ तक टिकटों की छपाई का सवाल है, हमारी लाटरी प्राइवेट लाटरी की तरह से नहीं है । मैं पूरे चैलेन्ज के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा की लाटरी का डिजाइन, छपाई और कागज हिन्दुस्तान में सभी लाटरीज के मुकाबले में बढ़िया है ।

श्रीधरी श्याम प्रकाश चौटाला : इससे स्टेट का क्या लाभ होने जा रहा है ?

श्री मंगे राम गुप्ता : मैंने रेट कोई अपने घर में तो बनाए नहीं है । जो रेट दूसरी स्टेट्स में है, वही हमारे यहाँ है । आपको समय लाटरीज की ट्रांसपोर्टेशन का रेट 375 या 300 रुपए प्रति क्विंटल था लेकिन आज 75 रुपये प्रति क्विंटल है ।

श्रीवरो श्रीम प्रकाश चौडाला : स्पीकर साहब, मैं सरकारी रिकार्ड से बताना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट छोटी लाटरीज हैं, वे 2272 रुपये प्रति लाख छपती हैं और आपकी लाटरीज 2900.00 रुपये प्रति लाख छपती है। बड़ी लाटरीज जो प्राइवेट है, वे 3050 रुपये प्रति लाख छपती हैं और हमारी सरकार छपवाती है 3750.00 रुपये प्रति लाख। स्पीकर साहब, यह अन्तर है हमारी लाटरी की छपाई में और प्राइवेट लाटरी की छपाई में। एक करोड़ लाटरीज रोज छपती है, इस तरह अस्सी हजार रुपये रोज का मुकदान हो रहा है। लाटरी पर जो खर्च आ रहा है, वह 670 करोड़ है और जो वसूल होता है, वह है 760 करोड़ रुपये। नब्बे करोड़ रुपये हरियाणा सरकार को मिलेंगे और इसमें आठ सौ करोड़ रुपये उन लोगों से वसूल किया जाएगा जो रिकशा पुलर हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं। छः सौ करोड़ रुपये कमीशन एजेंट को मिलेगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, लाटरीज में श्रीम प्रकाश चौडाला जैसे बड़े-बड़े आदमी, जिनके पास बहुत पैसा है, वे अपना भाग्य आजमाते हैं। स्पीकर साहब, जहाँ तक छपाई के रेट्स का सवाल है, वह कोई मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं दे रहा हूँ। सरकार ने बाकायदा एम्बरटाईजमेंट दिया, टैम्बर आए और जो लोएस्ट टैम्बर था, उसको काम दिया गया। सरकार जो भी मंटीरियल खरीदती है या बेचती है, उसके लिए टैम्बर काल किए जाते हैं। सरकार के पास कोई और तरीका नहीं है, सिवाए टैम्बर काल करने के। सरकार कोई प्राइवेट आदमी तो है नहीं जिसने आज यहाँ छपवा ली और कल दूसरी जगह छपवा ली। प्राइवेट आदमी तो दो दिन कहीं छपवाते हैं, उसके बाद कहीं और छपवा लेते हैं। लाटरी छपाई के लिए जो टैम्बर लोएस्ट था, उसी से छपवा ली। प्राइवेट लाटरी हमारे यहाँ छपती नहीं है और न ही हम उनका मुकाबला कर सकते हैं।

श्री० सम्पत सिंह : आपकी लाटरीज भी यहाँ नहीं छप रही, बाहर छप रही हैं। आप यह बताइए कि आपकी प्रिंटिंग प्रेस ने क्या रेट दिया था ?

श्री मांगे राम गुप्ता : हमारी प्रिंटिंग प्रेस अपनी लाटरीज को छाप नहीं सकती। उसको बाहर से ही छपवाना पड़ता है, चाहे वह कहीं से भी छपवाए।

श्री० राम प्रकाश : जिस प्रेस से छपवा रहे हैं, क्या सरकार उससे नेगोशिएट करके रेट कम कराने का प्रयास करेगी, और अगर वह नेगोशिएशन में रेट कम नहीं करती तो क्या उसके साथ कन्ट्रैक्ट खत्म करने पर सरकार विचार करेगी ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : आप कोई पार्टी ले आएँ, अगर वह कम रेट पर छापने के लिए तैयार होगी तो हम उससे छपवा लेंगे। स्पीकर साहब, कल इन्होंने कोई बात कही और जब मदान साहब ने इनको अपनी ओफिस दी तो वे बीछला गए।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

मैं फिर कहता हूँ कि आप किसी प्रैस वाले को ले जाएँ। अगर उसके रेट कम होंगे और हमारी बत्तों के मुताबिक छपाई करेगा तो हम छपवा लेंगे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, एक मिनट रुकिए। यदि हाउस की सहमति ही तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाज : जी हाँ, बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1994-95 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, हमने हर इंसान की जरूरत को समझते हुए बिल्कुल ठीक काम किया है, गलत नहीं किया है। इन्होंने बूढ़ों को पेंशन का जिक्र कर दिया और दूसरी तरफ हरियाणा के विकास की बातें भी बड़ी बढ़-चढ़ कर करते हैं। ये बड़े हितैषी बनते हैं हरियाणा के लोगों के। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लोगों को गुमराह करते हुए, कर्जा माफ करने की बात का प्रचार करते हुए राज लिया था लेकिन सारे हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति का भट्ठा बिठा दिया और बूढ़ों की नाममात्र की पेंशन स्कीम शुरू कर दी जिसको वे लोग सिर नहीं चढ़ा सके। हालत यहां तक खराब हो गई थी कि जब ये लोग गये तो बूढ़ों की 6-6 महीनों की पेंशन छोड़ गये, दे नहीं पाए थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये हमारी बात करते हैं कि हमने पेंशन बन्द कर दी। अध्यक्ष महोदय हमारी एक मजबूरी रही है, उसको हम मानकर चलते हैं। हरियाणा के अन्दर पीछे बाढ़ आ गई, दूसरा बिजली का काइसिज भी आ गया और तीसरा एम्पलाईज की स्ट्राइक हो गई जिसके कारण हमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिजली का बढ़ा भारी संकट आ गया। उधर एन० टी० पी० सी० वालों ने कहा कि आप हमारा पहला एरियर क्लीयर करो और करन्ट चांजिज दो, तभी हम आपको बिजली की सप्लाई देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सरकार को बिजली बोर्ड को पैसा देना था और पैसे का इन्तजाम करने के लिये सरकार को यह पता डलाना पड़ा कि सरकार ने कुछ समय के लिये पेंशन को रोकना लेकिन बन्द नहीं किया, ताकि पैसे की अदायगी एन० टी० पी० सी० को हो, बिजली की सप्लाई मुदतवस्तु भावित रहे ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। बड़ी

हमने किया। पांच छः महीने अगर किसी की पेंशन जमा हो गई और उसे इकट्ठा पैसा मिल जाए तो इसमें कौन सा अन्वय होगा ? इन आपोजीशन वालों के पास तो और कोई बात है नहीं जो कर सकें, सिवाये इसके कि गलत प्रकार लोगों के सामने करते रहें। हमें उस रोके हुए पैसे से बिजली मिल गई और किसानों का भला हुआ। (शोर)

श्री अध्यक्ष : भागे राम जी, इनका मतलब यह है कि जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है, उनको समय पर व इकट्ठी पेंशन मिल जायेगी न ?

श्री भागे राम गुप्ता : जी हां, अध्यक्ष महोदय, अवश्य पूरी-पूरी पेंशन मिलेगी, व मिलने का सबाल ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ यहाँ पर पथ-कर का भी जिक्र आया। इन लोगों ने बोलते हुए कहा कि सरकार को इससे 27 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। पहले हमें 42 करोड़ रुपये पथ-कर से आता था। इस विषय पर केन्द्र सरकार ने सारी स्टेटों को बुलाकर यह फैसला करवा दिया कि पथ-कर खत्म किया जाए और इसकी जगह लम्प-सम 5000 कर दिया जाए। इसके खिलाफ लोग कोर्ट में चले गये। कोर्ट ने लोगों को स्टे दे दिया इसलिए यह पथ-कर नोटिफिकेशन इशू न होने की वजह से सरकार को 27 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर कोर्ट में उन के हक में फैसला हो जाए तब हमें कुछ नहीं मिलेगा और नुकसान उस हालत में होगा।

इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, वाटर सप्लाई का मामला भी चर्चा का विषय रहा।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप कितना समय और लेंगे ?

श्री मन्त्री (श्री भागे राम गुप्ता) : मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1994-95 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनराारम्भ)

श्री सांग राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं वाटर सप्लाई के बारे में जिज्ञास कर रहा था कि सरकार लोगों को पीने का पानी हर गांव में देने की पूरी-पूरी कोशिश कर रही है। जो बड़े गांव हैं, उनकी जरूरत के मुताबिक, पानी की मिक्चर को बढ़ाने का प्रयास भी हमने किया है, इसके लिये पहले से ही हम चिन्तित हैं। आज मैं विधानसभा के बीच आ रहा हूँ कि हम गांव-गांव में पीने के पानी को कमी बिल्कुल नहीं रहने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, एजुकेशन के ऊपर भी सरकार का पूरा ध्यान है। इसी तरह से हस्पतालों के ऊपर भी पूरा ध्यान है, दवाइयों के ऊपर भी पूरा ध्यान है। इस सरकार का शरीर मजदूरों की तरफ भी पूरा ध्यान है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हरियाणा की जनता की तरफ यह सरकार पूरा ध्यान रखेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इन शब्दों के साथ स्पिकर साहब, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker: Now, the House stands adjourned till 2.00 p.m., the 15th March, 1994.

*13:51 hrs. | (The Sabha then adjourned till 2.00 p.m., on the Tuesday 15th March, 1994):

ANNEXURE—A

Appointment made on Daily Wages Basis

*746. Smt. Chandravati, : Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

- (a) the post-wise number of persons working on daily-wages in the Transport Department at present; and
 (b) whether any persons have been appointed on permanent/daily wages basis in Dadri Depot during the period from 1st January 1993, to date; if so, the names and addresses thereof ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल शाह):

(क) विवरणी अनुबन्ध-I पर संलग्न है।

(ख) विवरणी अनुबन्ध-II पर संलग्न है।

अनुबन्ध—I

परिवहन विभाग में दैनिक वेतन आधार पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की

पदवार संख्या (28-2-94 तक)

क्र०स०	पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या	क्र०स०	पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1.	हेल्पर	480	22.	गनमैन	21
2.	स्वीपर	119	23.	असिस्टेंट कुक	4
3.	वांशिंग ब्वाय	20	24.	मेट	22
4.	वाटर कैरियर	22	25.	कन्टीन अटेंडेंट	1
5.	कौकीदार	51	26.	मैसन	2
6.	पलम्बर	12	27.	लेबरर	2
7.	टिकट क्लेरीफायर	54	28.	पम्प ड्राईवर	5
8.	सेवादार	41	29.	सहायक कारपेन्टर	1
9.	कार्केटर लिपिक	11	30.	सहायक ब्लैकस्मिथ	1
10.	टेलीफोन अटेंडेंट	1	31.	सहायक वैल्वर	3
11.	वेटर	7	32.	सहायक फिटर	1
12.	सेबरमैन	8	33.	सहायक अपहोस्टर	1
13.	बालक	86	34.	कारपेन्टर	1
14.	परिचालक	91	35.	ब्लैक स्मिथ	2
15.	माली	19	36.	कुक	1
16.	बोरबर	2	37.	सहायक पेन्टर	4
17.	वांशरमैन	1	38.	क्लीनर	1
18.	स्टोरमैन	1	39.	सहायक विद्युत्कार	3
19.	सिग्नलरटी अटेंडेंट	31	40.	अनाकसर	1
20.	टाईपिस्ट	2	41.	ट्यूबवैल आपरेटर	6
21.	लिपिक	16	42.	अड्डा फीस आपरेटर	4
	कुल	1103		—कुल जोड़	1142

[श्री अमलीन पात्र शाह]

अनुबन्ध-II

हरियाणा रोडवेज चरलीदाहरी में दिनांक 1-1-93 से 28-2-94 तक नियुक्त किये गए परिचालकों वारे सूचना

नियुक्त व्यक्तियों की श्रेणी	नाम और पूरा पता	नियुक्ति तिथि	नियमित तदर्थ	नियमित/वैतन भोगी	कन्टेनर/ग्रुप	विवरण
1		3	4	5	6	7

परिचालक

1. रामपाल सख्त मिश्र राम गांव लीलोहेरी जिला रोहतक

4-5-93

सी/विसिम

रोजगार विभाग

के माध्यम से

इस लिपी में कोई

प्रतीक्षा सूची न

होने के कारण

आपात स्थिति में

उम्मीदवारों के

नाम हरियाणा

रोडवेज, गुडगाँवा

तथा रोहतक से

मगि गए।

2. कूल सिंह सपुल खकीर सिंह भाँव व डाकडाना रोहर जिला महेंद्रगढ़

3-5-93

3. चदि सिंह सपुल नेल राम गाँव व डाकडाना कर्णवास, जिला रिवाड़ी

12-5-93

	3	4	5	6	7
4. रणधीर सिंह सुपुत्र मोहर सिंह गाँव व डाकखाना माजरी (सोनीपत)	13-5-93			सी/वेसिस	रोजगार विभाग के माध्यम से। इस डिप्टी
5. रामभजन सुपुत्र सुबे सिंह गाँव व डाकखाना मादी बकतावरपुर (सोनीपत)	14-5-93			"	में कोई प्रतीक्षा
6. धर्मबीर सिंह सुपुत्र मुखलाब गाँव व डाकखाना जुलाही (जिला सोनीपत)	14-5-93			"	सूची न होने के कारण आपात स्थिति में उम्मीदवारों के
7. वेद प्रकाश सुपुत्र सुलतान सिंह गाँव व डाकखाना खोराना (जिला अलवर)	15-5-93			"	नाम हरियाणा
8. राम कुमार सुपुत्र रामभरण गाँव व डाकखाना खोराना (जिला सोनीपत)	21-5-93			"	रोडवेज, मुड़गाँव तथा रोहताक से
9. मतील कुमार सुपुत्र ओम प्रकाश गाँव व डाकखाना मुड़गाँव	7-6-93			"	मांगे गए।
10. दीनानाथ सुपुत्र अम्बरीश लाल गाँव व डाकखाना गुड़गाँव	7-6-93			"	"
11. जय प्रकाश सुपुत्र भरत सिंह गाँव व डाकखाना जमालपुर	7-6-93			"	"
12. जय किशोर सुपुत्र प्रताप सिंह टासपुर (फरीदाबाद)	7-6-93			"	"
13. योगी राम सुपुत्र कर्ण सिंह गाँव व डाकखाना दाहू (मुड़गाँव)	4-6-93			"	"
14. दुशाध चन्द सुपुत्र मुखराम गाँव व डाकखाना नूरपुर (मुड़गाँव)	7-6-93			"	"
15. अशपाल सुपुत्र जयमल गाँव व डाकखाना बिलखा (मुड़गाँव)	8-6-93			"	"
16. राम अक्षय सुपुत्र संगत राम गाँव व डाकखाना कौजू (भिवानी)	8-6-93			"	"
17. यशवि सिंह सुपुत्र रिकुणाल सिंह गाँव व डाकखाना चांगरोड़ (भिवानी)	8-12-93			"	रोजगार विभाग चादरी।
18. रणधीर सिंह सुपुत्र हवा सिंह गाँव व डाकखाना खरकी (भिवानी)	7-12-93			"	"
19. बिजेंद्र सिंह सुपुत्र निहाल सिंह गाँव व डाकखाना चादरी	8-12-93			"	"
	7-12-93			"	"

1	2	3	4	5	6	7
					सी/बिसिस	रोजगार विभाग
20.	महावीर सिंह सुपुत्र साजू गाँव व डाकखाना बाम्बला (भिवानी)	8-12-93			"	दादरी
21.	जयवीर सुपुत्र हरकिशन गाँव व डाकखाना जोजू (भिवानी)	8-12-93			"	"
22.	राम निवास सुपुत्र सुरजीत सिंह गाँव व डाकखाना जमालपुर (भिवानी)	11-12-93			"	"
23.	कश्मीरी बाल सुपुत्र पूर्ण सिंह गाँव व डाकखाना ढाणी फोगाट (भिवानी)	7-12-93			"	"
24.	किरणलाल सिंह सुपुत्र पारस राम गाँव व डाकखाना जोजू कला (भिवानी)	7-12-93			"	"
25.	महावीर सिंह सुपुत्र शेर गाँव व डाकखाना महिरा (भिवानी)	8-12-93			"	"
26.	रामफल पुत्र टेक चन्द गाँव व डाकखाना रिनिला (भिवानी)	8-12-93			"	"
27.	सुरजीत सुपुत्र राम सिंह गाँव व डाकखाना हेलवास (भिवानी)	8-12-93			"	"
28.	सत्यवान सिंह सुपुत्र हवा सिंह गाँव व डाकखाना पंचगाँव (भिवानी)	8-12-93			"	"
29.	परमिंद कुमार सुपुत्र गोखुल राम गाँव व डाकखाना दतौली (भिवानी)	8-12-93			"	"
30.	कर्ण सिंह सुपुत्र हरसहय गाँव व डाकखाना ढाणी फोगाट (भिवानी)	8-12-93			"	"
31.	शर्मवीर सुपुत्र हरफूल गाँव व डाकखाना चरखी (भिवानी)	8-12-93			"	"
32.	राज सिंह पुत्र शर्मवीर सिंह गाँव व डाकखाना खेड़ी हलमवाय (भिवानी)	8-12-93			"	"
33.	कर्ण सिंह पुत्र मंसा राम गाँव व डाकखाना नन्दा (भिवानी)	16-12-93			"	"
34.	सुमेर सिंह पुत्र उदमी राम गाँव व डाकखाना बीरान (भिवानी)	8-12-93			"	"
35.	रामफल पुत्र चन्दागीराम गाँव व डाकखाना मंडोल (भिवानी)	8-12-93			"	"

	1	2	3	4	5	6	7
36.	सुरेश पुत्र जयदयाल गाँव व डाकखाना बवानी खेडा (भिवानी)	8-12-93	सी/बि/सिस	कर्मशाला में पहले से दैनिक वेतन पर लगा हुआ है।			
37.	देवकी नन्दन पुत्र रूप चन्द गाँव व डा10 झज्वर (रोहतक)	13-12-93	"	हड़ताल के दौरान विभागीय कमेटी की सिफारिश पर लगाया गया।			
38.	राजेश कुमार पुत्र गोपी राम गाँव व डाकखाना सिद्वाना (भिवानी)	9-12-93	"	"			
39.	अजीत सिंह पुत्र भरत सिंह खेरी बुरा (भिवानी)	9-12-93	"	"			
40.	कृष्णदीप पुत्र हरिकृष्णन गाँव व डाकखाना हिंदोला (भिवानी)	10-12-93	"	"			
41.	श्रीम प्रकाश पुत्र भरत सिंह गाँव व डाकखाना इमलोटा (भिवानी)	10-12-93	"	"			
42.	सतीश कुमार पुत्र होशियार सिंह गाँव व डाकखाना दादरी	10-12-93	"	"			
43.	अशोक कुमार पुत्र संसा राम गाँव व डाकखाना बलाल (भिवानी)	10-12-93	"	"			
44.	नरेश कुमार पुत्र नरयु राम गाँव व डाकखाना (रिवाडी)	10-12-93	"	"			
45.	राजवीर सिंह पुत्र बलबीर गाँव व डाकखाना नौमली (भिवानी)	9-12-93	"	"			
46.	विजय सिंह पुत्र रण सिंह गाँव व डाकखाना रावलधी (भिवानी)	10-12-93	"	"			
47.	देवानन्द पुत्र टेक राम गाँव व डाकखाना रावलधी (भिवानी)	10-12-93	"	"			

[श्री बलवीर पाल शर्मा]

1	2	3	4	5	6	7
48.	सुरेन्द्र पुत्र सुस्ताव शर्मा गाँव व डाकखाना रावलधी (भिवानी)	10-12-93			श्री विजिस	हस्ताल के दौरान
49.	दीप चन्द पुत्र राम कुमार गाँव व डाकखाना रावलधी (भिवानी)	10-12-93			"	विभागीय क्रमेट्री
50.	मीन सिंह पुत्र धनपत सिंह गाँव व डाकखाना पोटा (महेन्द्रगढ़)	10-12-93			"	की सिफारिश
51.	रासपत पुत्र भगवाना गाँव व डाकखाना सोथ (भिवानी)	10-12-93			"	पर लगाना तथा
52.	ईश्वर सिंह पुत्र सुभाष गाँव व डाकखाना दादरी	10-12-93			"	"
53.	दलवीर सिंह पुत्र जीता राम गाँव व डाकखाना भिनाल (भिवानी)	10-12-93			"	"
54.	जितेन्द्र कुमार पुत्र वगारावत सिंह गाँव व डाकखाना डबवास (भिवानी)	8-12-93			"	"
55.	सतनारायण पुत्र गुरुजारी लाल गाँव व डाकखाना लोहरा	8-12-93			"	"
56.	पन्नी सिंह पुत्र सिध राम गाँव व डाकखाना डलवास (भिवानी)	8-12-93			"	"
57.	सुरेश कुमार पुत्र सुबे सिंह गाँव व डाकखाना हुई (भिवानी)	8-12-93			"	"
58.	पवत कुमार पुत्र अमर सिंह गाँव व डाकखाना गोपी (भिवानी)	8-12-93			"	"
59.	राजेश कुमार पुत्र जारा चन्द गाँव व डाकखाना	8-12-93			"	"
60.	संजय कुमार पुत्र जिले सिंह गाँव व डाकखाना मुदमा (भिवानी)	8-12-93			"	"
61.	वेद प्रकाश पुत्र श्री चन्द गाँव व डाकखाना भिवानी	8-12-93			"	"
62.	चबन कुमार पुत्र किशोरी लाल गाँव व डाकखाना चहर (भिवानी)	"			"	"
63.	अतर सिंह पुत्र नरपाल सिंह गाँव व डाकखाना मसिट (रवाडी)	8-12-93			"	"
64.	विजेन्द्र पुत्र रणधीर गाँव व डाकखाना बिगवास (भिवानी)	13-12-93			"	"

65.	दलबीर सिंह पुत्र सोमा राम गांव व डाकखाना बरवास (भिवानी)	8-12-93.		सी/बेसिस	हुड्डताल के दो रात्र	
66.	विश्वेन्द्र पुत्र राम चन्द गांव व डाकखाना थराना (हिसार)	"		"	विभागीय कमेटी	
67.	राजपाल पुत्र जरसल गांव व डाकखाना माडी (भिवानी)	8-12-93		"	की सिफारिश	
68.	राजबीर पुत्र राम सरूप गांव व डाकखाना साम (जौद)	"		"	पर लगाया	
69.	परवीन कुमार पुत्र जिले सिंह गांव व डाकखाना कामद (जौद)	"		"	मया ।	
70.	अनिल कुमार पुत्र टेक चन्द गांव व डाकखाना खरका (रोहतक)	"		"	"	
71.	जगजीत सिंह पुत्र बीर सिंह गांव व डाकखाना खरका (भिवानी)	"		"	"	
72.	जय शम्भूत पुत्र करतार सिंह गांव व डाकखाना रावलधी (भिवानी)	"		"	"	
73.	सत्यवान पुत्र गंगा राम गांव व डाकखाना रामपुरा (भिवानी)	"		"	"	
74.	रोहतास पुत्र कन्हैयालाल गांव व डाकखाना बलाली (भिवानी)	"		"	"	
75.	कर्ण सिंह पुत्र राम किशन गांव व डाकखाना डिमोड (भिवानी)	"		"	"	
76.	नरेन्द्र कुमार पुत्र जय करण गांव व डाकखाना नगल (भिवानी)	"		"	"	
77.	साजव सिंह पुत्र चन्द्र सिंह गांव व डाकखाना हुसतगढ़ (हिसार)	"		"	"	
78.	धर्मपाल पुत्र रिखाल सिंह गांव व डाकखाना लोहाहू	"		"	"	
79.	सतपाल पुत्र खेम चन्द गांव व डाकखाना रावलधी (भिवानी)	—		"	"	
80.	रमेश कुमार पुत्र जागे राम गांव व डाकखाना दादरी	"		"	"	

म. न. व. प.

श्री बलबीर सिंह शाह

1	2	3	4	5	6	7
81.	बलबीर सिंह पुत्र दलीप सिंह गाँव व डाकखाना प्रेम नगर (भिवानी)	13-12-93			सो/विशेष	हड़ताल के दौरान विभागीय केमिटी की सिफारिश पर लगया गया।
82.	हरकपत सिंह पुत्र गफे सिंह गाँव व डाकखाना जाटी (भिवानी)	13-12-93			"	"
83.	परमतीत सिंह गाँव व डाकखाना खेड़ी बुरा भिवानी	13-12-93			"	"
84.	रणबीर सिंह पुत्र जयसाल गाँव व डाकखाना गौराया (रोहतक)	"			"	"
85.	साजन सिंह पुत्र बीर सिंह गाँव व डाकखाना बलाली (भिवानी)	"			"	"
86.	जय भगवान पुत्र बिल राम गाँव व डाकखाना बधानी (रोहतक)	"			"	"
87.	श्रीम प्रकाश पुत्र सुधेर सिंह गाँव व डाकखाना बधानी (महेन्द्रगढ़)	"			"	"
88.	कर्मबीर सिंह पुत्र देस राम गाँव व डाकखाना कटवार (भिवानी)	"			"	"
89.	सुरेन्द्र पुत्र धन सिंह गाँव व डाकखाना चिखर (भिवानी)	"			"	"
90.	लाल सिंह पुत्र सुमेर सिंह गाँव व डाकखाना कनीना (महेन्द्रगढ़)	"			"	"
91.	रुम चन्द पुत्र प्रभाती लाल गाँव व डाकखाना संगारा (रोहतक)	"			"	"
92.	सुरेश कुमार पुत्र गोखरमल गाँव व डाकखाना आदमपुर (भिवानी)	"			"	"
93.	रामपाल पुत्र रामधारी गाँव व डाकखाना चाबी (जौद)	"			"	"
94.	सत्यवान पुत्र रिसाल गाँव व डाकखाना पटवार (हिसार)	"			"	"
95.	रमेश पुत्र सतनारायण गाँव व डाकखाना नारगौद, हिसार	"			"	"
96.	रणधीर पुत्र रामसरूप गाँव व डाकखाना छरक (हिसार)	"			"	"
97.	राज सिंह पुत्र प्रीत सिंह गाँव व डाकखाना दुधवा (भिवानी)	"			"	"
98.	अशोक कुमार पुत्र सुरत सिंह गाँव व डाकखाना धमडलान (रोहतक)	"			"	"
99.	मंसा राम पुत्र नेत राम गाँव व डाकखाना पेतवास (भिवानी)	"			"	"

100.	राम फल पुत्र धर्मपाल गाँव व डाकखाना दवारका (बिधानी)	13-12-1093	सी बेसिस	हडताल के
101.	राजबीर पुत्र रामसह्य सामरू (जीद)	"	"	दौरान विभा-
102.	सीता राम पुत्र लाल चन्द गाँव व डाकखाना बिहरी कला भिवानी	15-12-93	"	गीय कमेटी
103.	सुरेश चन्द पुत्र बलबीर सिंह गाँव व डाकखाना दादरी	"	"	द्वारा की गई
104.	सतीश कुमार पुत्र चन्दनी राम गाँव व डाकखाना लोहार भिवानी	"	"	सिफारिश के
105.	सतबीर पुत्र राम कुमार गाँव व डाकखाना लोहार भिवानी	8-12-93	"	आधार पर
106.	किरोडी मल पुत्र शुभ राम गाँव व डाकखाना चंगरोद (भिवानी)	14-12-93	"	लगाया गया।
107.	मोहन चन्द पुत्र लोक राम गाँव व डाकखाना दादरी भिवानी	15-12-93	"	"
108.	ममोकि पुत्र कृष्ण गाँव व डाकखाना पटवास भिवानी	14-12-93	"	"
109.	सत प्रकाश पुत्र दुर्गा प्रशाद गाँव व डाकखाना भिवानी	15-12-93	"	"
110.	दलबीर पुत्र जीता राम पुत्र गाँव व डाकखाना गिनाऊ भिवानी	15-12-93	"	"
111.	जयबीर पुत्र बजीर सिंह गाँव व डाकखाना मोम रोहतक	15-12-93	"	"
112.	देवी प्रशाद पुत्र चन्द्र भान गाँव व डाकखाना अवीना भिवानी	15-12-93	"	"
113.	पवन कुमार पुत्र किशोरी लाल गाँव व डाकखाना मिराम भिवानी	15-12-93	"	"
114.	धर्म पाल पुत्र कुरल राम गाँव व डाकखाना लोहार	15-12-93	"	"

(8) 94

[११ अक्टूबर पांच साह]

हरियाणा विधान सभा

[९ मार्च, 1994]

क्रम संख्या	नाम और पूरा पता	नियुक्ति तिथि	नियमित/तदर्थ	वैयक्तिक वेतन भोगी	कर्मचारी श्रेणी	विवरण
1		3	4	5	6	7
		23-2-93			कर्मचारी श्रेणी	रोजगार
1.	राजपाल सिंह सुपुत्र ज्ञानी राम गाँव व डाकखाना मितापल (भिवानी)					कायसिय दादरी
2.	श्रीम प्रकाश सुपुत्र श्रीलाल गाँव व डाकखाना खेरी बूरा (भिवानी)					
3.	राम कुमार सुपुत्र थापमल गाँव व डाकखाना खड्डडी (भिवानी)					
4.	जीरा सिंह सुपुत्र किशन लाल जाटू लोहार (भिवानी)					
5.	करतार सिंह सुपुत्र दशा नन्द गाँव व डाकखाना बोरजू कलां (भिवानी)					
6.	प्रकाश सिंह सुपुत्र सुलतान सिंह गाँव व डाकखाना मंडोला (भिवानी)					
7.	सुरेश कुमार सुपुत्र हजारी सिंह गाँव व डाकखाना फर्तीया (भिवानी)					
8.	नरेश कुमार सुपुत्र राम चन्द्र गाँव व डाकखाना निमरी वाली (भिवानी)					
9.	उदयवीर सिंह सुपुत्र रामनिधर सिंह गाँव व डाकखाना धनासा (भिवानी)					
10.	राजेंद्र सिंह सुपुत्र कन्हैया सिंह गाँव व डाकखाना मन्हेड़ (भिवानी)					
11.	नीर सिंह सुपुत्र हरनारायण सिंह गाँव व डाकखाना चिस्था (भिवानी)					

1	2	3	4	5	6	7
12.	सुभाष चन्द्र सुपुत्र श्रीय प्रकाश गाँव व डाकखाना मोहरा (रोहतक)	23-2-93			कनैचुअल	रोजगार
13.	वीरेंद्र सिंह सुपुत्र सुमान राम बी 0 फारी (भिवानी)	"			"	कार्यालय
14.	भरत कुमार सुपुत्र जगत सिंह गाँव व डाकखाना दादरी	"			"	दादरी
15.	जयवीर प्रसाद सुपुत्र रोडपाल सिंह गाँव व डाकखाना इमलोटा (भिवानी)	"			"	"
16.	पतराम सुपुत्र गौरधन सिंह गाँव व डाकखाना भोजु (भिवानी)	25-6-93			"	"
17.	रामफल सुपुत्र राम सिंह गाँव व डाकखाना चरही (भिवानी)	"			"	"
18.	रामनिवास सुपुत्र मेश सिंह गाँव व डाकखाना नीरमावास	"			"	"
19.	महावीर सिंह सुपुत्र साई लाल गाँव व डाकखाना सुगरपुर (भिवानी)	"			"	"
20.	कैलास चन्द्र सुपुत्र बतवारी लाल गाँव व डाकखाना मण्डी हरिया	"			"	"
21.	सुरेश कुमार सुपुत्र मंगे राम गाँव व डाकखाना कलवास (भिवानी)	"			"	"
22.	बलवान सिंह सुपुत्र हरयाणा गाँव व डाकखाना मेहरा (भिवानी)	"			"	"
23.	सुभाष सुपुत्र धरम सिंह गाँव व डाकखाना सुहरा (रोहतक)	"			"	"
24.	राज कुमार सुपुत्र चागीर सिंह गाँव व डाकखाना चौहान मथ (सिरसा)	16-11-93			"	"
25.	सुरत सिंह सुपुत्र शोभनारायण सिंह गाँव व डाकखाना जीतापुरा (भिवानी)	26-10-93			"	"
26.	बहाबेर सिंह सुपुत्र फल सिंह गाँव व डाकखाना बुधवा	"			"	"
27.	भतपाल सिंह सुपुत्र जमलाल मुझमावा	"			"	"

(22)
CE
01

[श्री बलवीर पाल शाह]

1	2	3	4	5	6	7
28.	रमेश कुमार सुपुत्र बाल शिवत गांव मतर (सोनीपत)	29-10-93			कन्दैबचुमल	रोजगार
29.	सत्यन कुमार सुपुत्र राम सिंह डाकखाना मण्डी (हिसार)	9-11-93			"	कार्यालय
30.	सुरेश कुमार सुपुत्र राम शिवत गांव व डाकखाना सिसाला (सोनीपत)	26-10-93			"	दावरी
31.	रामधारी सुपुत्र कन्हैया लाल गांव व डाकखाना मन्हेडा (भिवानी)	7-12-93			"	"
32.	वेद प्रकाश सुपुत्र मन सिंह गांव व डाकखाना संसपुर (भिवानी)	"			"	"
33.	राजेन्द्र सिंह सुपुत्र देव राम गांव व डाकखाना भागवती	"			"	"
34.	रत्नेन्द्र कुमार सुपुत्र लक्ष्मी नारायण गांव व डाकखाना फरमाना (सोनीपत)	"			"	रोजगार कार्यालय प्रौर डिस्कॉन्टीन्यूड 31-12-93
35.	सुभाष सुपुत्र भागमल गांव व डाकखाना गासोल (भिवानी)	"			"	"
36.	जयवीर सिंह सुपुत्र जुगती राम गांव व डाकखाना खरकरी (भिवानी)	"			"	"
37.	जयवीर सिंह सुपुत्र फल सिंह गांव व डाकखाना पंडवा (भिवानी)	"			"	"
38.	पह्लाद सिंह सुपुत्र ईश्वर सिंह गांव व डाकखाना रावलधी (भिवानी)	"			"	"
39.	रणदीप सिंह सुपुत्र राजपाल सिंह गांव व डाकखाना आंग (भिवानी)	"			"	"
40.	सांनि राम सुपुत्र चन्द गांव व डाकखाना छासोला (भिवानी)	"			"	"
41.	कुलवीर सिंह सुपुत्र करण गांव व डाकखाना सिसली (भिवानी)	"			"	"

1	2	3	4	5	6	7
42.	सुखबीर सिंह सुपुत्र शेर सिंह गाँव व डाकखाना खेड़ी बुरा (भिवानी)	7-12-93		कन्दूबधुश	रोजगार	
43.	अशोक कुमार सुपुत्र चंदनी राम पोखरवास (भिवानी)	"		"	"	कार्यालय और
44.	सतबीर सुपुत्र शूभ राम गाँव व डाकखाना उमरवास (भिवानी)	"		"	"	डिसकोण्टीन्यूड
45.	सुरेश कुमार सुपुत्र टेक चन्द गाँव व डाकखाना टोडा (भिवानी)	"		"	"	31-12-93
46.	दलबीर सिंह सुपुत्र धूप सिंह गाँव व डाकखाना झमलोटा (भिवानी)	"		"	"	"
47.	रघुबीर सिंह सुपुत्र अमी चन्द गाँव व डाकखाना इमरीवाली (भिवानी)	"		"	"	"
48.	प्रदीप कुमार सुपुत्र वीरेन्द्र सिंह गाँव व डाकखाना दादरी	"		"	"	"
49.	जसबीर सिंह सुपुत्र बलबीर सिंह छातीवास (भिवानी)	"		"	"	"
50.	सज्जन सुपुत्र वेद प्रकाश गाँव व डाकखाना प्रेम नगर (भिवानी)	"		"	"	"
51.	सतबीर सिंह सुपुत्र अमृत सिंह (भिवानी)	"		"	"	"
52.	ईश्वर सिंह सुपुत्र सुधर (भिवानी)	"		"	"	"
53.	संतीश सुपुत्र गोपाल सिंह (भिवानी)	"		"	"	"
54.	जय सिंह सुपुत्र मौल चन्द गाँव व डाकखाना पाजु (लोहार)	"		"	"	एस. डी. एम. लोहार याता- यात प्रबन्धक के द्वारा नियुक्ति।

१७
१७

(8)98

श्री बलवीर पाल शाह

श्रीवाणा विधान सभा

[9 मार्च, 1994]

1	2	3	4	5	6	7
55.	ग्रहलाद सिंह सुपुत्र घासी राम गाँव व डाकखाना लोहार	7-12-93			कान्ट्रेवचुअल	एस. डी. एम.
56.	राजेन्द्र सुपुत्र कमल सिंह समासपुर (भिवानी)	"			"	लोहार/याता-
57.	मदन सिंह सुपुत्र रीछपाल सिंह गाँव व डाकखाना बहरा (लोहार)	"			"	यात प्रबन्धक
58.	धर्मवीर सुपुत्र पारस राम गाँव व डाकखाना समासपुर दादरी	"			"	के द्वारा
59.	जयमल सिंह सुपुत्र रामानन्द गाँव व डाकखाना लोहार	"			"	नियुक्ति ।
60.	राम किशन सुपुत्र हरनारायण गाँव व डाकखाना बहरली (रोहतक)	"			"	"
61.	सुभाष सुपुत्र बुद्ध राम गाँव व डाकखाना लधा (भिवानी)	"			"	"
62.	जय राम सुपुत्र मंगली राम गाँव व डाकखाना दलवास (भिवानी)	"			"	"
63.	कृष्ण कुमार सुपुत्र धर्मपाल गाँव व डाकखाना मलनेहली (रोहतक)	"			"	"
64.	केलाश चन्द सुपुत्र मजानन्द गाँव व डाकखाना सतसली महेश्वर	13-12-93			"	हड़ताल के दौरान विभागीय कमेटी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर लिया गया तथा 31-12-93 को हटा दिया गया ।

1	2	3	4	5	6	7
65.	लच्छी सिंह सुपुत्र सुहवा राम गाँव व ठाकुराना हसनपुर दादरी	13-12-93			कनट्टेसुभल	हड़ताल के दौरान
66.	बृज मोहन सुपुत्र यमोहर बाल गाँव व डाकखाना भागी (भिवानी)	"			"	विशमोध कमेटी
67.	हरनाारायण सुपुत्र अमी लाल गाँव व डा0 देवमा (भिवानी)	"			"	द्वारा की गई
68.	राजवीर सिंह सुपुत्र दिलीप सिंह गाँव व डा0 चरखी (भिवानी)	"			"	सिफारिश के
69.	सुरेश कुमार सुपुत्र-मलिक राम गाँव व डा0 मंडाली (भिवानी)	"			"	आधार पर लिया
70.	बलबीर सिंह सुपुत्र दिलीप सिंह गाँव व डा0 प्रेम नगर (भिवानी)	"			"	गया तथा
71.	राम कुमार सुपुत्र कन्हैया गाँव व डा0 राजलक्षी (भिवानी)	"			"	31-12-93 को
72.	सतवन सुपुत्र हर नारायण गाँव व डा0 भण्ड कला (भिवानी)	"			"	हटा दिया गया।
73.	सुरजभान सुपुत्र महताब सिंह गाँव व डा0 दादरी	"			"	"
74.	रणधीर सुपुत्र धर्म चन्द गाँव व डा0 गुडन (भिवानी)	"			"	"
75.	अमल सुपुत्र राधा कृष्ण गाँव व डा0 दादरी	"			"	"
76.	विश्वप्रिय सुपुत्र केहर सिंह गाँव व डा0 चंगरोह दादरी	"			"	"
77.	रवि सुपुत्र सुन्दर दास गाँव व डा0 चरखी दादरी	"			"	"
78.	अमई राम सुपुत्र अमर सिंह गाँव डा0 क्रिकोरा (भिवानी)	"			"	"
79.	अमृत सुपुत्र बलबीर सिंह गाँव व डा0 चंगरोह (भिवानी)	"			"	"
80.	रणवीर सुपुत्र जय सिंह गाँव व डा0 सुष्पगढ़ (भिवानी)	"			"	"

श्री बलवीर मान शर्मा

1	2	3	4	5	6	7
81.	सतपाल सुपुत्र राम चन्द्र गाँव व डा0 पटवास (भिवानी)	13-12-93			कानून्सुयल	हस्ताक्षर के दौरान
82.	रणवीर सुपुत्र रीछपाल गाँव व डा0 चिलर (भिवानी)				५५	विधायक कमेटी
83.	सुरेन्द्र सिंह सुपुत्र राम चन्द्र गाँव व डा0 वसोला (भिवानी)				५५	द्वारा की गई
84.	मोहन लाल सुपुत्र प्यारेलाल गाँव व डा0 दादरी (भिवानी)				५५	सिफारिश के आधार
85.	सूरजभान सुपुत्र धीना राम गाँव व डा0 मेहरा (भिवानी)				५५	पर लिया गया तथा
86.	राजवीर सुपुत्र गुलाब सिंह गाँव व डा0 बुलन्द रोहतक				५५	31-12-93 को हटा
87.	मोहिन्द्र सिंह सुपुत्र मान सिंह गाँव व डा0 झोबु कला (भिवानी)				५५	दिया गया।
88.	मोहन सिंह सुपुत्र देवी दयाल गाँव व डा0 दादरी भिवानी				५५	
89.	नरेश सुपुत्र निरंजर गाँव व डा0 झोबु कला (भिवानी)				५५	
90.	रणवीर सुपुत्र राम चन्द्र गाँव व डा0 सिसाना (सोनीपत)				५५	
91.	सतवीर सुपुत्र नरेश राम गाँव व डा0 कनीथा (रोहतक)				५५	
92.	रमेश सुपुत्र हीरा लाल गाँव व डा0 सेनीपर दादरी (भिवानी)				५५	
93.	रणधीर सुपुत्र तेज राम गाँव व डा0 पिलाना (रोहतक)				५५	
94.	बलवान सुपुत्र सोपेशो नाथ गाँव व डा0 दुधवास (रोहतक)				५५	
95.	रतन सिंह सुपुत्र मान सिंह गाँव व डा0 बलयाली (भिवानी)				५५	
96.	मान सिंह सुपुत्र रिशाल सिंह गाँव व डा0 काँकरेली (भिवानी)				५५	

दिनांक: 1-1-93 से 28-2-94 तक हरियाणा राज्ज परिवहन, चरखी दादरी से तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मशाला स्टाफ बारे सूचना

कर्मशाला में नियुक्त	नाम तथा पुरा पता	नियुक्ति तिथि	स्थाई/ नियमित/ तदर्थ	डेप्टी/ वेजिज बेसिस	सी/ रिमांडिंग	1	2	3	4	5	6	7
----------------------	------------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---

कर्मशाला स्टाफ

- रणधीर सिंह लघु मूत्र चार्ज नं० 7 चरखी दादरी फिटर
8-12-93 डेप्टी वेजिज --- हड़ताल के दौरान
विभागीय कमेटी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर रखा गया तथा दिनांक 31-12-93 से हटा दिया गया।

2. मुकेश कुमार सधुल चर्नार्दन शंभु व आ० बी० जयर, रोहताक सहायक बीरर

1	2	3	4	5	6	7
97.	नरेश सुपुत्र सागमल गाँव व डा0 जिहार (भिवानी)	13-12-93			कानूनी प्रमाण	हस्ताक्षर के दोपार विधायीय कमेटी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सिधा गयी तथा 31-12-93 को हटा दिया गया।
98.	सूबे सिंह सुपुत्र धर्मपाल गाँव व डा0 बरसाना भिवानी	"			"	"
99.	समसेर सुपुत्र मोहर सिंह गाँव व डा0 बिकारा भिवानी	"			"	"
100.	राम चन्द्र सुपुत्र दीना राम गाँव व डा0 न्यू दिल्ली	"			"	"
101.	राज कुमार सुपुत्र कपूर सिंह गाँव व डा0 सुधाना रोहतास	"			"	"
102.	सतवान सुपुत्र इन्दर सिंह दादरी गाँव पंढवा डा0 मारकवास	"			"	"
103.	महाबीर सिंह सुपुत्र शिवोदित गाँव अंजल लेहारा	"			"	"
104.	रमेश सुपुत्र गणपत गाँव व डा0 रावलधी भिवानी	"			"	"
105.	दया सुपुत्र रती दत गाँव व डा0 रावलधी भिवानी	"			"	"
106.	बलबीर सुपुत्र विजेन्द्र गाँव व डा0 बरसाना भिवानी	"			"	"
107.	प्रदीप सिंह सुपुत्र अजीत सिंह गाँव व डा0 दतौली भिवानी	"			"	"
108.	रमेश चन्द सुपुत्र सुरजमान गाँव व डा0 खरकपूनिया हिसार	"			"	"
109.	सुशील कुमार सुपुत्र सज्जन कुमार गाँव व डा0 नारनौल	"			"	"
110.	सुरेश कुमार सुपुत्र राम देव गाँव व डा0 धुराना हिसार	"			"	"
111.	शिवरा राम सुपुत्र गणपत गाँव व डा0 धुराना हिसार	"			"	"
112.	भतेह सिंह सुपुत्र गणेशी लाल गाँव व डा0 नंथल सिरौही	"			"	"
113.	सतबीर सिंह सुपुत्र रतन सिंह गाँव व डा0 विछना कुरुड भिवानी	"			"	"
114.	सतवान सुपुत्र गगवान सिंह गाँव व डा0 सोन भिवानी	"			"	"
115.	सुभाष सुपुत्र रिछपाल सिंह गाँव व डा0 बिजवाल भिवानी	"			"	"
116.	जगदीश सुपुत्र लक्ष्मी नारायण गाँव व डा0 माजरा रोहतास	"			"	"

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
		8-12-93	--	देवी वेंजिज		हस्ताक्षर के
3.	जसवंत सिंह पुत्र महा सिंह गाँव फरख नगर गुडगाँवा सहायक फिटर	"	"	"		दीरान
4.	प्रवीण कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार गाँव व डा0 बहादुरगढ़ (रोहतक) स0 विद्युतकार	"	"	"		विभागीय
5.	धान्द सिंह पुत्र सुरत सिंह गाँव व डा0 विहरोड, रोहतक स0 विद्युतकार	"	"	"		कुमेटी द्वारा
6.	सतपाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह वाई नं0 1 नजदीक रोज गाँव, चरखी बादरी स0 टायरमैन	"	"	"		की गई
7.	रमेश कुमार पुत्र राम गोपाल, बिकारा रोड, चरखी बादरी आर0	"	"	"		सिफरिश के
8.	यतीन्द्र सिंह पुत्र चंदगर्बीर सिंह, जीन्द रोड, रोहतक हैलपर	"	"	"		आधार पर
9.	सहजीव सिंह पुत्र रामेश्वर याँ0 व डा0 अधीना भिवानी हैलपर	"	"	"		रखा गया
10.	संजय पुत्र छोट राम गाँव व डा0 पाटवासा, भिवानी हैलपर	"	"	"		तथा दिनांक
11.	विजय कुमार पुत्र कृष्ण सिंह गाँव व डा0 महराना, रोहतक हैलपर	"	"	"		31-12-93
12.	जगदीश पुत्र राम नारायण गाँव व डा0 निमरी, भिवानी हैलपर	"	"	"		से हटा दिया
13.	केविक्र पुत्र राजेन्द्र वी0 एस0 बी0 बादरी हैलपर	"	"	"		गया।
14.	विक्रम पुत्र मंगल राम भाक व डा0 बसई, महेंद्रगढ़ हैलपर	"	"	"		"
15.	सुरेश खान पुत्र अशुच मनी गाँव व डा0 दुधवा भिवानी हैलपर	"	"	"		"
16.	सुकेश पुत्र दया नन्द गाँव व डा0 संग्रहेडी, रोहतक हैलपर	"	"	"		"
17.	धर्म प्रकाश पुत्र शोस दल गाँव व डा0 रावलधी, भिवानी हैलपर	"	"	"		"
18.	सिरी शम्भुल पुत्र छज्जू राम गाँव व डा0 मन्डोसा, भिवानी हैलपर	"	"	"		"

(8) 104

श्री राजीव विधान सभा

[9 मार्च, 1994]

श्री बलबीर राय झाह

1	2	3	4	5	6	7
19.	चिनोद पुत्र राधेश्याम गांव व डा0 अकोडा, रोहतास जिला, रोहतास जिला	8-12-93	हेवी वेलिज	--	हस्पताल के दीवान	
20.	रमेश कुमार पुत्र चित्त सिंह गांव व डा0 भू अरवपुर, रोहतास जिला	"	"	"	विभागीय कमेटी	
21.	कैलाश पुत्र श्रीम प्रकाश गांव व डा0 काई नं0 1 चरखी दादरी जिला	"	"	"	द्वारा की गई	
22.	सतीश कुमार पुत्र हरनाथगं गांव व डा0 झोजरी रिवाही जिला	"	"	"	सिफारिश के आधार	
23.	सुरेन्द्र पुत्र भगवान सिंह गांव व डा0 हरी नथर दादरी जिला	"	"	"	पर रखा गया तथा	
24.	श्री कृष्ण पुत्र बिश्व राम गांव व डा0 कठुरा सोनीपत जिला	"	"	"	दिनांक 31-12-93	
25.	रमजोर पुत्र राम सरूप गांव व डा0 भण्डेरी सोनीपत जिला	"	"	"	से हटा दिया गया।	
26.	अनन्द पुत्र मुखार गांव व डा0 बलाबी बिदानी जिला	"	"	"	"	
27.	सतवीर सिंह पुत्र खजान सिंह गांव व डा0 करसोडा, जीन्द जिला	"	"	"	"	
28.	जयदयाल पुत्र टेकन दास गांव व डा0 झरजर चाटी दादरी जिला	"	"	"	"	
29.	गुलाम सिंह पुत्र शेर सिंह गांव व डा0 सडीवी रोहतास जिला	"	"	"	"	
30.	धर्म वरत पुत्र श्रीम प्रकाश गांव व डा0 सगीठी रोहतास जिला	"	"	"	"	
31.	इन्द्रजीत पुत्र ध्यारे लाल गा0 व डा0 अबानिया, महेंद्रगढ़ जिला	"	"	"	"	
32.	राजेश कुमार पुत्र हजारी लाल तथा बस स्टैंड दादरी जिला	"	"	"	"	
33.	राजेश पुत्र जगदीश गा0 व डा0 रिबारा, मोहाना सोनीपत जिला	"	"	"	"	
34.	रणवीर सिंह पुत्र श्रीम सिंह गा0 व डा0 दबोडा खुर्द रोहतास जिला	"	"	"	"	
35.	बसंत पुत्र सरजोत सिंह गा0 व डा0 बरोना सोनीपत जिला	"	"	"	"	

1	2	3	4	5	6	7
36.	जय राम पुत्र पूरन चन्द बवानी छेड़ा भिवानी हैलपर	8-12-93		देवी केजज		हड़ताल में
37.	सोमबीर पुत्र रामेश्वर गा० व डा० खिन्जर, भिवानी हैलपर	"	"	"	"	दौरान
38.	रघबीर पुत्र अजदा प्रजाद गा० व डा० कलायना भिवानी हैलपर	"	"	"	"	विभागीय
39.	सतपाल सिंह पुत्र किशन सिंह गा० व डा० वास अचीना भिवानी हैलपर	"	"	"	"	कमेटी द्वारा
40.	नरेंद्र कुमार पुत्र जबर मल गा० व डा० बलापच महेन्द्रगढ़ हैलपर	"	"	"	"	की गई
41.	राम कुमार पुत्र हरी चन्द गा० व डा० भू रिवाड़ी हैलपर	"	"	"	"	सिफारिश के
42.	सतपाल पुत्र मन्कूल गा० व डा० कनेहटी भिवानी हैलपर	"	"	"	"	आधार पर
43.	विजय सिंह पुत्र कृष्ण सिंह महराना रोहतक हैलपर	"	"	"	"	रखा गया
44.	रामधन पुत्र राम गा० व डा० मटेवी, रोहतक	"	"	"	"	तथा दिनांक
45.	हेमन्त पुत्र राम किशोर, भारावास रोड़ रिवाड़ी हैलपर	"	"	"	"	31-12-93
46.	महाबीर पुत्र पिरथी सिंह गा० व डा० चौरोपुर भिवानी हैलपर	"	"	"	"	से हटा दिया
47.	जय भगवान पुत्र सूरत सिंह गा० व डा० बिहरोड रोहतक हैलपर	"	"	"	"	गया।
48.	अमिल पुत्र राम चन्द्र गा० व डा० बपरीवा, रोहतक हैलपर	"	"	"	"	"
49.	आनन्द पुत्र ज्ञानी राम गा० व डा० वास स्टैण्ड चरखी दादरी हैलपर	"	"	"	"	"
50.	जय भगवान पुत्र होंशियार सिंह गा० व डा० कनेटी भिवानी हैलपर	"	"	"	"	"
51.	सुरेश कुमार पुत्र खुशी राम गा० व डा० दुधवास भिवानी हैलपर	"	"	"	"	"
52.	राज सिंह पुत्र अरुण सिंह गा० व डा० सरली रोहतक हैलपर	"	"	"	"	"

[श्री. अशोक पांडे शास्त्री]

1	2	3	4	5	6	7
		8-12-93		डेही, जेजिज		हड़ताल के दौरान विवाहीय कर्मों द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर रखा गया तथा दिनांक 31-12-93 से हटा दिया गया।
53.	हरीश कुमार पुत्र शिव लाल गा0 व डा0 धीरेरा नारनील हैलपर			"		"
54.	अम्बा लाल पुत्र सुरखाल गा0 व डा0 धीरेरा नारनील हैलपर			"		"
55.	विजेन्द्र पुत्र चन्दवी राम गा0 व डा0 खेड़ी बुरा भिवानी हैलपर			"		"
56.	रोशन अली पुत्र सुभान अली गा0 व डा0 मोरवाला भिवानी हैलपर			"		"
57.	मुन्नेज पुत्र राम कुमार गा0 व डा0 आसर जिला रोहतक हैलपर			"		"
58.	देविन्द्र पुत्र रवबीर गा0 व डा0 सन्तल खड़ सीनीपत हैलपर			"		"
59.	रविकुमार पुत्र कमल सिंह गा0 व डा0 गुदन भिवानी हैलपर			"		"
60.	रमेश दत्त पुत्र कमल सिंह गा0 व डा0 सालावास रोहतक हैलपर			"		"
61.	वशीर पुत्र हल्दरायण गा0 व डा0 खेड़ी दौलतपुर भिवानी हैलपर			"		"
62.	कमल सिंह पुत्र फतेह सिंह गा0 व डा0 मंडौला, भिवानी			"		"
63.	श्रीम प्रकाश पुत्र रति राम गा0 व डा0 कलासी भिवानी हैलपर			"		"
64.	श्री भगवान पुत्र राम सरूप गा0 व डा0 ग्रहमदलपुर रोहतक हैलपर			"		"
65.	सेख राम पुत्र जीम सिंह गा0 व डा0 कन्नूरुप रोहतक			"		"
66.	सतबीर पुत्र मसा राम गा0 व डा0 रातिला भिवानी हैलपर			"		"
67.	संजय पुत्र सतीश नरुदीक रोज मारुन चरखी दादरी हैलपर			"		"
68.	पूरन सिंह पुत्र धूप सिंह गा0 व डा0 चरखी दादरी हैलपर			"		"

1	2	3	4	5	6	7
69.	राम निवास पुत्र चन्दा राम गाँव व डा0 मोरवाला, भिवानी हैलपर	8-12-93				हड़ताल के दौरान
70.	अतर सिंह पुत्र राम बन्द, चरखी गेट दादरी हैलपर	"			"	विभागीय कमेटी द्वारा
71.	जमालदीन पुत्र मंगल राम गाँव व डा0 सकराना भिवानी हैलपर	"			"	की गई सिफारिश के
72.	राजबीर पुत्र अमबीर गाँव व डा0 रिताली रोहतक हैलपर	"			"	आधार पर रखा गया
73.	धर्मपाल पुत्र सातू राम गाँव व डा0 कलियाणा भिवानी हैलपर	"			"	और दिनांक 31-2-93
74.	सरिन्दर पुत्र जगदीश सैनी पुरा चरखी दादरी हैलपर	"			"	से हटा दिया गया।
75.	देविन्द्र पुत्र बनवारी बाल गाँव व डा0 दाहिना हैलपर	"			"	"
76.	राज पुत्र कुरदा गाँव व डा0 भिवानी हैलपर	"			"	"
77.	अजय पुत्र राम किशन गाँव व डा0 बालमकी मोहल्ला चरखी दादरी हैलपर	"			"	"
78.	महाबीर पुत्र लट्टू राम गाँव व डा0 सन्दना रोहतक हैलपर	"			"	"
79.	अमि प्रकाश पुत्र राधेश्वर गाँव व डा0 अचीना भिवानी हैलपर	"			"	"
80.	सतपाल पुत्र लेख राम गाँव व डा0 फरतिया ताल भिवानी हैलपर	"			"	"
81.	नरेन्द्र पुत्र राम चन्द्र गाँव व डा0 गोपी जिला भिवानी चौकीदार	"			"	"
82.	अमर पाल पुत्र हरि सिंह गाँव व डा0 मिशरी भिवानी हैलपर	"			"	"
83.	महिन्द्र पुत्र हरि चन्द गाँव व डा0 डूरा खेड़ी भिवानी हैलपर	"			"	"
84.	राकेश कुमार पुत्र शाम लाल गाँव व डा0 चरखी दादरी हैलपर	"			"	"
85.	राम कुमार पुत्र जगो राम बस स्टैण्ड रोड दादरी हैलपर	"			"	"

[श्री बलबीर पाल द्वारा]

1	2	3	4	5	6	7
		8-12-93		डेवी वैजज		हड़ताल के दौरान
86.	राजपाल पुत्र शोभा राम गाँव व डाँ0 चरखी दादरी हैलपर	"	"	"	"	विभागीय
87.	रिशी पाल पुत्र गंगा राम गाँव व डाँ0 मगोट महिन्द्रगढ़ हैलपर	"	"	"	"	कमेटी द्वारा
88.	मिजेन्द्र पुत्र उमेद सिंह गाँव व डाँ0 धनी माह भिवानी हैलपर	"	"	"	"	की गृहि
89.	मोहिन्द्र सिंह पुत्र सतनारायण गाँव व डाँ0 बैडाला भिवानी हैलपर	"	"	"	"	सिफारिस के
90.	सबे सिंह पुत्र हरि सिंह गाँव व डाँ0 शोक कासनी भिवानी हैलपर	"	"	"	"	आधार पर
91.	कपूर चन्द पुत्र मूल चन्द शान्ति नगर भिवानी हैलपर	"	"	"	"	रखा गया
92.	संजय पुत्र प्रभाती गाँव व डाँ0 देवास नारनौल हैलपर	"	"	"	"	तथा दिनांक
93.	अंशु पुत्र मूल चन्द गाँव व डाँ0 देवास नारनौल हैलपर	"	"	"	"	31-12-93
94.	आनन्द पुत्र रणबीर गाँव व डाँ0 चरखी दादरी हैलपर	"	"	"	"	से हटा दिया
95.	शिव कुमार पुत्र करतार राम धानक बस्ती दादरी हैलपर	"	"	"	"	गया।
96.	रमेश पुत्र चन्दनी राम गाँव व डाँ0 गावलीसन रोहतक हैलपर	"	"	"	"	"
97.	विष्णु पुत्र सतनारायण गाँव व डाँ0 गांधी नगर दादरी हैलपर	"	"	"	"	"
98.	जय प्रकाश पुत्र रामप्रकाश गाँव व डाँ0 भारत जीन्द हैलपर	"	"	"	"	"
99.	संजय पुत्र धनबीर गाँव व डाँ0 गांधी नगर दादरी हैलपर	"	"	"	"	"
100.	सतिन्द्र पुत्र करतार सिंह गाँव व डाँ0 पन्टावास खुर्द भिवानी हैलपर	"	"	"	"	"
101.	जयपाल सिंह पुत्र रमेश गाँव व डाँ0 गाँवा सोनीपत हैलपर	"	"	"	"	"
102.	राजेश पुत्र हीरा लाल गाँव व डाँ0 बिवेक नगर दादरी हैलपर	"	"	"	"	"

	3	4	5	6	7
103. रणधीर पुत्र माई राम गां० व डा० चरखी दादरी हैलपर	8-12-93	डेवी वेजिज			हड़ताल के दौरान
104. जयवीर पुत्र रामेश्वर गां० व डा० चुलकाना सोनीपत हैलपर	"	"			विभागीय
105. सतबीर पुत्र हरधरम गां० व डा० पेटावास कलां भिवानी हैलपर	"	"			कमेटी द्वारा
106. हरजान पुत्र हरि सिंह गां० व डा० मोहन बेरी रोहतक हैलपर	"	"			की गई
107. ललित कुमार पुत्र राज सिंह कोसली रिवाड़ी हैलपर	"	"			सिफारिश के आधार पर
108. अमेन्द्र पुत्र राजेन्द्र सिंह गां० व डा० रावलधी भिवानी हैलपर	"	"			रखा गया
109. विजेन्द्र सारन किला राम गां० व डा० रावलधी चरखी दादरी हैलपर	"	"			तथा दिनांक
110. सुमेर सिंह पुत्र वीर राम गां० व डा० रावलधी चरखी दादरी हैलपर	"	"			31-12-93
111. सुबे सिंह पुत्र भजन लाल गां० व डा० नाहर रिवाड़ी हैलपर	"	"			से हटा दिया गया ।
112. रतन सिंह पुत्र कलू राम गां० व डा० अमोठ महिन्द्र गढ़ हैलपर	"	"			"
113. विजेन्द्र पुत्र चांद गां० व डा० खेड़ी दूरा दादरी हैलपर	"	"			"
114. नरिन्द्र पुत्र श्रीम प्रकाश गां० व डा० झञ्जर हैलपर	"	"			"
115. सुभाष पुत्र बुध राम गां० व डा० बेरी रोहतक रानीपर	"	"			"
116. मोहिन्द्र पुत्र कर्ण सिंह गां० व डा० जीन्व हैलपर	"	"			"
117. सुखवीर पुत्र मंगला राम भागवी भिवानी हैलपर	"	"			"
118. सुरेश कुमार पुत्र हरके राम रावलधी चरखी दादरी हैलपर	"	"			"

(8) 110

हरियाणा विधान सभा

[9 मार्च, 1994]

[श्री बलवीर मान शर्मा]

दिनांक 1-11-93 से 28-2-94 तक हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी में नियुक्त किए गये स्टाफ बारे सूचना

नियुक्त किए गए व्यक्तियों की कटेगरी	नाम तथा पूरा पता	नियुक्त तिथि	स्थाई/नियमित/तदर्थ	डेप्टी जेजिब	सी/बेसिस	रिआर्केस
-------------------------------------	------------------	--------------	--------------------	--------------	----------	----------

टिकट नं० फांथर

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री लोख राम सैनी पूरा चरखी दादरी
टी : बी : एफ :

1-11-93

डेप्टी जेजिब

स्वीपर

2. श्री धर्म मान पुत्र केशर राम, लोहाण

12-11-93

डेप्टी जेजिब

लिफिक

3. श्री राजेश पुत्र लक्ष्मी चन्द मान व डा० रावलध्री

17-2-94

तदर्थ

25697—H.V.S.—H.G.P., Chd.